राजनीति का अपराधीकरण

उन्मूलन की चुनौती

राजनीति में अपराधीकरण के प्रभाव को प्राथमिकता से समाप्त किया जाना चाहिए। हालिया वर्षों में राजनीति में अपराधीकरण का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय रहा है। ज्यादा राजनेताओं पर आपराधिक आरोप और दोषसिद्धि से सवाल उठा कि क्या चुनाव लड़ने के लिए उनकी अयोग्यता का मानक उपयुक्त है। वर्तमान बहस सर्वोच्च न्यायालय में विचारार्थ हालिया मामले से पैदा हुई है जिसमें अयोग्यता की अवधि सीमित करने की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठते हुए कहा गया कि न केवल विधिक व्याख्या, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था में अपराधों के प्रभाव की व्यापक विभीषिका पर चर्चा होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में पेश एक याचिका में कहा गया कि दोषसिद्ध राजनेताओं के आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि अयोग्यता को सीमित अवधि का रखने से उन संवैधानिक प्राविधानों का उल्लंघन होता है जिनके अनुसार अपराधियों को सत्ता के प्रयोग से रोका जाना चाहिए। वर्तमान समय में जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 8 के अंतर्गत यह प्रतिबंध रिहा होने के बाद 6 साल है। इसकी प्रतिक्रिया में केन्द्र ने वर्तमान प्राविधानों का बचाव करते हुए तर्क दिया है कि आजीवन प्रतिबंध 'अनावश्यक रूप से कठोर' होगा और इसका अर्थ संसद को एक खास तरीके से कानून बनाने का निर्देश देना होगा जो न्यायिक शक्ति की सीमा से बाहर है। सरकार के प्रति-शपथपत्र में जोर दिया गया कि अनेक दंडात्मक कानून

एक समयबद्ध ढांचे में काम करते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि अनावश्यक गंभीरता से बचने की आवश्यकता को देखते हुए प्रतिरोध संतुलित रखा जाए।

यह कानूनी दांवपेंच एक महत्वपूर्ण नीतिगत बहस की ओर संकेत करता है। क्या दोषसिद्ध राजनेताओं को चुनाव में सहभागिता में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाया गाजए या अयोग्यता का एक निश्चित कालखंड संवैधानिक तथा समानुपातिक है? सरकार का तर्क है कि अस्थाई रूप से दोषसिद्ध लोगों को बाहर रखने वाली वर्तमान व्यवस्था समानुपातिकता और तार्किकता के सिद्धान्तों का सम्मान करती है। उसके दृष्टिकोण से अयोग्यता को सीमित रखने की विधायी पसंद एक दंडात्मक व पुनर्स्थापना वाला उपाय है जो लोकतांत्रिक सहभागिता की अनुमति देता है। कानूनी बहसों से आगे राजनीतिक क्षेत्रों में आपराधिक चरित्र की बढ़ती लहर का मुद्दा बना हुआ है। राजनीति में आपराधिक तत्वों का प्रवेश न केवल लोकतांत्रिक संस्थानों की निष्ठा को खतरा पैदा करता है, बल्कि यह जनता का विश्वास भी तोड़ता है। आपराधिक व्यवहार के इतिहास वाले नेताओं के भ्रष्ट व्यवहारों में शामिल होने की संभावना अधिक होती है जो कानून के शासन को नुकसान पहुंचाते हैं। राजनीति का अपराधीकरण स्पष्ट होने के बाद से इस समस्या से निपटने के लिए कठोर उपायों का आह्वान हो रहा है। राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है जो आजीवन प्रतिबंधों के सवाल से आगे जाता है। संसद को राजनीतिक उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर पुनः विचार कर उसे संभवतः कठोर बनाने का प्रयास करना चाहिए। चाहे यह कुछ गंभीर अपराधों के दोषसिद्ध राजनेताओं पर लंबे प्रतिबंध से हो या अतिरिक्त नियंत्रणों से, विधायी सुधारों का लक्ष्य आपराधिक व्यवहार वाले लोगों को हतोत्साहित करना होना चाहिए। दोषसिद्ध लोगों के आजीवन प्रतिबंध के पक्ष या विपक्ष में मजबूत तर्क हो सकते हैं पर सभी लोग एक चीज से अवश्य सहमत हो सकते हैं कि हमें अपनी संसद या राज्य विधानसभाओं में ऐसे दोषसिद्ध व आपराधिक चरित्र वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में इसे करने का तरीका तय करना कठिन नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि यह काम कौन करेगा?

खैरातों की बढ़ती चुनौती

वर्तमान चुनौती केवल चुनावी वादे पूरे करना नहीं, बल्कि पहले से ही संकटग्रस्त राजकोषीय समीकरण ठीक करना है जो बेलगाम हो सकता है।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दो तिहाई बहुमत से चुनाव जीतने के बाद रेखा गुप्ता नीत भाजपा सरकार को अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए पैसा एकत्र करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अन्य वादों के साथ ही भाजपा ने 'महिला समृद्धि योजना'-एमएसवाई के अंतर्गत हर महिला को 2,500 रुपये महीने देने, 500 रुपये में एलपीजी सिलिंडर तथा होली और दीपावली में मुफ्त सिलिंडर देने, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने वाले एससी छात्रों को 1000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड देने, केजी से पीजी तक जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने, दिल्ली मेट्रो में छात्रों को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने, झुग्गी बस्तियों में केवल 5 रुपये में भोजन देने वाली अटल कैंटीने स्थापित करने, आयुष्मान भारत योजना लागू करने तथा वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा कवरेज देने के वादे किए हैं।

भाजपा ने पूर्व 'आप' सरकार की तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अवस्थापना द्वारा लागू अन्य सभी योजनायें जारी रखने का वादा भी किया है जिसमें मुफ्त बिजली व मुफ्त पानी भी शामिल हैं। यदि हर महिला को 2500 रुपये देने वाली महिला समृद्धि योजना-एमएसवाई पर गौर करें तो स्पष्ट होगा कि दिल्ली में 18 साल से अधिक आयु वाली लगभग 6700,000 महिलायें हैं। इनको पैसा देने पर हर साल 20,100 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की सहायता जोड़ने पर लगभग 1500,000 गर्भवती महिलाओं पर लगभग 3150 करोड़ रुपये सालाना खर्च होगा। यदि यह मान लिया जाए कि हर परिवार साल में 4 गैस सिलिंडर खर्च करता है तो होली व दीपावली पर दो मुफ्त सिलिंडरों के साथ यह खर्च लगभग प्रति परिवार 3000 रुपये सब्सिडी होगा। दिल्ली की वर्तमान जनसंख्या 330 लाख है।

यदि प्रत्येक परिवार में चार सदस्य हों तो यहां 82.5 लाख परिवार हैं। इस मद पर हर साल 2,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या में लगभग 33 लाख गरीब लोग हैं जिनमें से 11 लाख 4-25 वर्ष आयु वाले छात्र होंगे। यदि भारत में हर छात्र पर न्यूनतम 20,000 रुपये खर्च आता हो तो शहर के सभी 'जरूरतमंद छात्रों' पर हर साल 2200 करोड़ रुपये खर्च होगा। अकेले इन चार वादों का भार दिल्ली सरकार के बजट पर 27,950 करोड़ रुपये होगा। अन्य 'खैरातें' इस बोझ को कई हजार करोड़ तक पहुंचा देंगी। यह लगभग 30,000 करोड़ तक हो सकता है।

वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में दिल्ली सरकार का कुल खर्च लगभग 76,000 करोड़ है। इसमें 61,000 करोड़ राजस्व खर्च तथा 15,000 करोड़ पूंजीगत खर्च है। इसके विपरीत कुल राजस्व लगभग 58,000 करोड़ है जिससे राजस्व घाटा लगभग 3,000 करोड़ होता है। यह स्थिति चिन्ताजनक है क्योंकि दिल्ली में अतिरिक्त राजस्व सृजन की दो प्रमुख संभावनायें हैं।

राज्य राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा होने के कारण कानून-व्यवस्था, पुलिस और भूमि केन्द्र सरकार के क्षेत्र में आती है जिससे वह इन कामों पर खर्च करती है। दूसरा, दिल्ली आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र है, इसलिए वह पेट्रोल व डीजल पर वैट के साथ ज्यादा जीएसटी संग्रह कर सकता है। लेकिन कर्ज की ब्याज अदायगी पर खर्च को देखते हुए राजस्व

भाजपा ने पूर्व 'आप' सरकार की तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अवस्थापना द्वारा लागू अन्य सभी योजनायें जारी रखने का वादा भी किया है जिसमें मुफ्त बिजली व मुफ्त पानी भी शामिल हैं।

घाटा बहुत बढ़ जाता है। दिल्ली जल बोर्ड पर 70,000 करोड़ तथा दिल्ली परिवहन निगम पर 60,000 करोड़ से अधिक कर्ज है। इन कर्जों की अदायगी पूरी तरह राज्य राजधानी क्षेत्र सरकार की जिम्मेदारी है और इसे बैलेंसशीट में दिखना चाहिए। वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा लगभग 18,000 करोड़ था जो 2023-24 के मुकाबले लगभग 80 प्रतिशत अधिक था। यदि डीजेबी व डीटीसी द्वारा लिए कर्जों पर ब्याज पर गौर किया जाए तो यह साल दर साल इनके खातों में बढ़ता जा रहा है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय बचत पंड-एनएसएसएफ से 10,000 करोड़ रुपये कर्ज देने की प्रार्थना की थी।

राज्य की खराब वित्तीय स्थिति का कारण काफी सीमा तक बढ़ती खैरातें तथा विभिन्न योजनाओं के संचालन में व्याप्त अनियमितायें एवं कुप्रबंधन है। इसके साथ ही 'आप' सरकार में प्रशासन असाधारण स्तर तक पंगु हो गया था। 2024-25 में केवल मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी पर लगभग 11,000 करोड़ रुपये खर्च हुआ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक-सीएजी की रिपोर्टों के अनुसार, 2025-16 से 2021-22 तक डीटीसी का घाटा बढ़ कर 35,000 करोड़ रुपये हो गया जिसका मुख्य कारण मुफ्त बस यात्रा के साथ डीटीसी में व्याप्त कुप्रबंधन था। अब इस परिदृश्य में भाजपा द्वारा किए वादों के प्रभाव पर गौर करें।

मोदी ने गारंटी दी है कि वर्तमान योजनायें समाप्त नहीं की जाएंगी। इस प्रकार 11,000 करोड़ रुपये खर्च करने वाली मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी। इसके साथ ही दो नई नई गारंटियों पर कम से कम 30,000 करोड़ रुपये खर्च होगा। यदि अन्य सभी चीजें अपरिवर्तित रहें तो इनसे वित्त वर्ष 2024-25 में खर्च का संशोधित अनुमान 61,000 करोड़ रुपये से बढ़ कर 91,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। 58,000 करोड़ की राजस्व प्राप्ति को देखते हुए राजस्व घाटा 33,000 करोड़ हो जाएगा जो 2024-25 के बजट से 3000 करोड़ अधिक होगा।

नव-निर्वाचित सरकार ने यमुना का पानी स्वच्छ करने, स्वच्छ हवा देने, सड़कों के निर्माण व सुधार, ड्रेनेज व्यवस्थाओं को साफ करने तथा अस्पतालों व स्कूलों को सुधारने के वादे किए हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दिल्लीवासियों को अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक भौतिक व सामाजिक ढांचागत परियोजनाओं की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि यदि सौई को 2023-24 के 22,000 करोड़ पर बहाल रखा जाए तो वह काफी नहीं होगा।

इस नाकाफी स्तर के बावजूद कुल खर्च 113,000 करोड़ हो जाएगा। यदि इसमें से 58,000 करोड़ की राजस्व प्राप्ति को घटा दिया जाए तो राजकोषीय घाटा 55,000 करोड़ बचेगा। सरल भाषा में कहा जाए तो केन्द्र को कम से कम 55,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी ताकि भाजपा दिल्लीवासियों से किए अपने चुनावी वादे पूरे कर सके।

भारत में बढ़ता सौर ऊर्जा का प्रयोग

दिशा शर्मा
(लेखिका, सहायक प्रोफेसर हैं)

वर्ष 2070 तक नेट जीरो हासिल करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता इसके ऊर्जा क्षेत्र में एक नाटकीय बदलाव को उत्प्रेरित कर रही है, जिसमें सौर ऊर्जा इस परिवर्तन के प्रमुख चालक के रूप में उभर रही है। प्रचुर मात्रा में सूरज की रोशनी, तेजी से घटती प्रौद्योगिकी लागत, मजबूत सरकारी समर्थन और एक विस्तारित कुशल कार्यबल ने मिलकर सौर ऊर्जा को भारत की नवीकरणीय रणनीति के केंद्र में रखा है। जबकि देश ने सौर अपनाने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर का जश्न मनाया है, यह बहुमुखी चुनौतियों का भी सामना कर रहा है, जिसके लिए अपनी गति को बनाए रखने के लिए अभिनव नीतिगत हस्तक्षेप और रणनीतिक दूरदर्शिता की आवश्यकता है।

पिछले एक दशक में, भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। राष्ट्र ने न केवल अपने महत्वाकांक्षी नवीकरणीय लक्ष्यों को पूरा किया, बल्कि उन्हें पार कर लिया, सौर ऊर्जा अब इसके नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। 2023 से 2024 तक सौर ऊर्जा उत्पादन में 19 प्रतिशत की वृद्धि से तीव्र विस्तार स्पष्ट है, जिसमें सौर ऊर्जा संयंत्र नई नवीकरणीय क्षमता का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा बना रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भारत की भूमिका वैश्विक सौर सहयोग के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, क्योंकि इस पहल का उद्देश्य विकासशील देशों के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना है। राष्ट्रीय एजेंसियों, विशेष रूप से भारतीय सौर ऊर्जा निगम, राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत सौर परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही हैं। इन प्रभावशाली उपलब्धियों के बावजूद, पूर्ण सौर एकीकरण के मार्ग में महत्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं। एक बड़ी चुनौती राष्ट्रीय ग्रिड से सौर ऊर्जा संयंत्रों का सीमित कनेक्शन है, जिसमें वर्तमान में केवल 16 प्रतिशत क्षमता ही एकीकृत है। यह अंतर देश की अपनी विशाल सौर क्षमता का पूरी तरह से

दोहन करने की क्षमता को सीमित करता है। इसके अलावा, सौर ऊर्जा विकास में क्षेत्रीय असमानताएँ हैं। जबकि राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य इस मामले में अग्रणी हैं, कई पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र पीछे हैं, जिसके परिणामस्वरूप नवीकरणीय संसाधनों का असमान वितरण होता है। वित्तीय बाधाएं भी गंभीर चुनौतियां पेश करती हैं। यद्यपि सरकारी सब्सिडी लागत को कम करने में मदद करती है, लेकिन बड़े पैमाने पर स्थापनाओं के लिए आवश्यक उच्च प्रारंभिक पूंजी, उच्च ब्याज दरों और विलंबित भुगतानों के साथ मिलकर निजी निवेश को हतोत्साहित करती है। निर्माता प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले सौर कोशिकाओं की कमी से जूझते हैं, एक समस्या जो सस्ता घरेलू सामग्री आवश्यकताओं से जुड़ी है जो उत्पादन क्षमताओं को प्रभावित करती है। ये वित्तीय बाधाएं न केवल वर्तमान परियोजना परिनियोजन में बाधा डालती हैं बल्कि इस क्षेत्र में भविष्य के विस्तार को भी खतरे में डालती हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा आयातित घटकों पर भारत की भारी निर्भरता है। लगभग 11 गीगावॉट की घरेलू मॉड्यूल उत्पादन क्षमता होने के बावजूद, भारत अभी भी पॉलीसिलिकॉन, वेफर्स और सौर कोशिकाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर है। यह निर्भरता देश को आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है, विशेष रूप से भू-राजनीतिक तनावों और व्यापार असंतुलन के बीच, क्योंकि चीन वैश्विक सौर विनिर्माण पर हावी है सौर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को अक्सर स्थानीय समुदायों और किसानों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण विरोध, कानूनी विवाद और कुछ मामलों में हिंसक टकराव होते हैं। राजस्थान में, भूमि अधिकारों पर विवादों के कारण परियोजना रद्द हो गई है, जिससे पारदर्शी और समावेशी प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है जो स्थानीय हितों का सम्मान करती हैं और उचित मुआवजा सुनिश्चित करती हैं। इन स्थानीय चिंताओं को संबोधित करना सामुदायिक समर्थन को बढ़ावा देने और परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए, भारत को एक बहुआयामी रणनीति अपनानी चाहिए। दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए नीतिगत ढांचे को मजबूत करना महत्वपूर्ण है, साथ ही अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ाना और प्रभावी निगरानी के लिए ऊर्जा डेटा तक विश्वसनीय पहुँच सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी निवेश को आकर्षित करने के लिए जोखिम शमन उपकरण प्रदान करके कम सेवा वाले क्षेत्रों में सौर अपनाने का विस्तार कर सकती है। सौर पैनलों और प्रमुख घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से आयात निर्भरता कम होगी और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त, सौर स्थापना, रखरखाव और विनिर्माण के लिए कुशल श्रमिक पूल बनाने के लिए कार्यबल विकास में निवेश करना उद्योग के विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

मजबूत नीति समर्थन, वित्तीय नवाचार, घरेलू विनिर्माण और सामुदायिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करके, भारत अपने सौर संसाधनों की पूरी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से अनलॉक कर सकता है। निरंतर सरकारी समर्थन और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच रणनीतिक सहयोग के साथ, राष्ट्र वैश्विक सौर क्रांति का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

आप की बात

नारी का अस्तित्व व पहचान

बाबर की वंशावली पढ़ कर महसूस हुआ कि मुझे अपनी वंशावली भी मालूम होना चाहिए। गंगागौर (पंडा) से अपनी 400 वर्षों की 14 पीढ़ियों की वंशावली प्राप्त कर उसकी विभिन्न शाखाओं को याद किया।अपनी मां, दादी के बारे में पूछने पर 1-2 पीढ़ियों की जानकारी देकर उन्होंने बताया कि पुरानी जानकारी उनके खानदान के गंगागौर के पास होगी। बुआ जी आदि के बारे में भी यही जवाब मिला।कितनी बड़ी विडंबना है। नारी का हिसाब पैदा करने वाला खानदान भी नहीं रखता। ससुराल वाले भी नहीं रखते।तो नारी का खानदान कौन सा है? कोई नहीं रखानदान को आगे बढ़ाने की कष्टप्रद जिम्मेदारी केवल स्त्री निभाती है। गर्भावस्था के कष्ट और डिलीवरी के समय जान का खतरा उठाना पति के खानदान को आगे बढ़ाने के लिए। प्रजनन प्रक्रिया में पति का रोल आम तौर पर सेक्स का आनंद उठाने जितना ही होता है। लेकिन हम बहन, बेटियों के परिवार का हिसाब नहीं रखते। यो तो परायी हो जाती हैं। हम पराये परिवार से आयी अपनी मां और पत्नी का हिसाब भी नहीं रखते।फिर सभ्यता, संस्कृति की बातें करने वाले इस देश में नारी को अपना कौन समझेगा? नारी का अस्तित्व और पहचान स्थापित करने के लिए सरकार को शुरुआती तौर पर सभी सरकारी रिकॉर्ड और पहचान पत्रों में मां का नाम लिखना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

– **ललित दुबे**, रतलाम

पशु-पक्षियों की भी सोचें

वर्तमान दौर में मौसम ने करवट बदल ली और गर्मी की दस्तक हों गई। गर्मी का मौसम हाय गर्मी उफ गर्मी में इंसान से पशु पक्षियों तक गर्म हवाओं और लू और तपन से बुरा हाल होता है। गर्मियों की शुरुवात में और इस गर्मी के दौर में हमे मूक प्राणियों के जीवन सरक्षण के बारे में भी सोचना होगा। हम सभी को इन दिनों में पक्षियों के लिए घर घर सकोरे बंधकर पानी का इंतजाम पुख्ता रखना होगा। ताकि पक्षियों का आसानी से पानी प्राप्त हों जाएं। अक्सर पशु पक्षियों को पानी के आभाव में खान पान के आभाव में जीवन और मौत से रूबरू होते देखा है। हमारा कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए की मूक प्राणियों की खान पान की दुरस्त व्यवस्था होनी चाहिए। चौपाल पर चोटले पर पानी की छोटी टंकिया, पशुओं के लिए पानी पीने की कारगर व्यवस्था जरुरी है। गर्मी के मौसम में मूक प्राणियों की उचित देखभाल और खान पान की समुचित व्यवस्था पुण्य और नेक कार्य है। हालांकि नगरीय प्रशासन द्वारा और समाज सेवी संस्थाएं इन कारगर नेक कार्यों के लिए कारगर रणनीति तैयार करती है और मूर्त रूप भी देती है। परंतु गर्मी के भीषण दौर में मूक प्राणियों पशु पक्षियों की जल पानी दाना पानी की सेवा हमारी संस्कृति सभ्यता की पहचान कायम करती है। क्यों न हम सभी संकल्प लें की मूक प्राणियों की उचित देखभाल और सकोरे रखकर दाना पानी की सेवा की अविरल गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ लेते रहें।

– **योगेश जोशी**, बड़वाह, मप्र

ट्रंप-जेलेंस्की की तीखी बहस

व्हाइट हाउस स्थित ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप व यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ जो तीखी बहस हुई वह पूरी दुनिया ने देखी है। ट्रंप की फटकार व दबाव की परवाह किए बिना, जेलेंस्की ने जिस तरह से आंखों में आंखें डालकर बातें की वह तारीफ – ए – काबिल है। जेलेंस्की, अमेरिका के चौधरी ट्रंप के सामने झुके नहीं है। बातचीत व नोंक-झोंक के दौरान जेलेंस्की के निडर व साहसिक बॉडी लेंग्वेज ने सबको न केवल चौंकाया है, अपितु कायल कर दिया है। पूरा विश्व चाहता है कि रूस व यूक्रेन के बीच पिछले 3 वर्षों से चल रहा युद्ध बंद हो। लेकिन जेलेंस्की ने यूक्रेन के हितों व सम्मान को मद्देनजर रखते हुए सही कहा है कि हम दबाव में आने की बजाय हमारी सुरक्षा की गारंटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रंप के समझौते प्रस्ताव पर जेलेंस्की का यह लाजवाब जवाब ‘सम्मान बेचने से बेहतर है, मिट्टी में मिल जाना’ सबसे ज्यादा कायल करने वाला है। उनके तीखे तेवर अति आत्मविश्वासी थे। इसके विपरीत चंद दिनों पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे। लेकिन वे ट्रंप के सामने कई मुद्दों पर आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाए। वे ट्रंप की खरी-खोटी, खिसियानी बिल्ली की तरह अगले बगले झांकते हुए सुनते रहे। पूरी दुनिया ने देखा कि अड़ानी पर पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर भाव-भंगिमा ही बदल गई थी।

– **हेमा हरि उपाध्याय**, खाचरोद

मिलावट पर हो कार्रवाई

उत्तर प्रदेश सरकार ने होली से पहले ही मिलावटियों और नकली दवाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए चेतावनी दी है कि किसी भी खाद्य या दवाई में मिलावट (नकली) पायी गई तो विक्रेताओं व निर्माताओं को आर्थिक दंड के साथ ही सजा भी दी जाएगी. अच्छी बात है. मिलावटी पदार्थ व नकली दवाइयों के चलते बीमारियां बढ़ रही है. उसे दूर करना ही चाहिए. ठीक यूपी की तर्ज पर पूरे देश में मिलावटियों और नकली दवाई बनाने व बिक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो सके. इसके साथ ही एमआरपी पर भी नियंत्रण होना चाहिए. क्योंकि बहुत सी वस्तुओं के पैकेट पर ड्यौढ़ा या इससे भी अधिक मूल्य तक अंकित रहता। कुछ व्यापारी तो कुछ प्रतिशत कम पर वस्तुएं बेचते हैं और कुछ तो अधिक मूल्य अंकित पर ही वस्तुएं बेच रहे हैं. इससे रोजाना ग्राहक लुट रहे हैं. अत: खाजिब मूल्य हो पैकेट पर अंकित हों इस पर सरकार ध्यान दे ताकि अधिक मूल्य देने से आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

– **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 3 मार्च • 2025
www.rashtriyasahara.com

मानवीय निर्वाह भत्ता

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, उप्र, राजस्थान को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली-एनसीआर में प्रैप के कारण गतिविधियों के बंद होने से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को मुआवजा दें, भले ही इस पर कोई अदालती आदेश न भी हो। प्रैप यानी चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औसत वायु गुणवत्ता के आधार पर प्रदूषणरोधी उपाय। पीठ ने कहा कि प्रैप उपायों के कारण निर्माण गतिविधियां बंद करनी पड़ें तो इस अदालत द्वारा नवम्बर, 2021 को जारी निर्देशों के अनुसार प्रभावित श्रमिकों को मुआवजा दिया जाए। अदालत को बताया गया कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उप्र ने समय-समय पर मुआवजा दिया है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने निर्माण

श्रमिकों को निर्वाह भत्ता न देने पर नाराजगी जताई थी। यह निर्देश भी दिया था कि श्रमिक संघों की बैठक बुला कर उनका पंजीकरण सुनिश्चित करें। मुफ्त योजनाओं के भरोसे चुनाव जीतने वाली सरकारों पर शीर्ष अदालत सख्ती न करे तो शायद वे श्रमिकों के हित पर विचार करने से किनारा ही करती रहें। वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए प्रति वर्ष सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर में विभिन्न प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। इनसे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। खासकर दिहाड़ी मजदूरों, वाहन चालकों, कुशल-अकुशल कारीगरों को काम नहीं मिलता। दूसरे राज्यों से यहां आकर मेहनत-मशक्कत करने वालों को बेकार बैठना पड़ता है, उन्हें खाने के लाले तक पड़ जाते हैं। सरकारों को ऐसे मौकों पर दो वक्त का मुफ्त खाना मुहैया कराने को अपनी जिम्मेदारी मानना चाहिए। आज जब किसानों, महिलाओं और अन्य लोगों को सीधा बैंक खातों में धन राशि देने सरीखी योजनाओं पर सरकारें मुतमईन हैं तो उन्हें रोज कमाओ, तब खाओ वाले इन हाड़-तोड़ मेहनतकशों के विषय में विचार करना सीखना होगा। इसमें संदेह नहीं कि श्रमिक संघों का काम और पंजीकरण पूर्णतः पारदर्शी नहीं हो सकता। पर सरकार का दायित्व है कि आधार कार्ड के जरिए ऐसे प्रावधान तय करे, जिनके माध्यम से श्रमिकों का पंजीकरण अनिवार्य किया जा सके। नियोक्ताओं या अन्य माध्यमों के भरोसे सभी मजदूरों को मुआवजा प्राप्त होने में तमाम व्यवधान आने की आशंका रह जाती है। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए उचित मार्ग सुनिश्चित करने की महती आवश्यकता है। सरकारों को अपनी जिम्मेदारी का भान होना चाहिए न कि अदालती आदेश का मुंह तकते हुए उन्हें इस तरह की लापरवाही करते रहने की छूट मिलनी चाहिए।

बेहतर होते हालात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दुनिया दशकों तक भारत को अपने 'बैक ऑफिस' के रूप में देखती रही, लेकिन देश अब दुनिया के कारखाने के रूप में उभर रहा है। शनिवार को 'एनएक्सटी' सम्मेलन में 'न्यूज़एक्स वर्ल्ड' चैनल के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका 'वोकल फॉर लोकल' अभियान रंग ला रहा है क्योंकि भारतीय उत्पाद वैश्विक होते जा रहे हैं। इस क्रम में भारतीय कार्यबल एक 'विश्व शक्ति' बन गया है। दरअसल, हाल के वर्षों में भारत ने वैश्विक हालात, चाहे महामारी का समय रहा हो, अपनी आर्थिक

मजबूती का विश्वसनीय प्रदर्शन किया है। बेशक, ठोस मांग का सृजन करने वाले भारत के मध्यम वर्ग का देश को मजबूत संबल मिला है। भारतीय कृषि क्षेत्र ने भी मजबूती से अर्थव्यवस्था को समर्थन दिया। हाल के समय कुछ ऐसे क्षेत्र उभरे हैं, जिनमें भारत अपने श्रम बल को पारंगत कर सकता है। चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के साथ ही फार्मा और ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, पोत निर्माण, रक्षा उपकरण निर्माण, योग और आयुष ऐसे क्षेत्र के रूप में पहचाने जा चुके हैं, जिनमें प्रयास करके भारत आर्थिक प्रगति की राह पर तेजी से बढ़ते ले सकता है। 'वोकल फॉर लोकल' अभियान से भारत में विनिर्माण क्षेत्र के लिए माहौल बना है, और जरूरत है कि नीतिगत उपायों से इस दिशा में बढ़ा जाए। अब प्रधानमंत्री ने भारत के वैश्विक कारखाना बनने का आह्वान करके भारतीय उद्यमियों को प्रेरित करने का काम किया है कि वे स्वयं को कमतर समझ कर शिक्षकें नहीं, बल्कि चुनौतियों का अच्छे से सामना करने का मन-मानस बना लें। कुछ दिन पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक उद्योग संगठन की बैठक में इसी प्रकार की बातें कही थीं। कहा था कि सरकारी 'बैसाखियों' का मोह छोड़कर उद्योग जगत अपने भीतर इतना आत्मविश्वास पैदा करे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सके। सरकार की तरफ से नीतिगत समर्थन मुहैया कराया जा रहा है। श्रम बल को कार्यकुशल बनाने की कार्ययोजना पर काफी पहले से काम शुरू हो चुका है। उद्योग क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक्ड योजना कार्यान्वित की जा रही है। कृषि क्षेत्र प्रछन्न रोजगार के बोझ तले दबा रहा है, और इस श्रम बल को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सका तो यकीनन अर्थव्यवस्था होगी और 'विकसित भारत' का सपना साकार हो सकेगा।

परिधि/राजीव मंडल

सख्ती से ही बनेगी बात

दिल्ली चुनाव के बाद अब सरकार के एक्शन की बारी है। इसके संकेत दिखने भी लगे हैं। प्रदूषण को लेकर दिल्ली की नई-नवेली सरकार ज्यादा संजीदा और सख्त दिख रही है। 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली और 10 वर्ष पुरानी डीजल गाड़ियों को अब पेट्रोल पम्प पर ईंधन नहीं मिलेगा। सरकार का यह ताजातरीन निर्णय राजधानी को साफ-सुथरा बनाए रखने में निश्चित तौर पर मददगार होगा।

प्रदूषण के मामले में देश की राजधानी ने किस तरह की दुश्वारियां झेली हैं, यह बताने की जरूरत नहीं। दिनों-दिन हालात बदतर ही हुए हैं। जिस सहभागिता और समन्वय से इस मसले को जमींदोज किया जा सकता था, उसका पिछली सरकार में नितांत अभाव दिखा। अब रेखा गुप्ता की सरकार में उम्मीद की जानी चाहिए की इस सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे को सलीके से निपटाया जाएगा। जहां तक बात मियाद पूरी कर चुके वाहनों को सिस्टम से बाहर करने की है तो यह नियम काफी पहले से लागू है। बस उस नियम को कड़ाई से लागू करने की है। वैसे भी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके की आबोहवा बदलने के वास्ते नियमों को बिना किसी भेदभाव के अमल में लाने की कार्रवाई बेहद जरूरी है। अच्छी बात है कि पेट्रोल पम्पों पर ऐसे उपकरण लगाए जा रहे हैं जिससे पुराने वाहनों की पहचान आसान हो जाएगी।

इसी तरह प्रदूषित यमुना के दिन भी बदलने का वक्त आ गया है। इस पवित्र नदी को लेकर भी जबरदस्त राजनीति हुई। लाजिमी है, सियासत की भेंट यमुना की स्वच्छता भी चढ़ गई। अभी भी अगर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध दिखे और सही दिशा में प्रयास करे तो यमुना को चमकदार बनने में तीन वर्ष का समय लगेगा। हालांकि सरकार बनने के तुरंत बाद से ही इस दिशा में काम शुरू हो गया है। मशीनों की मदद से नदी से कूड़ा-कचरा निकाला जाने लगा है। विशेषज्ञ भी इस तथ्य से परिचित हैं कि दिल्ली को साफ-सुथरा रखने का काम काफी दुष्कर है। सिर्फ योजना बनाने से नहीं बल्कि नियमों को अमलीजामा पहनाने से ही बात बन सकती है। हां, इस रिपोर्ट से भी सरकार भिज्ञ है कि पराली से दिल्ली का दम नहीं घुटता है। असली खलनायक वाहन हैं, जो काफी मात्रा में जहरीला धुंआ वातावरण में छोड़ते हैं। कुल मिलाकर 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज भाजपा की सरकार से बेहतरी की उम्मीद है। इसलिए कि इस बार उनका बहुत कुछ दांव पर लगा है।

कब सुधरेंगी स्वास्थ्य सेवाएं

सामयिक

विनीत नारायण

आजादी के बाद नियोजित कार्यक्रम के तहत देश भर में जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे, उनमें ग्रामीण इलाकों के लिए स्वास्थ्य परियोजनाएं भी शामिल थीं। मकसद था देहात में स्वास्थ्य सेवाओं का जाल बिछना ताकि गरीबों की सेहत सुधर सके। आज पचहत्तर वर्ष बाद भी हालत यह है कि गरीब की सेहत सुधरना तो दूर स्वास्थ्य सेवाओं की ही सेहत खराब दिखाई देती है। स्वास्थ्य आदमी की बुनियादी जरूरत है। इसलिए नियोजित विकास के तहत कई प्रदेशों के देहात में सामुदायिक विकास खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई।

मूल सोच यह थी कि ग्रामीणों के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सेवाएं एकीकृत रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी जिनमें उपचार, खानपान स्वच्छता (सुरक्षित पेय जल आपूर्ति व कूड़ा-मलमूत्र निपटान), मातृ शिशु स्वास्थ्य, विद्यालय स्वास्थ्य, संक्रामक रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा व जन्म-मृत्यु आंकड़ों का संकलन जैसी सेवाएं शामिल थीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर देश भर में हजारों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हो चुके थे। मैदानी इलाकों में 5000 व पर्वतीय क्षेत्रों में 3000 की आबादी पर एक मातृ शिशु स्वास्थ्य उपकेंद्र भी खोले गए। इन उपकेंद्रों पर प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान व प्रसवोपरांत स्वास्थ्य सेवाओं के साथ प्रतिरक्षण, निर्जलीकरण उपचार के लिए घोल वितरण और खून की कमी दूर करने के लिए आयरन या फोलिक एसिड की गोलियां बांटना व अंधेपन व नेत्ररोग से बचाव के लिए विटामिन घोल बांटना शामिल था। कालांतर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में परिवर्तित होना था। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इन केंद्रों में जहां शल्य क्रिया, बाल रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ व पैथोलॉजी सेवाएं और बढ़ाई गईं वहीं प्रत्येक केंद्र में मरीजों के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या 6 से 30 कर दी गई। जाहिर है कि इस पूरे तामझाम पर जनता का अरबों रूपया खर्च हुआ। पर क्या जो कुछ कागजों पर दिखाया गया, वह जमीन पर भी हो रहा है? किसी भी गांव में जाकर असलियत जानी जा सकती है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के हाल इतने बुरे हैं कि इनमें कोई भी विशेषज्ञ नियुक्ति नहीं चाहता। प्रशिक्षण केंद्रों का स्टाफ व साज सज्जा दशकों से बेकार पड़ी है।

इस तरह ऐसे सेवा केंद्र चिकित्सकीय व स्वास्थ्य सेवाएं तो न मुहैया करा पाए, अलबत्ता नसबंदी कराने के केंद्र जरूर हो गए। 1970-71 से 1991-92 तक नसबंदी के अलावा यहां कुछ भी नहीं हुआ। बीस सूत्री कार्यक्रमों के दौरान जो फर्जी नसबंदी का दौर चला था, वह अभी थमा

नहीं है। नसबंदी की उपलब्धियां फर्जी तौर पर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती रहीं और इन्हीं 'उपलब्धियों' की एवज में नौकरशाह करोड़ों रुपये के पुरस्कार लेते रहे। इस तरह देश की बेबस जनता पर दुहरी मार पड़ी है। साल 2000 में विश्व बैंक द्वारा 'भारत जनसंख्या परियोजना' लागू हुई। योजना का मूल उद्देश्य सेवा संगठनों को मजबूत करना था। फलतः एक ओर नवनिर्माण शुरू हुआ तो दूसरी ओर नये चिकित्सकीय सेवा केंद्र भी खोले गए। कई उपकेंद्र गांव से दूर बनाए गए जो कभी इस्तेमाल नहीं हुए। ये केंद्र वीरानें में खंडहर बन चुके हैं। ऐसी योजनाओं के नाम पर तमाम ब्यूरोक्रेट-टेक्नोक्रेट अमेरिका, थाईलैंड, इंग्लैंड आदि से प्रशिक्षण लेकर आए। पर जहां ये प्रशिक्षण लेने गए थे, वहां से लौट कर नहीं आए। इसी तरह सूचना शिक्षा संचार के नाम पर प्राइवेट छपाई भी लाखों रुपये खर्च करके करवाई गई। जनचेतना फैलाने के नाम पर छपवाई गई वह स्टेशनरी कभी काम नहीं आई। न जाने कितने फार्म छपे और रद्दी में बिक गए। इस पूरे कार्यक्रम के नतीजे असंतोषजनक थे। ऐसा विश्व बैंक द्वारा कराए गए मूल्यांकन से पता चला। नतीजतन, कई प्रदेशों में 'भारत जनसंख्या परियोजना 3,4,5' नहीं दी गई। पर 'भारत जनसंख्या परियोजना-6' कई प्रदेशों को मिल गई जिसका मूल उद्देश्य श्रम संसाधनों का विकास करना था। इस योजना के तहत ऊपर के अधिकारी तो विदेशी सैरगाहों में घूम आए पर नीचे का स्टाफ भी पीछे नहीं रहा। वे भी अहमदाबाद, गांधीधाम, मुंबई में सैर-सपाटे करता रहा। फिर आया सूचना क्रांति का दौर। स्वास्थ्य सेवा भले ही लोगों को न मिले पर सूचना के आधुनिक उपकरणों को खरीदनें में संकोच क्यों किया जाए? सूचना नहीं तो कमीशन की आमदनी तो होगी ही। इसलिए प्रौद्योगिकी से तालमेल बिठाए रखने के नाम पर करोड़ों रुपये के सैकड़ों कंप्यूटर व बाकी का साजोसामान खरीद लिया गया। जनजागरण के नाम पर हजारों टीवी व अन्य उपकरण भी खरीदे गए जो अधिकारियों के बंगलों की शोभा बढ़ा रहे हैं।

परिवार प्रशिक्षण के लिए पहले जहां थोड़े बहुक्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र थे, उनके स्थान पर दुगुने केंद्र खोल दिए गए जिनका भवन निर्माण हुआ, साज-सज्जा के लिए भारी खरीदारियां की गईं पर योजनाबद्ध तरीके से कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ। दरअसल तो इन केंद्रों में पहुंच वालों की बारातें टिकती रहती हैं। यकीन जनता के पैसे से खरीदे गए कंप्यूटर व साज सज्जा अपनी मूल पैकिंग में रखे-रखे ही आउटडेटेड हो गए। बढ़-चढ़ कर दावा किया जाता है कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हुई खोजों व लोष के कारण उपचार के क्षेत्र में अत्यधिक सुविधाएं आज सुलभ हैं। हृदय के साथ ही अन्य अंगों का प्रत्यारोपण भी आज हो रहा है परंतु वैश्वीकरण व उदारीकरण के फलस्वरूप इस दिशा में जितना भी विकास हुआ व सेवा सुविधाएं उपलब्ध हुईं उन तक पहुंच समाज के धनाढ्य व नव-धनाढ्य वर्ग की ही है।

आम जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है। तमाम बड़े सरकारी संस्थान या प्राइवेट अस्पताल या क्लीनिक की सेवाएं विशिष्ट वर्ग के लिए ही सुरक्षित व सुलभ हैं। दूसरी त्रासदी यह है कि कुछ गिने-चुने विशेषज्ञ जिनकी सेवाएं सामान्य जनता को सरकारी अस्पतालों में मिल भी जाती थीं, वह भी अब इन्हीं पांच सितारा अस्पतालों में चले गए हैं। स्वास्थ्य के मामले में भारत का पारंपरिक ज्ञान और लोक जीवन का अनुभव इतना समृद्ध है कि हमें बड़े ढांचों, बड़े अस्पतालों और विदेशी अनुदानों की जरूरत नहीं है, जरूरत है अपनी क्षमता और अपने संसाधनों के सही इस्तेमाल की।

(लेखक में विचार निजी हैं)

2000 में विश्व बैंक द्वारा 'भारत जनसंख्या परियोजना' लागू हुई। इसके तहत नये चिकित्सतीय सेवा केंद्र खोले गए। कई उपकेंद्र गांव से दूर बनाए गए जो कभी इस्तेमाल नहीं हुए। ये केंद्र वीरानें में खंडहर बन चुके हैं। योजनाओं के नाम पर तमाम ब्यूरोक्रेट-टेक्नोक्रेट अमेरिका, थाईलैंड, इंग्लैंड आदि से प्रशिक्षण लेकर आए। पर जहां ये प्रशिक्षण लेने गए थे, वे लौट कर नहीं आए। इसी तरह जनचेतना फैलाने के नाम पर छपवाई गई स्टेशनरी भी कभी काम नहीं आई

बढ़ रहा है **अरंडी** तेल का निर्यात

- भारत का अरंडी तेल निर्यात बढ़ रहा है, और 2030 तक इसके 2.5 अरब डॉलर पर पहुंचने की आकलन है
- कास्टरोयल कैस्टर एसोसिएशन (एससीए) के मुताबिक, वैश्विक बाजार में अरंडी के तेल की भारी मांग है। इसका उपयोग पेंट, वार्निश, रेजिन और प्लास्टिक्स सहित कई औद्योगिक अनुप्रयोगों में होता है
- अरंडी के प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात और राजस्थान हैं। प्रमुख निर्यात गंतव्यों में चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, व. कोरिया, नीदरलैंड, मेक्सिको, रूस, सिंगापुर आदि देश शामिल हैं

(मीडिया इनपुट्स)

स्वच्छ मन — श्रीराम शर्मा आचार्य

नैतिक आदर्शों का पालन शरीर के प्रतिबंधों पर नहीं, मन की उच्च स्थिति पर निर्भर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के षडरिपु जो मन में छिपे बैठे रहते हैं, समय-समय पर हिंसा, झूठ, पाखंड, स्वार्थ, बेईमानी, विश्वासघाती, दहेज,कन्या विक्रय, वर विक्रय, जुआ, चोरी आदि सामाजिक बुराइयों के रूप में फूट पड़ते हैं। नाना प्रकार के दुष्कर्म यद्यपि अलग-अलग प्रकार के दीख पड़ते हैं पर उनका मूल एक ही है 'मन की मलिनता'। जिस प्रकार पेट खराब होने से नाना प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार मन मलिन होने पर हमारे वैयक्तिक और आंतरिक जीवन में नाना प्रकार के कुकर्म बन पड़ते हैं। जिस प्रकार रोगों के कारण शरीर की पीड़ा उठानी पड़ती है, उसी प्रकार मन की मलिनता से हमारा सारा बौद्धिक संस्थान-विचार क्षेत्र औंधा हो जाता है और कार्यशैली ऐसी ओछी बन पड़ती है कि पग-पग पर असफलता, चिंता, त्रास, शोक, विक्षोभ के अवसर उपस्थित होने लगते हैं। अव्यवस्थित मनोभूमि को लेकर संसार में न तो कोई महान बना है और न किसी ने अपने जीवन को सफल बनाया है। उसके लिए क्लेश-कलह, शोक-संताप, दैन्य-दारिद्र ही सुनिश्चित हैं, न्यूनाधिक मात्रा में वे ही उसे मिलने हैं, वे ही मिलते भी रहते हैं। स्मरण रखने योग्य बात, गांठ बांध लेने योग्य तथ्य यह है कि मनुष्य के जीवन में एकमात्र विभूति उसका मन है। इस मन को यदि संभाला-साधा न जाएगा, सुथारा-सुसंस्कृत न किया जाएगा तो यह नीचे बहने वाले जल की तरह स्वभावतः पतनोन्मुख होगा। मन को स्वच्छ बनाना-हमारे चेतन जगत का सबसे बड़ा पुरुषार्थ-की ओर जिनके कदम बढ़े हैं, उनके लिए लौकिक सफलताओं और समृद्धियों का द्वार प्रशस्त होता है और उन्हीं ने आत्मिक लक्ष्य प्राप्त किया है। मन पर चढ़े मल आवरण जब हट जाते हैं, तो अपनी आत्मा में ही परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते हैं। मन की मलिनता के रहते प्रत्येक दुख और अशुभ मनुष्य के आगे-पीछे ही घूमता रहेगा। देवत्व तो मानसिक स्वस्थता का ही दूसरा नाम है जिसने अपना अन्तःकरण स्वच्छ कर लिया उसने इसी देह में देवत्व का लाभ उठाया है, और इसी धरती पर स्वर्ग का आनंद लिया है। 'स्वच्छ मन' जीवन की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।

रीडर्स मेल

पाकिस्तान की जगहंसाई

आज पाकिस्तान की हालत देख कर हंसी आ रही है। चैंपियंस ट्राफी का मेजबान बन जो किरकिरी पाकिस्तान ने अपनी करवाई है, शायद ही कभी किसी भी खेल में किसी देश की हुई होगी। पाकिस्तान अपने पहले दोनों मैच न्यूजीलैंड और भारत से बुरी तरह हार चैंपियंस ट्राफी से बाहर हो चुका है। आखिरी मैच बंगलादेश से था जो बारिश की भेंट चढ़ गया। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट जगत का पहला देश बन गया है जो अपनी मेजबानी वाले आईसीसी टूर्नामेंट का एक भी मैच नहीं जीत पाया हो। चलो, खेल में हार-जीत तो चलती रहती है परंतु मजे की बात यह है कि पाकिस्तान 29 साल बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है यानी दो सेमीफाइनल में से एक पाकिस्तान के बाहर खेला जाना तय है, और भारत सेमी जीत जाता है तो असली मजाक बनेगा पाकिस्तानी मेजबानी का, क्योंकि फिर टूर्नामेंट का फाइनल मैच दूसरे देश में खेला जाएगा। स्टोरी में एक और ट्विस्ट यह होगा कि प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह भी मेजबान देश पाकिस्तान में नहीं, बल्कि दुबई में होगा।

नीरज शर्मा 'भरथल', ई मेल से

महिला सशक्तिकरण की हकीकत

भारतीय महिलाएं शिक्षा, व्यवसाय, तकनीकी, राजनीति, खेल, विज्ञान एवं हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। वे अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक आगे बढ़ रही हैं। राजनीति और प्रशासन में अपनी योग्यता साबित कर रही हैं। लेकिन भारतीय महिलाओं का अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र 18 प्रतिशत है। क्या सिर्फ इतना ही काफी है? पुरुषों की अपेक्षा जीडीपी में महिलाओं योगदान इतना कम क्यों है? महिला सशक्तिकरण को हकीकत के तौर पर देखा जाए तो आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं शिक्षा से वंचित हैं, और रीति-रिवाज एवं रूढ़िवादी सोच के भार तले अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को तरस रही हैं। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सरकार और समाज को मिल कर काम करना होगा। महिलाओं को सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करना होगा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। वैसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों को बदलने के लिए प्रयास करना होगा जो महिला विकास में बाधक बनते हैं। लैंगिक असमानता को दूर करने का भी प्रयास करना होगा।

अम्बिका कुशवाहा 'अम्बी', पटना

आसान नहीं है केजरीवाल की राह

कैग रिपोर्ट पीएसी को भेजने के बाद दिल्ली विधानसभा में हंगामा खड़ा हो गया। शराब नीति के कारण 'आप' सरकार की लुटिया डुबी है। कोढ़ में खाज यह कि उस शराब से दिल्लीवासियों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ा। अब अरविंद केजरीवाल की राह आसान नहीं है क्योंकि जिन नीति-नियमों से केजरीवाल ने जनता को भरोसा दिलाया था, उन केजरीवाल की अब पोल खुल चुकी है। विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी इस पर चिंता जताई है। घाटे की रकम की आपूर्ति बजट के दौरान की जा सकती है। केजरीवाल ने ईमानदारी का चोला पहन कर उस चेहरे के नकाब को भी हटा दिया है, जिस पर मतदाता भरोसा करते थे। इतिहास गवाह है कि राजनीति के मंच पर जिन नेताओं ने नौका खराब की, वे आज भी प्रायश्चित करते दिखाई दे रहे हैं। मतदाता कुर्सी देना जानता है, तो कुर्सी खींचना भी उसे बहुत अच्छे से आता है।

कांतिलाल मांडोत, ई मेल से
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

वन्य जीव दिवस — प्रो. आर.के. जैन

वन्य जीव बिना अधूरी है सृष्टि

वन्य जीव धरती के अनुपम रत्न हैं, प्रकृति की उस अनमोल थाती के प्रतीक जो विशाल सृष्टि का संतुलन थामे हुए हैं। ये प्राणी केवल जीवित जैविक वैविध्य की शोभा ही नहीं, अपितु मानव जीवन के उद्गम, उसकी यात्रा और उसके संपूर्ण अस्तित्व के आधार हैं। धरती की धड़कन हैं, जो अपने मूक स्वर से प्रकृति का सौंदर्य जीवंत करते हैं। किंतु, आधुनिकता की उन्मत्त दौड़, शहरीकरण की अनियंत्रित विस्तार, शिकार की क्रूर लिप्सा और प्रदूषण का विषैला जाल इन ननहें जीवन-संगियों को लील रहा है। अनेक प्रजातियां समय के अंधेरे गर्भ में समा चुकी हैं, और असंख्य अन्य अपने अंतिम प्राण गिन रही हैं।

यह दारुण दृश्य हमें झकझोरता है कि वन्य जीवों की रक्षा अब केवल कर्त्तव्य नहीं, अपितु हमारी आत्मा का आह्वान और मानवता का परम धर्म बन चुका है। इसी संकल्प को बल देने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को 'विश्व वन्य जीव दिवस' मनाया जाता है। बीस दिसम्बर, 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को 'विश्व वन्य जीव दिवस' के रूप में अंकित किया। इसका मूल ध्येय है-वन्य जीवों और वनस्पतियों के प्रति वैश्विक चेतना का प्रज्ज्वलन और उनके प्राकृतिक अधिवासों को अक्षुण्ण रखने की पुकार। वर्ष 2025 की थीम 'प्रकृति और संरक्षण का उत्सव' मंत्र-सी है, जो प्रकृति की अलौकिक छटा, अनंत गहराई और संरक्षण की अनिवार्यता को उजागर करती है। हमें जागरूक करती है कि हम प्रकृति के साथ एक लय में बंधें, उसके संगीत को सुनें और उसकी रक्षा के लिए संकल्प लें। वन्य जीवों को बचाने का मार्ग बहुआयामी और दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण होना चाहिए। प्रथम, वनों की अंधी लूट और शहरीकरण की अनियंत्रित आंधी पर लगाम कसनी होगी। वृक्षों का अनवरत संहार वन्य जीवों से उनका घर छीन रहा है, साथ ही जलवायु परिवर्तन के भयावह दानव को भी पोषित कर रहा है। वृक्षारोपण का महायज्ञ शुरू करना होगा-हर पौधा एक आशा है, हर वन एक जीवन।

वृक्ष धरती की श्वास हैं, और इनके बिना जीवन का संगीत मंद पड़ जाएगा। दूसरा, प्रदूषण का यह दुष्चक्र तोड़ना होगा। प्लास्टिक का अंबार और कचरे का जहर जल-थल के प्राणियों को निगल रहा है। समुद्र के गर्भ में मछलियां, कछुए और जलपक्षी इस कृत्रिम आपदा के शिकार बन रहे

हैं। प्लास्टिक को जीवन से निर्वासित करना होगा-पुनर्चक्रण का संकल्प और प्रकृति के प्रति संयम ही इस संकट का कवच बन सकता है। स्वच्छता का यह अभियान हर प्राणी के लिए जीवन का उपहार होगा। तीसरा, स्थानीय जनमानस को वन्य जीवों की महिमा का बोध कराना होगा। जब हर दिल समझेगा कि ये प्राणी केवल जंगल के आभूषण ही नहीं, बल्कि जीवन-चक्र के संनाद हैं, तब हर हाथ संरक्षण के लिए उठेगा। शिक्षण संस्थाएं, संगठन और सरकारें मिल कर ज्ञान का ऐसा दीप जलाएं जो अज्ञान के अंधेरे को चीर दे। विशेषकर बनवासी और ग्रामीण समुदाय इनके संरक्षक बन सकते हैं, उनके भीतर प्रकृति का प्रेम पहले से ही बस्ता है, बस उसे जागृत करना है। चौथा, अवैध शिकार और वन्य जीव व्यापार का यह काला कारोबार कुचलना होगा। दुर्लभ प्राणियों की निर्मम हत्या केवल लालच की भेंट चढ़ रही है-बाघ का गर्वीला रुदन, गैंडे का शांत चिंतन और हाथी की विशालता व्यापार की भट्टी में जल रही है। कठोर कानून और उनका दृढ़ पालन ही इस संकट का अंत कर सकता है। हर नागरिक को संरक्षक बनना होगा-हर आंख सतर्कता की प्रहरी और हर कदम न्याय का संवाहक। पांचवां, संरक्षण संगठनों को शक्ति देनी होगी। ये संगठन वन्य जीवों के लिए योद्धा हैं, जो दिन-रात उनके जीवन की रक्षा में संलग्न हैं। हमारा सहयोग-चाहे धन से, समय से या संदेश के प्रसार से-इनके संकल्प को पंख देगा। ये संगठन अकेले नहीं लड़ सकते; यह युद्ध हम सबका है। आज जब वन्य जीवों पर संकट की काली छाया गहरा रही है, तब यह हमारा परम कर्त्तव्य है कि हम संरक्षण का संकल्प करें।

'प्रकृति और संरक्षण का उत्सव' एक थीम नहीं, बल्कि एक स्वर है-प्रकृति का स्वर, जो हमें जीवन का मोल समझाता है। यदि आज हम चुप रहे तो भावी पीढ़ियां इस सौंदर्य को कोसेंगी। उनकी आंखों से यह विविधता छिन जाएगी, और हम इतिहास के गुनहगार कहलाएंगे। समय आ गया है उठ खड़े होने का-ऐसा संकल्प करें जो वन्य जीवों में जीवन, प्रकृति में सम्मान और धरती में समृद्धि का संदेश फैलाए। विश्व वन्य जीव दिवस एक तिथि भर नहीं है, बल्कि एक पुकार है-एक जागृति जो हमें याद दिलाती है कि यह धरती तभी तक जीवंत है, जब तक हर प्राणी का स्वर इसमें गूंजता रहता है। हर सांस, हर कदम, और हर प्रयास इस अद्भुत संगीत को अनंत बनाए। चलिए, हम एकजुट होकर धरती के हर प्राणी के लिए एक शाश्वत और सजीव संगीत की रचना करें, जो युगों-युगों तक गूंजता रहे।

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक-विजय कावरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, कारखां तल, लक्ष्मी टावर, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित।
• समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रमेश मिश्र*।
मुख्यालय - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23362369, 23352371, 23362372, फैक्स - 23352370, मुख्यालय - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 196
आर.एन.आई. सं. 53469/93, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*मुद्रण अंक में प्रकाशित समाचार सामग्री के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मसलों के लिए उत्तरदायी

अमर उजाला
प्रवाह
नई दिल्ली ■ सोमवार, 3 मार्च 2025
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

दिखने से मत आंकिए, एक गरीब कोट के नीचे एक अमीर दिल भी हो सकता है। - जोशुआ बेकर

ट्रंप युद्धों को खत्म करने के एवज में चतुर सौदागर की तरह शांति की कीमत भी चाहते हैं। तमाम अन्य राष्ट्राध्यक्षों के बाद अब यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ उनकी तीखी वार्ता यह समझने की जरूरत दर्शाती है कि बेवजह आक्रामकता और टकराव के बजाय संयमित संवाद से ही स्थायी समाधान निकलते हैं।

ट्रंप सौदागर

अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच शांति वार्ता की संभावनाओं पर केंद्रित बैठक ने जिस तरह से तीखा मोड़ लिया, उससे दोनों देशों के बीच मतभेद तो उजागर हुए ही हैं, वैश्विक राजनीति में भी हलचल मच गई है। दरअसल, ट्रंप के इस आरोप कि यूक्रेनी राष्ट्रपति शांति स्थापित करने के प्रति गंभीर नहीं हैं, के जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि वे सुरक्षा की गारंटी के साथ युद्ध विराम चाहते हैं, क्योंकि कहने को तो युद्ध विराम पहले भी हुए हैं। बातचीत में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस बार कहानी ने जो मोड़ लिया, वह काफी चौंकाने वाला है। दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच कूटनीतिक वार्ता का इस तरह मीडिया के सामने होने का दृश्य निस्संदेह चौंकाने वाला है। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली वह शैली है, जिसमें यह संवाद हुआ। चाहे जॉर्डन के किंग हो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर हों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सभी के साथ अपनी शैली में ही बात की, लेकिन तब स्थितियां इतनी नहीं बिगड़ीं। मैक्रों और स्टार्मर ने तो यूक्रेन के प्रति ट्रंप के दृष्टिकोण से असहमति भी दिखाई। लेकिन इन सभी नेताओं ने यह परिपक्वता दिखाई, जो वर्तमान परिस्थितियों में सबसे जरूरी थी। जेलेंस्की के लिए यह बैठक बेहद अहम थी, लेकिन अब, भले ही यूरोपीय देश उनके समर्थन में खड़े हों, उनकी आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। तय यह है कि यूरोपीय देशों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वे अपने दम पर कोई बड़ा सैन्य अभियान चला पाएं। इसके अलावा, यूरोप के देशों के हथियारों की आपूर्ति भी अमेरिका पर निर्भर करती है। दूसरी ओर, यह छिपा नहीं है कि ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने के एजेंडे पर चल रहे हैं। पर यह भी सच है कि उनकी आक्रामक शैली, अन्य देशों के प्रमुखों के साथ हुए कठोर संवाद और अप्रत्याशित राजनीतिक फैसलों से वैश्विक राजनीति में अनिश्चितता ही आई है। जैसा वह अपने चुनावी अभियानों से कहते आ रहे हैं, इसमें संदेह नहीं कि वे युद्धों को खत्म कर शांति की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन के खनिजों और गाजा पर कब्जे में रुचि दिखाई है, उससे जाहिर है कि वह चतुर सौदागर की तरह इस शांति की कीमत भी वसूलना चाहते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल शक्ति प्रदर्शन या व्यापार के नियमों से नहीं चलते, इनमें संयम और संवाद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। व्यर्थ की आक्रामकता और टकराव अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कभी भी स्थायी समाधान नहीं लाते।

नई पहचान ढूंढती यह पुरानी दुनिया

कोविड के दौरान सबने माना कि दुनिया बम की आइडेंटिटी से नहीं, बल्कि वैक्सीन यानी जीवन की आइडेंटिटी से ही बच सकती है। यही परमानेंट आइडेंटिटी शायद दुनिया को बचा सके और शांति ही इस दुनिया की पहचान बने। फिर सूट या पहनावे के सवाल किसी राष्ट्राध्यक्ष से नहीं पूछे जाएंगे।

नंदितेश निलय
स्तंभकार, लेखक एवं रचनात्मक प्रशिक्षक

क्या इस दुनिया में हम हमेशा किसी खास पहचान के इर्द-गिर्द अपने कन्वर्सेशंस और रिलेशंस को ढूंढते रहते हैं? अपने पहनावे, अपनी सामरिक या किसी अन्य शक्ति के सहारे? जैसे कि किसी राष्ट्राध्यक्ष से यह पूछ लिया जाए, 'आपके पास पहनने को सूट नहीं है, क्या?' यह कुछ अजीबो-गरीब नहीं लगता? चर्चिल का महात्मा गांधी के पहनावे पर टिप्पणी जैसा, जब गांधी को 'नेकेड फकीर' कहा गया! क्या दुनिया में हर देश, हर इन्सान कोई आइडेंटिटी नहीं ढूंढ रहा? क्या हम एक कंपलसरी आइडेंटिटी में बंधते तो नहीं जा रहे हैं? ऐसी पहचान, जो जाति, धर्म से शुरू होकर पद, धन या फिर मैनेजर, लीडर आदि न जाने कितने पड़ाव लेती है। और फिर न जाने कितने सामाजिक, धार्मिक, संस्थागत और यहां तक कि देश से लेकर, पारिवारिक विषेद का भी कारण बन जाती है। और अब तो यह आइडेंटिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के फॉलोअर्स और लाइक्स से भी प्रभावित होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रील बनाने की हवस में हम उस कंपलसरी आइडेंटिटी की ओर बढ़ रहे हैं, जो दुर्भाग्यवश हमारी परमानेंट आइडेंटिटी भी बनती जा रही है।

शीत युद्ध ने सबसे शक्तिशाली आइडेंटिटी को जन्म दिया, जिसका मुकाबला करने के लिए सामरिक शक्ति बढ़ाने की होड़ लग गई। अमेरिका और रूस ने मानो संसार को नीर्थ पोल और साउथ पोल की तरह एक आइडेंटिटी दी, और इस कंपलसरी आइडेंटिटी से जुड़ने के लिए विश्व के अन्य देशों को किसी एक पाले के साथ जाना था। तमाम मुल्क हथियार खरीदने और कुछेक बेचने के दायरे में आ रहे थे। और यह नई बनती कंपलसरी आइडेंटिटी न्यूक्लियर बम की अधिकाधिक संख्या को सब कुछ मान बैठी और दुनिया को खत्म करने के लिए तमाम देश न्यूक्लियर बम का परीक्षण करने लगे कि कौन किसको कितना डरा सकता है, सबसे शक्तिशाली कौन है। यह उस कंपलसरी आइडेंटिटी का हिस्सा बना।

चलिए, थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। भारत जब स्वतंत्रता संग्राम कर रहा था, तो जैसे कंपलसरी आइडेंटिटी छोड़ने की होड़ लगी हुई थी। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी आर दास, अरुणा आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस आदि ने अपनी लॉ की प्रैक्टिस, कोई पद या नौकरी छोड़ दी। लेकिन आजादी के बाद, तो मानो कंपलसरी आइडेंटिटी ने सभी को घेर लिया। विभाजन की त्रासदी में एक भौगोलिक लकीर एक पूरी कौम को दूसरी कौम से अलग कर रही थी। लाखों लोग समुदाय या धर्म के नाम पर मारे जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात इस कंपलसरी आइडेंटिटी ने उस कंटेस्टिंग कन्वर्सेशन को जन्म दिया, जिसने 'मेरा और तुम्हारा' या 'कौन और क्या' के विभेद की बहुत बड़ी खाई खड़ी कर दी, जो तबसे और गहरी होती जा रही है।

आज डिजिटल और एआई की दुनिया ने हमें ऐसी कुछेक दस कंपनियों से परिचित कराया, जिन्होंने तकनीक की शक्ति और समझ को कंपलसरी आइडेंटिटी बना दिया। जो देश जितना डिजिटल बनता रहा, वह उन दस कंपनियों से किसी न किसी रूप से जुड़ा रहा। यहां तक कि एलन मस्क का अमेरिकी चुनाव के दौरान और फिर मंत्रिमंडल से जुड़ना बता रहा है कि इस दशक ने एक ऐसी कंपलसरी आइडेंटिटी पैदा की, जिससे बचना करीब-करीब असंभव हो गया है।

नतीजतन मनुष्य के सामाजिक संवाद की जिम्मेदारी भी इन कंपलसरी आइडेंटिटी ने ले ली। सब कुछ मानो इन्हीं के इर्द-गिर्द हो रहा है। देश के स्तर पर सामरिक और डिजिटल शक्ति राष्ट्र के आपसी संबंधों और संप्रेषण का रास्ता बना रही है, तो समाज के स्तर पर पहले से ही जाति, धर्म, पद और धन से उभरी आइडेंटिटी इन संबंधों और संप्रेषणों को प्रभावित करती आ रही है। लखनऊ में कोई अपने पूरे परिवार को मारकर सोशल मीडिया पर फेमस होना चाह रहा है, तो कोई गरीब किसी अमीर की गाड़ी के नीचे आ जाए, तो कोई हो-हल्ला नहीं होता। और न ही किसी छोटे देश पर किसी बड़े देश के आक्रमण का।

भारत को भी एक स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान मिली और 15 अगस्त, 1947 को नियति से मुलाकात हुई। हालांकि, भारत ने महात्मा गांधी को खो दिया और नियति से यह मुलाकात स्वतंत्रता पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि सांप्रदायिकता दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, जबकि गांधी ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था, 'अगर दिल्ली खो गई, तो भारत खो जाएगा।' लेकिन सांप्रदायिकता की कंपलसरी आइडेंटिटी ने थोड़ी देर के लिए मानो मनुष्यता की आइडेंटिटी को ग्रहण लगा दिया। मानो एल्डस हक्सले कह रहे हों, 'शायद यह दुनिया किसी दूसरे ग्रह का नरक है।' महात्मा गांधी स्वतंत्रता के बाद देश में उभर रहे ऊर्ध्वाधर मतभेदों के बारे में चिंतित थे। नंदन नीलेकणी ने अपनी पुस्तक, *इमेजिनिंग इंडिया* में उन ऊर्ध्वाधर मुद्दों और क्षैतिज विषयों के बारे में बात की है।

क्या एक विकसित समाज या 2047 का भारत अपने लोगों को उस कंपलसरी आइडेंटिटी से निकाल पाएगा? क्या हम ऐसे सामाजिक और संस्थागत संप्रेषण को गढ़ पाएंगे, जो कंपलसरी आइडेंटिटी को स्थायी बनने से रोके और उस वास्तविक स्थायी पहचान का निर्माण कर सके, जिसमें मनुष्य बनना और मानवता ही सबकुछ होता है। फिल्म दीवार में एक भाई ने अपनी आइडेंटिटी बंगला, गाड़ी और पैसे में ढूंढी, तो दूसरे भाई ने अपनी मां में। आइए, हम मनुष्य बने रहने के जीवन मूल्यों की ही आइडेंटिटी चुनें और अपने संबंध और संप्रेषण उसी के इर्द-गिर्द चुनें। शायद श्रीराम, गुरु नानक, पैगंबर, जीसस, कबीर, रैदास, रूमी भी यही चाहते थे कि मनुष्य अपनी पहचान मनुष्यता में ही ढूंढे। महात्मा ने तो उन सारी कंपलसरी आइडेंटिटी को ही मिटा दिया था। और वायरस जब हारा, तो सिर्फ मनुष्य होने की उस परमानेंट आइडेंटिटी से ही।

कोविड के दौरान सबने माना कि दुनिया बम की आइडेंटिटी से नहीं, बल्कि वैक्सीन यानी जीवन की आइडेंटिटी से ही बच सकती है। यही परमानेंट आइडेंटिटी शायद दुनिया को बचा सके और शांति ही इस दुनिया की पहचान बने। फिर सूट या पहनावे के सवाल किसी राष्ट्राध्यक्ष से नहीं पूछे जाएंगे। न कोई 'चर्चिल उस महात्मा गांधी को 'नेकेड फकीर' कह पाएगा और न हो कोई एलीट विवेकानंद के पहनावे पर सवाल खड़े कर पाएगा। कोविड ने तो मनुष्य के चेहरे पर ही मास्क लगाकर इन्सानियत की परमानेंट आइडेंटिटी गढ़ दी। और विवेकानंद ने 'सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका' से पूरे विश्व की।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

स्वामी चिदानंद सरस्वती

उन सभी इच्छाओं को त्याग दें, जो आपके मानवीय अस्तित्व के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति में बाधक हैं, आपका ध्यान हटाती हैं तथा स्थूल मानवीय चेतना व संसार-बद्धता के नियम से बांधे रखती हैं।

इच्छाओं को सही दिशा दें जीवन सुखमय बनाएं

इच्छा शांति की शत्रु है। इच्छा मानव-चित्त की सबसे बड़ी समस्या है। इच्छा सर्वाधिक कष्टदायी है। यह वस्तुतः एक महान शत्रु है। अतः समस्त इच्छाओं को त्याग दें। कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मरण-शक्ति भ्रमित हो जाती है। अतः बार-बार कहा गया है कि निष्काम बनें। हमें इन उपदेशों का महत्व और निहितार्थ साधधानीपूर्वक समझना होगा। सभी इच्छाओं को त्याग दें। यहां इच्छाओं का अर्थ है- वे सभी इच्छाएं, जो आपके मानवीय अस्तित्व के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति में बाधक हैं, जो आपका ध्यान हटाती हैं और आपको स्थूल मानवीय चेतना अथवा संसार-बद्धता के नियम से बांधे रखती हैं। ऐसी इच्छाओं को कठोरता से त्यागना होगा। दैनिक आत्म-निरीक्षण, अंतरविश्लेषण तथा गहन छानबीन से उन्हें पहचानना होगा। उनको नष्ट करके उनसे मुक्ति पानी होगी। किंतु, इस प्रकार की इच्छाओं पर विजयी होने की प्रक्रिया का एक भाग यह है कि आप दिव्यता को प्राप्त करने की एक महान तथा अन्य इच्छाओं को अपने में समाहित कर लेने वाली पूर्णतय प्राप्त करें। आत्म-साक्षात्कार की प्रबल इच्छा तथा अपने जीवन को उदात्त, आदर्श और पवित्र बनाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न करें। दिव्यता, परमात्मा, आत्मज्ञान, मोक्ष और पूर्णता के मार्ग की समस्त बाधाओं पर विजय पाने का यह एक प्रारंभिक बिंदु है। वेदांत का कथन है कि इस जागृति की ओर, जीवनमुक्ति की ओर ले चलने वाली इस प्रक्रिया की प्रथम अवस्था शुभेच्छा है। यदि आपके पैर में कांटा चुभ जाता है, तो पैर का कष्ट दूर करने का एकमात्र उपाय यह है कि उतना ही अथवा उससे भी अधिक तीक्ष्ण कोई कांटा अथवा सुई लेकर उससे पांव में चुभे हुए कांटे को निकाल दिया जाए। यह इच्छा (शुभेच्छा) दिव्य इच्छा है। यह मानव के हृदय में भगवान का प्रकटीकरण है। यह जीवात्मा के अभिलाषी हृदय में परमात्मा की कृपा की अभिव्यक्ति है। यह अपरिहार्य है। यह शुभेच्छा पलट कर सही दिशा की ओर दृढ़ निश्चय के साथ की जाने वाली गति है। मनुष्यता से दिव्यता की ओर, ससीम-परिसीमित जीवन की ओर। और इसकी पुष्टि करने के लिए भगवान कृष्ण हमें बताते हैं- 'मैं उन लोगों के अंदर इसी प्रकार की उन्नत और मोक्षदायिनी शुभेच्छा बनकर निवास करता हूँ, जो धर्म से प्रतिबद्ध हैं, जो धर्म-च्युत नहीं होते और जो धर्म-प्रेमी हैं। धर्म आधार है। एक कामना के रूप में उनके जीवन में आकर मैं उन्हें धर्म से भी परे समस्त धर्मों के मूल स्रोत, स्वयं परमात्मा, स्वयं ब्रह्माडीय सत्ता तक ले जाता हूं।' यह पावन इच्छा, महान ललक, लालसा, उत्कंठा, प्रचंड उत्सुकता, मुमुक्षुत्व हमारे भीतर विद्यमान उन शुभ तथा मांगलिक तत्वों का तात्कालिक कारण हैं, जो हमें अच्छे संस्कारों, आध्यात्मिक संस्कारों-वासनाओं के रूप में गत जीवन से प्राप्त होते हैं। जब तक शुभेच्छा का यह प्रज्वालक स्फुलिंग इन प्रसुप्त संस्कारों तथा वासनाओं के संपर्क में नहीं आता, तब तक ये संस्कार निष्क्रिय रहते हैं।

जीवन जीना सीखें

सूत्र

जीवन जीना सीखें। इसे व्यर्थ गंवाएं नहीं। स्वयं से कहें कि मुझे यह मखमल के डिब्बे में एक अत्यंत मूल्यवान रत्न के समान जीवन का उपहार मिला है। बाहरी चीजों में भटकर स्वयं को बर्बाद न करें। अपनी इच्छाओं को सही दिशा दें और जीवन को सुखमय बनाएं। जीवन का धर्म यही है कि हमें अपने कर्तव्यपथ पर बिना रुके हमेशा चलते रहना है।

दूसरा पहलू

जमानी बांध बनने के चलते विश्वविख्यात आस्था का केंद्र हैड़ाखान का मंदिर डूब क्षेत्र में आ रहा है।

दशकों पुराना मंदिर, चमत्कार और विस्थापन

उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के प्रवेश द्वार हल्द्वानी से 40 किलोमीटर दूर दो पहाड़ों के बीच कलकल बहती गौला नदी (जिसे गौतमी गंगा और गार्गी भी कहा जाता है) के दोनों किनारों पर रहस्यमयी बाबा हैड़ाखान का मंदिर व सदियों पुरानी गुफा है। यहां न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। गुफा से ठीक छह किलोमीटर ऊपर छोटा कैलाश का प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन हल्द्वानी की प्यास बुझाने और उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर के साथ ही उत्तर प्रदेश के रामपुर व बरेली जिले में सिंचाई के लिए अथ यहां जमरानी बांध बनाने का काम शुरू हो चुका है। बांध बनने से अगले पांच साल में यह मंदिर भी बांध के डूब क्षेत्र में आ जाएगा। ऐसे में मंदिर को दूसरी जगह नए स्वरूप में स्थापित करने के लिए जमीन की तलाश शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने मंदिर समिति को मुआवजा दे दिया है।

बांध निर्माण का कार्य जून 2029 से पहले पूरा होना है। नदी तल से बाबा हैड़ाखान मंदिर की ऊंचाई करीब 25 मीटर है, जबकि बांध के लिए 40 से 45 मीटर तक जलभराव किया जाना है। ऐसे में मंदिर, बाबा का समाधि स्थल, अस्पताल और गेस्ट हाउस सब डूब जाएंगे। आसपास प्रभावित परिवारों को न्यूनतम 40 लाख रुपये की रकम मुआवजे में मिल रही है। नतीजतन प्रभावित परिवारों की रातों-रात किस्मत बदल रही है।

बांध बनने के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार में भी प्राथमिकता मिलेगी। कुमाऊं का यह इलाका नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। बांध बनने के बाद सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश को 57 फीसदी और उत्तराखंड को 43 प्रतिशत पानी मिलना है। मान्यता है कि बाबा हैड़ाखान 1860 में यहां आए थे। वह 1922 तक रहे। इलाके में उनके चमत्कार की कई कथाएं प्रचलित हैं। उन्होंने ही यहां शिवलिंग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि 1922 में काली और गौरी नदी में उन्होंने जलसमाधि ले ली थी। उन्होंने भक्तों से कहा था कि मैं फिर हैड़ाखान आऊंगा। 1970 में अचानक एक संत का हैड़ाखान में आगमन हुआ। उसने 45 दिन तक गुफा में बिना अन्न के तपस्या की, फिर भक्तों को दर्शन दिए। उन्होंने ही मंदिर का निर्माण करवाया था। इतिहासकार प्रो. अजय रावत के अनुसार, अवतारी बाबा के यहां आने के बाद इस स्थल का नाम हैड़ाखंडी बाबा पड़ा। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि इस स्थल पर पहले बड़ी संख्या में हरड़ के पेड़ थे। प्रचुर मात्रा में यहां हरड़ होने से इसे हैड़ाखान यानी हरड़ की खान (भंडार) कहा जाने लगा। राजस्व अभिलेखों में हैड़ाखान गांव का नाम मुक्तड़िया है।

प्रेम प्रताप सिंह

बांध बनने के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार में भी प्राथमिकता मिलेगी। कुमाऊं का यह इलाका नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। बांध बनने के बाद सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश को 57 फीसदी और उत्तराखंड को 43 प्रतिशत पानी मिलना है। मान्यता है कि बाबा हैड़ाखान 1860 में यहां आए थे। वह 1922 तक रहे। इलाके में उनके चमत्कार की कई कथाएं प्रचलित हैं। उन्होंने ही यहां शिवलिंग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि 1922 में काली और गौरी नदी में उन्होंने जलसमाधि ले ली थी। उन्होंने भक्तों से कहा था कि मैं फिर हैड़ाखान आऊंगा। 1970 में अचानक एक संत का हैड़ाखान में आगमन हुआ। उसने 45 दिन तक गुफा में बिना अन्न के तपस्या की, फिर भक्तों को दर्शन दिए। उन्होंने ही मंदिर का निर्माण करवाया था।

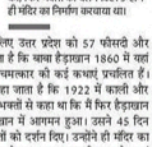

1970 में अचानक एक संत का हैड़ाखान में आगमन हुआ। उसने 45 दिन तक गुफा में बिना अन्न के तपस्या की, फिर भक्तों को दर्शन दिए। उन्होंने ही मंदिर का निर्माण करवाया था।

आंकड़े

विश्व धरोहर स्थल

यूनेस्को की सूची में 168 देशों के 1,223 स्मारक विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं, जिनमें से सर्वाधिक स्थल इटली के हैं।

इटली	60
चीन	59
जर्मनी	54
फ्रांस	53
स्पेन	50

भारत 43 विश्व धरोहर के साथ छठे स्थान पर है। | स्रोत :UNESCO

वासुदेवानंद जी से उनके सहाध्यायी ने वैदिक मंत्र का सामर्थ्य प्रकट करने को कहा। वासुदेवानंद जी ने एक वैदिक मंत्र पढ़ा, तो सहाध्यायी आश्चर्यचकित हो गए।

मंत्र की शक्ति

अंतर्यात्रा
संकलित

वासुदेवानंद सरस्वती जी का जन्म महाराष्ट्र के माणगांव में हुआ था। पिता का नाम गणेश भट्ट और माता का रमाबाई था। वासुदेवानंद सरस्वती जी बचपन से ही बड़े तीव्र बुद्धि के थे। जो किसी भी पाठ दो-चार बार सुन लेते, वह उन्हें कंठस्थ हो जाता था। उन्होंने अपने दादा से लिखना-पढ़ना सीखा था। इसके बाद गुरु वेदमूर्ति विष्णुभट्ट जी और भास्करभट्ट औलकर के पास बैठकर वेदाध्ययन किया। वासुदेवानंद सरस्वती जी ने कई दिनों तक भगवान श्रीदत्तात्रेय की उपासना की। इस प्रखर तप के परिणामस्वरूप उन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हुईं।

एक बार वासुदेवानंद जी और उनके सहाध्यायी वैदिक मंत्रों की अद्भुत सामर्थ्य की चर्चा करते हुए भगवान श्रीगणेश को पुष्पांजलि चढ़ाने जा रहे थे। रास्ते में एक सांप दिखा। सहाध्यायियों ने कहा कि यह अच्छा अवसर है, किसी वैदिक मंत्र की सामर्थ्य प्रकट करने का। वासुदेवानंद जी ने सांप के चारों ओर थोड़ी मिट्टी डाल दी और एक वैदिक मंत्र पढ़ा। वह सांप उसी छोटे से मिट्टी के घेरे में ही रहा। दूसरे दिन वासुदेवानंद जी अपने साथियों के साथ उसी स्थान पर गए, तो वह सांप उसी घेरे में था। वासुदेवानंद जी ने मिट्टी की रेखा मिटा दी, तो सांप वहां से बाहर निकल गया। उनके सहाध्यायी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वासुदेवानंद जी बोले, हम तो केवल भगवान के दास हैं, असली कर्ता-धर्ता वही हैं। कहते हैं कि भगवान श्रीदत्तात्रेय जी से वासुदेवानंद सरस्वती जी की रहस्यमय बातचीत हुआ करती थी।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 01 नवंबर, 1965

पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम का निरंतर उल्लंघन

पाकद्वारायुद्धविराम का निरंतर उलंघन
काश्मीरका क्षेत्र में गोलाबारी

पाकिस्तान युद्ध विराम की अब कोई परवाह नहीं कर रहा हैं। उसने पिछले दिन अकेले जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में मोर्टार तोपों से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों के सामने भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की।

खुद की तलाश में

अप्रतिम कलाकार हिम्मत शाह का जाना कला के एक युग का अवसान है। वह कहते थे कि खुद को तलाशने के लिए सबको छोड़ना पड़ेगा।

राजेश कुमार व्यास — **स्मृति-शेष**

हिम्मत शाह का विछोह दिक्-काल को संबोधित कला के एक युग का अवसान है। वह इस दौर के अप्रतिम कलाकार थे। अंतिम समय तक सक्रिय रहकर कलाओं में रमने वाले, जोड़-तोड़ से दूर अपने एकाकीपन में निरंतर सृजन में सुख तलाशने वाले। कुछ दिन पहले ही उनके घर पर मिलकर दूरदर्शन के कला-केंद्रित अपने कार्यक्रम 'संवाद' में बातचीत के लिए उन्हें राजी किया था। मार्च के प्रथम सप्ताह में बातचीत के लिए वह तैयार हो गए थे। लेकिन उससे पहले ही वह अनंत यात्रा पर निकल गए। उनके भीतर एक मासूम बच्चा था, जो अब भी बहुत कुछ और करना चाहता था। इस दुनिया को सर्वथा अलग ढंग से देखना और दिखाना चाहता था। हमेशा ऐसा कुछ रचने को आतुर, जो अब तक किसी ने नहीं रचा है। हिम्मत शाह के भीतर की यह अकुलाहट ही उनके सृजन का मूल थी।

हिम्मत शाह जड़ता से परे थे। उनकी कलाकृतियों में भी कहीं कोई एकरसता नहीं थी। मूर्तिशिल्प, रेखांकन रचते हुए वह अपने आपको भी भूल जाते थे।...और कुछ सृजित हो जाता, तो इतना उत्साहित हो उठते कि बच्चे की तरह उछल-कूद करने लगते थे। एक दफा रविवार को कुमार गंधर्व की सीढ़ी लेकर घर आ गए। हमने साथ सुनी। सुनते-सुनते अचक हिम्मत जी नृत्य करने लगे थे। वह ऐसे ही थे, मन से निर्मल, निश्छल।

कोविड के समय जब पूरा विश्व थमा हुआ था, वह रेखांकन कर रहे थे। तब करीब तीन सौ कलाकृतियां उन्होंने सिरजीं। बाद में नई दिल्ली स्थित कीकानेर हाउस और आर्ट मैग्नम में 'अंडर द मास्क' शृंखला से चयनित कुछ कलाकृतियां प्रदर्शित हुईं। रघु राय उनके करीबी रहे हैं। उन्होंने हिम्मत शाह की कला-साधना में रत विविध छवियों को 'थ्रू द लेंस ऑफ हिम्मत शाह' में संजोया है।

(जन्म-1933, मृत्यु-2025)

हिम्मत शाह दस वर्ष की वय में सृजन से जुड़ गए थे। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, बांबे और फिर एमएस यूनिवर्सिटी, बड़ौदा में उन्होंने अध्ययन किया। वर्ष 1967 में फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर दो साल के लिए पेरिस गए। वहां एटलियर 17 में प्रिंटमेकर एसडब्ल्यू हेटर और कृष्णा रेड्डी के अधीन अध्ययन किया। हमारे यहां इन्स्टालेशन का दौर बहुत बाद में आया, पर हिम्मत शाह ने पचास के दशक में ही 'बर्न पेपर कोलाज' जैसा महती इन्स्टालेशन किया था। राजस्थान के गांव-गांव घूमकर उन्होंने 'हेमेज टू राजस्थान' शृंखला सिरजी, जिसे बाद में इब्राहिम अल्का जी ने खरीद लिया था।

उन्होंने वास्तुशिल्प, भित्ति चित्र, टेराकोटा और कांस्य में अमूर्त्त का इतिहास रचा। मिट्टी की मूर्तियों में उभार, बल और रस्सी जैसे रूपाकारों में उनका टेक्सचर विरल है। अपने सृजन के काम आने वाले, मूर्ति तराशने, आकार देने और ढालने के लिए कई तरह के हाथ के औजारों, ब्रश और उपकरणों को उन्होंने खुद ईजाद किया। सीमेंट और कंक्रीट में भित्ति चित्र भी उन्होंने निरंतर सिरजे।

वह हुए 1890 के संस्थापक सदस्य थे। इस समूह की प्रदर्शनी पर मेक्सिको के तत्कालीन राजदूत और सुप्रसिद्ध कवि ऑक्टेवियो पाज ने 'सरउंडेड बाय इनफिनिटी' शीर्षक से लिखा कि यह प्रदर्शनी नए समय का एक संकेत है। एक ऐसा समय, जो आलोचना के साथ-साथ सृजन का भी होगा। इन कलाकारों के साथ कुछ अनमोल पैदा हो रहा है।' यह समूह तो बाद में बिखर गया, परंतु हिम्मत शाह ने रचना-कर्म उम्र पर्यंत जारी रखा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा और उस समय के महती कवियों ने उनकी सिरजी कलाकृतियों पर अपने दौर में कविताएं लिखीं।

एक सप्ताह पहले जब उनका फोन आया, तो भविष्य की ढेर सारी योजनाओं के बारे में बताते हुए वह कहने लगे, 'स्टील आई एम यंग।' बहुत उत्साह से उन्होंने नए शिल्प पर किए जा रहे अपने कार्य को दिखाया था। इसे उन्होंने शीर्षक दिया-'एंटाग्नर द सिटी'। मिट्टी में सिरजे सूक्ष्म शिल्प। मुझे लगा, यह शहरों में बसते और दूसरे शहरों की गाथा है। यह किसी एक माध्यम से कभी बंधकर नहीं रहे। वह सदा कुछ नए की तलाश करते रहे। उनकी सामग्री, माध्यम और तकनीक निरंतर बदलती रही है। उनकी पेंटिंग, उनके मूर्तिशिल्प में बेहद सूक्ष्म अनुभव प्रतीतियां हैं। भले इन्हें कला की किसी खास परंपरा और शैली के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, परंतु हिम्मत शाह ने जो किया, वह कला में सर्वथा अद्भुत, अपूर्व रहा है। खंड-खंड अखंड उन्होंने रचा।

कला के इस दौर में जब रचनात्मकता के स्तर पर नए कुछ की जगह सब जगह एक-सा मूर्त-अमूर्त काम दिखाई दे रहा है, हिम्मत शाह के आश्रयहीन रूपाकार कला में अभी बची अनंत रचनात्मकता के प्रति विश्वास दिलाते हैं। उनसे अंतिम बार जब मिला, तो अपनी स्मृतियों के संसार में ले जाते हुए वह बार-बार कह रहे थे, 'मैंने सबको छोड़ दिया। अपने को ढूंढने के लिए सबको छोड़ना पड़ेगा।' हिम्मत जी ने हमें छोड़ दिया। अपने आपको तलाशने इतनी दूर चले गए कि हम उनसे बहुत पीछे छूट गए हैं। विदा, हिम्मत जी। नमन!

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 13

नया द्विपक्षीय दौर

गत सप्ताह बिज़नेस स्टैंडर्ड के आयोजन 'मंथन' में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द्विपक्षीय वार्ताओं और समझौतों के बढ़ते महत्त्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीयता 'एक तरह से समाप्त' हो गई है। उन्होंने दलील दी कि ऐसी स्थिति में भारत को व्यापार, निवेश और रणनीतिक रिश्तों में ऐसे द्विपक्षीय समझौतों पर जोर देना होगा। भारत के हितों को प्राथमिकता देने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों को इस तरह से आकार देना आवश्यक होगा। सीतारमण की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब यूरोपीय आयोग भारत की यात्रा पर है और जिसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के लिए आकांक्षी समयसीमा की घोषणा की गई। ऐसे मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना उस 'रीसेट' के लिए आवश्यक होगा जिसके बारे में सीतारमण ने बात की।

सीतारमण ने वैश्विक शासन के बदलते परिदृश्य पर जो दृष्टिकोण पेश किया है उसका समर्थन करने वाले कई प्रमाण मौजूद हैं। बीते दशक में दुनिया के कई हिस्सों में लोकलुभावन आंदोलनों ने उस आधार को चुनौती दी है जिस पर वैश्वीकरण को अंजाम दिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था भी इसी पर आधारित थी। यहां तक कि बहुपक्षीयता में बहुत अधिक भरोसा करने वाले लोग भी विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संस्थानों में चीन के भारी प्रभाव को देखकर निराश हैं। विश्व व्यापार संगठन भी चीन द्वारा अपने निर्यात क्षेत्रों को दी जा रही छिपी हुई सब्सिडी पर लगाम लगा पाने में विफल रहा। ऐसे में वह विश्व व्यापार के लिए समान क्षेत्र नहीं निर्मित कर पाया। परंतु बहुपक्षीय व्यवस्था को सबसे बड़ा झटका इसके मुख्य गारंटर और प्रायोजक अमेरिका के पाला बदलने से लगा।

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के अधीन अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते से दूरी बना ली है। अमेरिका द्वारा विश्व व्यापार संगठन की अपील संस्था में कर्मचारी रखने से इनकार करने के बाद यह संस्था नख दंत विहीन हो गई है। विभिन्न देशों पर मनमाना टैरिफ लागू करने से विश्व व्यापार के बुनियादी सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा है। यह अच्छी खबर नहीं है। बहुपक्षीय संस्थानों और नियम आधारित व्यवस्था यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में बड़े देश, छोटे देशों के साथ किस तरह का आचरण करते हैं इस पर कुछ नियंत्रण कायम किया जा सके। समान द्विपक्षीय समझौते बहुत कम होते हैं क्योंकि वार्ता में शामिल पक्षों का आकार और उनकी ताकत भी ध्यान में रखी जाती है। भारत विश्व व्यापार में बहुत मजबूत उपस्थिति नहीं रखता है और वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि जहां वह अपनी प्राथमिकता को द्विपक्षीय ढंग से आरोपित कर सके।

बहरहाल, उसे वर्तमान वैश्विक हालात से निपटने के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी करनी चाहिए। उसे उन बहुलवादी संस्थानों में शामिल होना चाहिए जो बहुपक्षीय संस्थानों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए विश्व व्यापार संस्था की स्वैच्छिक बहुपक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था। इसे द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए उपलब्ध संसाधनों और क्षमताओं का भी विस्तार करने की आवश्यकता है। सरकार को अंतरविभागीय प्रक्रिया गठित करनी चाहिए ताकि अन्य मंत्रालयों या विभागों से संबंधित मुद्दों या वित्तियों पर राजनयिकों या आर्थिक संबंधों के अफसरशाहों द्वारा ऐसी वार्ताओं में चर्चा किए जाने पर होने वाली देरी को कम से कम किया जा सके। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उसे यह चिन्हित करना होगा कि उसे ऐसी द्विपक्षीय चर्चाओं में अधिक से अधिक लक्षित रियायत देनी होगी। अब वह समय नहीं रहा जब बहुपक्षीय स्तर पर आसानी से मुद्दों को वीटो कर दिया जाता था। अब यह आवश्यक है कि रियायत दी जाएं और बहुपक्षीय स्तर पर मोलभाव किया जाए।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इस नए द्विपक्षीय दौर में भारत की प्रतिबद्धता के लिए परीक्षण का विषय होगा। इस समझौते को लेकर उच्च स्तरीय राजनीतिक ऊर्जा और ध्यान स्वागतयोग्य है और इस वर्ष के अंत तक इसे पूरा करने के वादे पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास होना चाहिए।

अफसरशाही पर विपरीत है ट्रंप और मोदी का नजरिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप बागी तेवर वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें अफसरशाही में बुराई ही नजर आती है मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अफसरशाह निरंतरता और बदलाव दोनों के प्रतीक हैं

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने जिस समय ईलॉन मस्क को देश की अफसरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसने के अधिकार दे दिए हैं लगभग उसी समय भारत में मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी है।

इनमें से पहला यानी ट्रंप का कदम सरकार का आकार कम करने और खर्च घटाने का नाटकीय तथा अराजकता भरा प्रयास है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कदम सरकार के आकार और वेतन पर होने वाले खर्च में विस्तार से जुड़ा है, जो 2029 के चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। दोनों नेताओं ने कमोबेश एक से वादे पर चुनाव जीता। हम मोदी की बात को तरजीह देंगे: न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन।

प्रशासन और उस पर आने वाले खर्च पर दोनों नेताओं के नजरिये में अंतर का इससे बेहतर उदाहरण शायद नहीं मिलेगा। ट्रंप एक तरह से बागी हैं, जो अफसरशाहों को बहुत बुरा मानते हैं। चुनाव में कोई जीते, कोई हारे, अफसरशाह अपना कार्यकाल आराम से पूरा करते हैं। वे नियम कायदों के हिसाब से देश चलाते हैं या उसे चलाने में सरकार की मदद करते हैं।

परिभाषा के हिसाब से उन्हें किसी तरह की राजनीतिक या वैचारिक वफादारी नहीं करनी होती। इस व्यवस्था में तो वफादारी को बहुत खराब माना जाता है। ट्रंप की नजर में यह अश्लीलता है। उनके लिए यह अनिर्वाचित लोगों की सत्ता है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसीलिए वह इसे समाप्त करना चाहते हैं।

मोदी के लिए अफसरशाह निरंतरता, बदलाव और वफादारी के प्रतिनिधि हैं। हमारे प्रशासनिक ढांचे और कर्मी जब तक मौजूदा राजनीति के हिसाब से ढले रहते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। यही वजह है कि हमने मोदी युग में यूपीएससी से चुने गए अफसरशाहों को सबसे ज्यादा अधिकारसंपन्न बनते देखा।

आठवें वेतन आयोग का गठन तो रूपक भर है। मोदी के कार्यकाल में केंद्र सरकार का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। उदाहरण के लिए लुटियन की दिल्ली से बाहर की नई दिल्ली देखें तो आपको विकास के साथ ढेरों नए 'भवन' बने दिख जाएंगे।

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

ट्रंप के अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के नवनियुक्त प्रमुख वॉशिंगटन में बना एफबीआई मुख्यालय नष्ट करने और उसके कर्मचारियों की छंटनी करने और उनको अल्बामा जैसे स्थानों पर भेजने की बातें कहकर चर्चा में आ गए हैं। यह तो वही बात हुई कि भारत में सीबीआई के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में कुशीनगर या सोनभद्र अथवा तेलंगाना में मेडक या आंध्र प्रदेश में कुरनूल भेज दिया जाए।

राष्ट्रीय जांच एजेसी (एनआईए) को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के निकट सीजीओ कॉम्प्लेक्स में नया और विशाल भवन मिला है। दिल्ली पुलिस को लुटियंस दिल्ली के मध्य एक शानदार नया ठिकाना मिल गया है। आईटीओ चौराहे के पास बना उसका पुराना मुख्यालय अब भी उसके पास है। प्रवर्तन निदेशालय की अपनी इमारत है, जो खान मार्केट के निकट लोक नायक भवन के उसके पुराने कार्यालय के मुकाबले कई गुना बेहतर है। सच कहूं तो लोक नायक भवन कतई सरकारी झुग्गी है। किसी भी इंसान को वहां काम करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि लुटियन की दिल्ली का पुनर्निर्माण करते समय इसे ढहा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन संस्थानों में शामिल है जिन्हें आईएनए मार्केट के पीछे बारापुला फ्लाईओवर के निकट बनी लाल बलुआ पत्थर वाली इमारत में एक पूरी मीनार मिल गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को कॉपरनिकस मार्ग पर अपना भवन मिल गया है और देश भर में उसके क्षेत्रीय केंद्र फैले हुए हैं। कोई भी यह नहीं पूछता कि इनमें बैठे अफसरशाहों का प्रदर्शन कामकाज के पैमाने पर कैसा है या ये संस्थाएं कैसा काम कर रही हैं। इसी तरह केंद्र और राज्यों में भी सभी अपेक्षाकृत नए संस्थानों (जरूरी नहीं कि मोदी सरकार ने ही बनाए हों) का खूब विस्तार हुआ है और उन्हें खूब भवन मिले हैं। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्यों के सूचना आयोग, राज्यों के लोकपाल और लोकायुक्त तथा कई पंचाट इसमें शामिल हैं।

अब सरकार के कारोबार पर नजर डालें तो एयर इंडिया की बिक्री को छोड़कर लगभग सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम न केवल मोदी सरकार के अधीन बने रहे बल्कि उनमें जनता के पैसे से भारी-भरकम नया निवेश भी किया गया। इस वर्ष के बजट में 14.7 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार के उपक्रमों में निवेश के लिए आवंटित किए गए हैं। राहुल गांधी अक्सर आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार सरकारी उपक्रमों को 'बेच' रही है। उधर मोदी खुद कई बार बता चुके हैं कि उनके कार्यकाल में इन उपक्रमों ने कितना बेहतर प्रदर्शन किया है। केंद्र ने विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में 11,440 करोड़ रुपये का निवेश करने की बात कही है, जबकि दो दशक से इसके निजीकरण की बात चल रही थी।

केंद्रीय उपक्रमों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है? जब निफ्टी और सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर से 13 फीसदी गिरे हैं, तब इन उपक्रमों का सीपीएसई इंडेक्स 30 फीसदी लुढ़क चुका है! इससे करीब 13 लाख करोड़ रुपये या करीब 23 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। जरा सोचिए भारत इतने पैसे से क्या कर सकता था? देश में उत्तर से दक्षिण तक जाने वाली बुलेट ट्रेन बनाई जा सकती थी? पीएम किसान सम्मान की राशि कई गुना बढ़ाई जा सकती थी? या शायद एफ-35 विमानों के दो बेड़े खरीदे जा सकते थे, जिससे ट्रंप भी खुश हो जाते। ध्यान रहे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दशकों से कहते रहे हैं कि 'जिस देश का राजा व्यापारी, उस की प्रजा भिखारी।'

मोदी के नेतृत्व वाले भारत में सरकार के बहुत अधिक हस्तक्षेप की समस्या कभी नहीं रही। वहां खर्च की भी बात नहीं है। अफसरशाह चुनकर नहीं आते यह भी अच्छी बात मानी जाती है। वैचारिक शुद्धता तो आदर्श स्थिति है, लेकिन जहां यह नहीं होती वहां अफसरशाहों को काबू करने के उपाय होते हैं-पुरस्कार या दंड के जरिये। बेहतरीन जगह पर नियुक्ति, अधिकार और आप ज्यादा काम के हैं तो आपको कभी सेवानिवृत्त ही नहीं होने दिया जाएगा।

शुरू में प्रमुख पदों पर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया मसलन भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में। मगर उसके बाद हम भरोसेमंद आईएएस के दौर में लौट आए हैं। अवर सचिव के स्तर पर सीधी भर्ती का विचार तो एकदम काफूर हो गया। अर्थशास्त्री संजीव सान्याल के अधीन कम से कम एक साहसी प्रयास चल रहा है, जिसमें सरकारी रोजगार कार्यक्रम के तहत बने देरों संस्थान बंद किए जा रहे हैं। यह अच्छी पहल है। ध्यान रहे कि हमारी व्यवस्था में किसी की नौकरी नहीं जाती। उन्हें बस कहीं और भेज दिया जाता है।

मोदी के मंत्रिमंडल में भी अब विदेश मंत्रालय से लेकर पेट्रोलियम, रेलवे, आईटी आदि मंत्रालयों की कमान पूर्व अफसरशाहों के हाथ में है। मोदी को वहां राहत मिलती है, जहां ट्रंप की नफरत बरसती है। हमें नहीं पता कि कौन अच्छा है कौन बुरा क्योंकि किसे पता कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका को कहां ले जाएंगी। हम केवल यह कह रहे हैं कि शासन का ढांचा तैयार करने का ट्रंप और मोदी का तरीका एक दूसरे के उलट है।

मोदी और भाजपा के समर्थकों के लिए डीप स्टेट (नीतियों पर असर डालने वाली गैर सरकारी ताकतें) वह निराकार सत्ता है जिसमें ग्लोबल फाउंडेशन, वाम एक्टिविस्ट निकाय और निवेशक तथा उनके सहयोगी खुफिया तंत्र शामिल माने जाते हैं। वहीं ट्रंप के लिए डीप स्टेट ऐसी जगह है जहां अनिर्वाचित नौकरशाह रहते हैं, कई राष्ट्रपतियों के दौर में काम करते रहते हैं और राजनीतिक आदेश के आगे सर नहीं झुकाते। वह इसे नष्ट करना चाहते हैं और न्यायाधीशों के साथ भी वह ऐसा ही करेंगे।

ट्रंप और मोदी अलग-अलग ढंग के नेता हैं। उनके राजनीतिक तौर तरीके और शैलियां अलग हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह उनकी शासन शैली में कैसे नजर आता है।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए कठिन है आगे की डगर

सिटी यूनियन बैंक, कर्णाटका बैंक लिमिटेड, बंधन बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, डीसीबी बैंक लिमिटेड और पंजाब एवं सिंध बैंक में एक जैसा क्या है? जवाब है इन सभी की गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए), जो कम से कम 1 प्रतिशत हैं। ऐक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और कुछ अन्य बैंकों में एनपीए केवल 0.5 प्रतिशत है। एनपीए का यह आंकड़ा सूचीबद्ध यूनिवर्सल बैंकों के दिसंबर तिमाही के नतीजों से लिया गया है।

जहां तक सकल एनपीए की बात है तो बंधन बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड और पंजाब नैशनल बैंक में सकल एनपीए कम से कम 4 प्रतिशत है और ऐक्सिस बैंक तथा एचडीएफसी बैंक में एनपीए 1.5 प्रतिशत से कम है। वित्त वर्ष 2024-25 की दिसंबर तिमाही में अच्छी बात यह रही है कि ऐसे बैंकों की संख्या अधिक रही है, जिनका सकल एवं शुद्ध एनपीए प्रतिशत कम रहा है। यह बात और है कि पूरे आंकड़े देखने पर निजी बैंकों की सकल एनपीए सितंबर तिमाही की 1.35 लाख करोड़ रुपये से मामूली बढ़कर दिसंबर में 1.39 लाख करोड़ रुपये हो गई। एक साल पहले इसी अवधि में यह 1.37 लाख करोड़ रुपये थी।

शुद्ध एनपीए में भी यही रुझान देखा जा रहा है, जो दिसंबर तिमाही में बढ़कर 36,260 करोड़ रुपये हो गई। यह सितंबर में 34,843 करोड़ रुपये और दिसंबर 2023 में 33,116 करोड़ रुपये थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी फंसे ऋणों की मात्रा कम हो रही है। उनमें दिसंबर 2023 तिमाही में 4.93 लाख करोड़ रुपये सकल एनपीए थी, जो सितंबर तिमाही में कम होकर 4.57 लाख करोड़ रुपये रह गई। यह दिसंबर 2024 में और कम होकर 4.44 लाख करोड़ रुपये रही। शुद्ध एनपीए भी दिसंबर 2020 के 1.12 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से कम होकर सितंबर 2024 में 99,675 करोड़ रुपये रह गई। दिसंबर 2024 में यह और भी घटकर 99,556 करोड़ रुपये तक आ गई।

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेहन या जमानत के बगैर दिए जा रहे पर्सनल लोन में तेज इजाफा देखकर इसमें कमी लाने के उपाय किए थे, जो कारगर होते दिख रहे हैं। नवंबर 2023 में केंद्रीय बैंक ने ऐसे कर्ज पर जोखिम भार बढ़ा दिया, जिससे बैंकों के लिए इस तरह का कर्ज देना महंगा हो गया क्योंकि उन्हें इसके लिए अधिक पूंजी की जरूरत पड़ रही है। इससे पर्सनल लोन श्रेणी में एनपीए काबू में आ रही है।

बैंकिंग साख
तमाल बंद्योपाध्याय

दिसंबर तिमाही में निजी क्षेत्र के बैंकों की शुद्ध ब्याज आय दिसंबर 2023 तिमाही के मुकाबले 8.88 प्रतिशत बढ़कर 1.02 लाख करोड़ रुपये हो गई। सितंबर 2024 तिमाही के मुकाबले इसमें 1.51 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शुद्ध ब्याज आय एक साल पहले की तुलना में 5.44 प्रतिशत बढ़कर 1.07 लाख करोड़ रुपये हो गई मगर सितंबर 2024 तिमाही के मुकाबले इसमें 1.06 प्रतिशत बढ़ोतरी ही दर्ज की गई। बैंक कर्ज पर जो ब्याज कमा रहे होते हैं, उसमें से जमा पर दिया जा रहा ब्याज घटाने पर उनकी शुद्ध ब्याज आय निकल आती है।

दिसंबर तिमाही में निजी बैंकों की अन्य आय भी दिसंबर 2023 से 10.2 प्रतिशत बढ़ी मगर सितंबर 2024 की तुलना में यह 1.7 प्रतिशत गिर गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में साल भर पहले से 14.04 प्रतिशत और एक तिमाही पहले से 18.64 प्रतिशत तक तेजी देखी गई। अन्य आय में फीस, कमीशन और ट्रेजरी आय शामिल होती हैं।

दिलचस्प बात कि निजी बैंकों ने पिछले साल फंसे ऋणों के लिए जितनी रकम का प्रोविजन या इंतजाम किया था वह साल भर पहले के मुकाबले भी बढ़ी और एक तिमाही पहले के मुकाबले भी। मगर इसमें किसी साफ रुझान का पता नहीं चल रहा है। दिसंबर 2023 तिमाही में निजी बैंकों ने ऐसे कर्ज के लिए 10,997 करोड़ रुपये रखे थे, जो सितंबर 2024 तिमाही में बढ़कर 13,134 करोड़ रुपये हो गए और दिसंबर 2024 तिमाही में उन्हें 14,149 करोड़ रुपये का प्रोविजन करना पड़ा। सार्वजनिक बैंकों ने दिसंबर 2023 तिमाही में 12,495 करोड़ रुपये और सितंबर 2024 में 16,445 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया था मगर दिसंबर 2024 तिमाही में रकम घटकर 10,193 करोड़ रुपये ही रह गई।

बैंकों के कुल परिचालन मुनाफे की बात करें तो दिसंबर तिमाही में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह 10.6 प्रतिशत बढ़कर 75,315 करोड़ रुपये हो गया, जो सितंबर में खत्म तिमाही की तुलना में सपाट ही था। प्रोविजन के बाद शुद्ध मुनाफा साल भर पहले से 3.97 प्रतिशत बढ़कर 46,374 करोड़ रुपये हो गया मगर एक तिमाही पहले की तुलना में 2.48 प्रतिशत की कमी आ गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का परिचालन मुनाफा दिसंबर तिमाही में 13.28 प्रतिशत बढ़कर 70,218 करोड़ रुपये हो गया मगर सितंबर तिमाही के मुकाबले यह 10.72 प्रतिशत फिसल गया। एक साल पहले की तुलना में इन बैंकों का शुद्ध मुनाफा 46.81 प्रतिशत बढ़कर 44,474 करोड़ रुपये रहा मगर एक तिमाही पहले से यह 2.36 प्रतिशत कम हो गया।

खत्म करने से पहले बैंकों के मुनाफे का आकलन करने वाले दो सबसे अहम पैमाने देख लेते हैं। ये हैं - कुल जमा में सस्ते चालू एवं बचत खाते (कासा) का प्रतिशत और बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) शामिल हैं। बैंक जमा पर जितना ब्याज देते हैं और ऋण पर जो ब्याज कमाते हैं उनके अंतर का प्रतिशत ही यह मार्जिन होता है।

छह बड़े बैंकों - दो निजी और चार सरकारी बैंक - का कासा अनुपात दिसंबर तिमाही में मामूली बढ़ा है। येस बैंक का कासा 32 प्रतिशत से बढ़कर 33.1 प्रतिशत और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कासा 32.72 प्रतिशत से बढ़कर 33.43 प्रतिशत हो गया। पंजाब ऐंड सिंध बैंक के लिए यह 30.43 प्रतिशत से बढ़कर 31.16 प्रतिशत और इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए 42.44 प्रतिशत से बढ़कर 43.37 प्रतिशत हो गया। आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को छोड़कर सभी बैंकों का कासा अनुपात दिसंबर तिमाही में साल भर पहले से कम रह गया।

इस बीच ज्यादातर बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन दिसंबर तिमाही में कम रहा है, जिसे बैंक द्वारा बांटे गए ऋण से जोड़कर देखा जाता है। अगर असुरक्षित ऋण श्रेणी में किसी बैंक की हिस्सेदारी ज्यादा होती है तो उसका शुद्ध ब्याज मार्जिन अधिक रहता है मगर उसे ऋण की लागत या परिसंपत्ति की गुणवत्ता पर थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है।

नीतिगत दर में 25 आधार अंक की कटौती के बाद बैंकों के शुद्ध ब्याज मार्जिन पर और असर पड़ सकता है। सभी खुदरा ऋण रीपो रेट से जुड़े होते हैं। रीपो रेट में कमी से बैंक ऐसे ऋणों पर ब्याज कम कर रहे हैं मगर रकम जुटाने पर उनका खर्च कम नहीं हुआ है क्योंकि वे जमा पर ब्याज दर कम नहीं कर रहे हैं। कंपनियों को आवंटित ऋण रकम जुटाने पर आ रही बैंकों की लागत से जुड़े होते हैं। बैंक जमा पर अपनी लागत संभालने के लिए कंपनियों के लिए कर्ज महंगा कर रहे हैं। जब तक बैंकों में जमा रकम पाने की होड़ लगी रहेगी तब तक बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन दबाव में रहेगा।

शेयर बाजार में तेज गिरावट और म्यूचुअल फंड निवेश में कमी को देखते हुए कुछ बैंकों को जमा बढ़ने की उम्मीद दिखने लगी है। मगर फिलहाल स्थिति साफ होने का इंतजार ही किया जा सकता है।

आपका पक्ष

केंद्रीय कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़े

लेख 'केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ती संख्या के लाभ!' में केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारियों एवं अधिकारियों के संख्या बल पर बहुत तर्कसंगत चर्चा की गई है। नए कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भर्ती का विषय राजनीतिक दलों द्वारा घोषणाओं और केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में आवश्यक एवं स्वीकृत संख्याबल के बीच फंसा हुआ है। बेरोजगारी के विषय पर राजनीतिक दल भले ही दस-बीस लाख कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा करें, परंतु यह धरातल पर और वास्तविकता में साकार होना संभव नहीं है। यही स्थिति राज्य सरकारों की भी है। एक तरफ शासन- प्रशासन, जन-भागीदारी, बैंकिंग, डायरेक्ट कैश बेनिफिट जैसी कल्याणकारी योजनाएं, आयकर व जीएसटी राजस्व संग्रहण, आधार आदि आधुनिकतम टेक्नॉलिजी से संचालित हो रहे हैं, दूसरी तरफ कर्मियों की भर्ती का चुनावी भार विषय को उलझा रहा है। सरकारों के पास विकल्प कम हैं। सरकार के लिए यह भी संभव नहीं कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 58 वर्ष कर दे जिससे युवा और शिक्षित कैडर की भर्ती हो सके परंतु अचानक सेवानिवृत्त कर्मियों को अरबों रुपयों का रिटायरमेंट भुगतान करना संभव नहीं है। केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों की उत्पादकता भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। 'बाबू संस्कृति' से सरकारी विभागों में कोई उत्पादकता और वृत्ति दक्षता नहीं बढ़ सकती। अब सरकार में कर्मियों में कुशल कार्यशक्ति चाहिए। इसलिए सबसे पहले सभी विभागों में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की जाए और केवल आवश्यकता-नुसार ही भर्ती की जाए। राजनीतिक दल और सरकारें निजी क्षेत्र, उद्योग व्यापार में व्यापार और रोजगार सृजित करें और सरकारी नौकरियों पर राजनीति करना बंद करें।

विनोद जौहरी, दिल्ली

केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों की उत्पादकता भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है

हरित विकास की नई राह

भारत के घने जंगल केवल प्राकृतिक धरोहर नहीं, बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय समृद्धि के स्तंभ भी हैं। सरकार ने वनों के सतत विकास और प्रबंधन को नया आयाम देने के लिए 40 वर्षों के लीज मॉडल की पहल की है, जिससे कार्बन क्रेडिट, वैज्ञानिक वन प्रबंधन और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। 95 लाख हेक्टेयर में से 37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इस योजना में शामिल किया गया है, जिससे हरित अर्थव्यवस्था को गति मिलने की संभावना है। यह नीति दीर्घकालिक दृष्टि से वनों के कुशल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन से निपटने और रोजगार सृजन में सहायक हो सकती है। निजी निवेश से जंगलों में आधुनिक तकनीकों का समावेश होगा, जिससे वन संपदा का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार को चाहिए कि इस योजना को पारदर्शी व न्यायसंगत बनाते हुए स्थानीय समुदायों और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोपरि रखे। यदि सही दिशा में इसे क्रियान्वित किया जाए, तो यह पहल भारत को वैश्विक स्तर पर हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास की ओर अग्रसर करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

रमजान के मौके पर रविवार को दक्षिणी गाजा पट्टी में इफ्तार में शामिल फिलिस्तीनी लोग। इजरायल ने रविवार को गाजा पट्टी में सभी तरह की राहत सामग्री की आपूर्ति और मानवीय सहायता पर रोक लगाने के साथ चेतावनी दी कि यदि हमास ने संघर्ष विराम के विस्तार के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो उसे 'और भी नतीजे' भुगतने होंगे।

सम्पादकीय

सरकारी नौकरियां बढ़ीं, लेकिन कामकाज में तेजी आई या नहीं?

जून 2022 में नरेंद्र मोदी सरकार ने रोजगार निर्माण पर एक साहसी घोषणा की थी। उसने अगले 18 महीनों में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी। घोषणा के मुताबिक ये भर्तियां 'मिशन' की तरह की जानी थीं। घोषणा के राजनीतिक और आर्थिक मायने थे। राजनीतिक इसलिए यह 2024 में होने वाले आम चुनावों से महज दो साल पहले की गई थी, जब राजनीतिक दलों और आम लोगों के बीच नौकरी अहम मुद्दा बन गई थी। आर्थिक इसलिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम बाजार में तेजी से जुड़ते लोगों के लिए वेतन वाली और अधिक नौकरियां तैयार करने की चुनौती से जूझ रही थी। केंद्र सरकार सबसे अधिक रोजगार देने वालों में है और वह इस राजनीतिक तथा आर्थिक जरूरत को पूरा करना चाहती थी। केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में बनी रिक्तियों ने इस वादे को पूरा करने का काम तेज किया। फरवरी-मार्च 2022 में तत्कालीन कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में मार्च 2020 तक करीब 8.70 लाख पद खाली थे। सबसे ज्यादा 2.47 लाख असैन्य पद रक्षा मंत्रालय में खाली थे। उसके बाद रेलवे में 2.37 लाख, गृह मंत्रालय में 1.28 लाख (ज्यादातर केंद्रीय पुलिस बलों में), डाक विभाग में 90,000 और अंकेक्षण विभाग में 28,000 रिक्तियां थीं। कुल रिक्तियों की 84 फीसदी तो इन्हीं में थीं। उस समय केंद्र सरकार में कुल 40 लाख कर्मचारी तय किए गए थे। फरवरी के आरंभ में प्रस्तुत 2025-26 के केंद्रीय बजट से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के अलावा अपने सभी विभागों और मंत्रालयों में किस तरह भर्तियां कीं। हकीकत में आंकड़े दिखा रहे हैं कि रेलवे सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है। मगर बढ़ोतरी उतनी नहीं है, जितनी का वादा जून 2022 में किया गया था। केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों की संख्या मार्च 2022 के अंत में 31.7 लाख थी। इसमें सशस्त्र बल के कर्मचारी शामिल नहीं हैं। दो साल बाद यानी मार्च 2024 के अंत में आंकड़ा बढ़कर 33 लाख हो गया। इस तरह दो साल में 1.37 लाख यानी केवल 4 फीसदी कर्मचारी बढ़े। अनुमान है कि मार्च 2025 तक संख्या बढ़कर 36.6 लाख हो जाएगी। ध्यान रहे कि मार्च 2025 के आंकड़े कर्मचारियों की वास्तविक संख्या नहीं बताते। परंतु अगर इस संशोधित आंकड़े को भी सही मान लें तो अप्रैल 2022 से अब तक कर्मचारियों की संख्या में करीब 4.89 लाख अथवा 15 फीसदी का इजाफा हुआ। इस बात के लिए सरकार की आलोचना की जा सकती है कि 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों का वादा किया गया मगर तीन साल बाद उसकी आधी नौकरियां भी नहीं दी गई हैं। सरकार यह कहकर खुद को सही साबित करेगी कि आधे लक्ष्य ने भी रोजगार की चिंता को कुछ हद तक दूर किया है। ज्यादा सरकारी नौकरियों के सृजन के अच्छे या खराब पहलू पर बात करने के बजाय इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि 1991 से 2022 तक सभी सरकारों के कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों का आंकड़ा कम ही हुआ है। केंद्र सरकार के कुल असैन्य कर्मचारियों की बात करें तो मार्च 1991 में करीब 40 लाख कर्मचारी थे। मार्च 2014 तक इनकी संख्या कम होकर 33.2 लाख रह गई। मोदी सरकार भी मार्च 2022 तक इनकी तादाद कम करके 31.7 लाख पर ले आई। सार्वजनिक नीति संबंधी अधिकतर बहसों में जिस बात की अनदेखी कर दी जाती है वह यह है कि हाल के सालों में सरकार ज्यादा विरोध या आंदोलन का सामना किए बगैर कर्मचारियों की संख्या घटाने में कामयाब रही है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि रिक्तियों को जानबूझकर नहीं भरा गया और कई नौकरियां खत्म कर दी गईं। उन्हीं नौकरियों को ठेके पर या अस्थायी कर्मचारियों के जरिये कराया गया।

मगर कर्मचारियों की तादाद तीन दशक में 21 फीसदी घटा दी गई और कोई उथल-पुथल भी नहीं हुई! ध्यान रहे कि इन सरकारों में से किसी ने भी इन कर्मचारियों की मंजूर संख्या नहीं घटाई और वह अब भी 40 लाख ही है।

आज का इतिहास

बढ़ता राजस्थान

3 मार्च की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- भारतीय मुगल बादशाह अकबर ने 1575 में बंगाली सेना को तुकरोई की लड़ाई में पराजित किया।
- राजा राव नंदलाल मंडलोई ने 1716 में इंदौर शहर की स्थापना की थी।
- अमेरिकी कांग्रेस ने 1812 में पहला विदेशी सहायता बिल पास किया था।
- फ्लोरिडा 1845 में अमेरिका का 28वां राज्य बना था।
- चीन और फ्रांस-ब्रिटेन के बीच 1857 में युद्ध हुआ था।
- 1915 में की स्थापना नाका जो कि बाद में नासा बना।
- 1923 में टाइम पत्रिका का पहली बार प्रकाशन हुआ।
- कैल्विन कूलेज 1924 में व्हाइट हाउस से रेडियो संदेस प्रसारित करने वाले पहले अमेरिकि राष्ट्रपति बने।
- सऊदी अरब में कच्चे तेल की 1938 में खोज हुई थी।
- महात्मा गाँधी जी ने 1939 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रारम्भ किया।
- फ्रांस से उत्तर अफ्रीका के देश मोरक्को को 1956 में आजादी मिली थी।
- तुर्की एयरलाइंस का डीसी10 विमान 1974 में पेरिस के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमान में सवार लगभग सभी लोगों की मौत हो गई।
- सातवां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन नयी दिल्ली में 1983 में संपन्न हुआ।
- आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया अधिनियम 1986 लागू होने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था।
- पाकिस्तान के लाहौर में मैच खेलने जा रही श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की बस पर 2009 में हथियारबंद लोगों ने गोलियां चला दीं।
- संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में 3 मार्च को 'विश्व वन्य जीवन दिवस' के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की थी।

03 मार्च को जन्मे व्यक्ति

- भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का 1839 में जन्म हुआ था।
- टेलीफोन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का 1847 में जन्म हुआ था।
- भारत के प्रसिद्ध अभिनेता और कॉमेडियन जसपाल भट्टी जी का 1955 में जन्म हुआ था।
- कारगिल युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाने के लिए 1999 में परमवीर चक्र से सम्मानित राइफलमैन संजय कुमार जी का 1976 में जन्म हुआ।

03 मार्च को हुए निधन

- मुगल साम्राज्य का आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब का सन 1707 में अहमदनगर में निधन हुआ था।
- मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक हरि नारायण आप्टे जी का 1919 में निधन हुआ था।
- उर्दू साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले शायर फिराक गोरखपुरी का 1982 में निधन हुआ था।
- भारत के राजनेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जी. एम. सी. बालायोगी जी का 2002 में आंध्र प्रदेश में हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

विशेष आलेख

विश्व वन्यजीव दिवस

केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक संकल्प

20 दिसंबर, 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में अंकित किया। इसका मूल ध्येय है–वन्यजीवों और वनस्पतियों के प्रति वैश्विक चेतना का प्रज्वलन और उनके प्राकृतिक अधिवासों को अक्षुण्ण रखने की पुकार। वर्ष 2025 की थीम प्रकृति और संरक्षण का उत्सव एक मंत्र-सा है, जो प्रकृति की अलौकिक छटा, उसकी अनंत गहराई और संरक्षण की अनिवार्यता को उजागर करता है। यह हमें आमंत्रित करता है कि हम प्रकृति के साथ एक लय में बंधे, उसके संगीत को सुनें और उसकी रक्षा के लिए संकल्प लें।

प्रो. आरके जैन

वन्यजीव इस धरती के अनुपम रत्न हैं, प्रकृति की उस अनमोल थाती के प्रतीक जो इस विशाल सृष्टि के संतुलन को थामे हुए हैं। ये प्राणी केवल जैविक वैविध्य की शोभा नहीं, अपितु मानव जीवन के उद्गम, उसकी यात्रा और उसके संपूर्ण अस्तित्व के आधार हैं। ये धरती की धड़कन हैं, जो अपने मूक स्वर से प्रकृति के सौंदर्य को जीवंत करते हैं। किंतु, आधुनिकता की उन्मत्त दौड़, शहरीकरण का अनियंत्रित विस्तार, शिकार की क्रूर लिप्सा और प्रदूषण का विषैला जाल इन नन्हे जीवन-संगियों को लील रहा है। अनेक प्रजातियाँ समय के अंधेरे गर्भ में समा चुकी हैं, और असंख्य अन्य अपने अंतिम प्राण गिन रही हैं। यह दारुण दृश्य हमें झकझोरता है कि वन्यजीवों की रक्षा अब केवल कर्तव्य नहीं, अपितु हमारी आत्मा का आह्वान और मानवता का परम धर्म बन चुका है। इसी संकल्प को बल देने हेतु प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, जो हमें इन प्राणियों के प्रति संवेदना का दीप जलाने और संरक्षण का पथ प्रशस्त करने को प्रेरित करता है। वन्यजीवों को बचाने का मार्ग बहुआयामी और दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण होना चाहिए। प्रथम, वनों की अंधी लूट और शहरीकरण की अनियंत्रित आँधी पर लगाम कसनी होगी। वृक्षों का

अनवरत संहार वन्यजीवों से उनका घर छीन रहा है, साथ ही जलवायु परिवर्तन के भयावह दानव को पोषित कर रहा है। वृक्षारोपण का महायज्ञ शुरू करना होगा–हर पौधा एक आशा है, हर वन एक जीवन। सतत विकास का स्वप्न साकार कर हम इस संकट को परास्त कर सकते हैं। वृक्ष धरती की श्वास हैं, और इनके बिना जीवन का संगीत मंद पड़ जाएगा।

दूसरा, प्रदूषण का यह विषचक्र तोड़ना होगा। प्लास्टिक का अंबार और कचरे का जहर जल और थल के प्राणियों को निगल रहा है। समुद्र के गर्भ में मछलियाँ, कछुए और जलपक्षी इस कृत्रिम आपदा के शिकार बन रहे हैं। प्लास्टिक को जीवन से निर्वासित करना होगा–पुनर्चक्रण का संकल्प और प्रकृति के प्रति संयम ही इस संकट का कवच बन सकता है। स्वच्छता का यह अभियान हर प्राणी के लिए जीवन का उपहार होगा। तीसरा, स्थानीय जनमानस को वन्यजीवों की महिमा का बोध कराना होगा। जब हर दिल यह समझेगा कि ये प्राणी केवल जंगल के आभूषण नहीं, बल्कि जीवन-चक्र के स्पंदन हैं, तब हर हाथ संरक्षण के लिए उठेगा। शिक्षण संस्थाएँ, संगठन और सरकारें मिलकर ज्ञान का ऐसा दीप जलाएँ जो अज्ञान के अंधेरे को चीर दे। विशेषकर वनवासी और ग्रामीण समुदाय इनके संरक्षक बन सकते हैं–उनके भीतर प्रकृति का प्रेम पहले से ही बस्ता है, बस उसे जागृत करना है। चौथा, अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार का यह काला कारोबार कुचलना होगा। दुर्लभ प्राणियों की निर्मम हत्या केवल लालच की भेंट चढ़ रही है–बाघ का गर्वीला रुदन, गैंडे का शांत चिंतन और हाथी की विशालता व्यापार की भट्टी में जल रही है। कठोर कानून और उनका दृढ़ पालन ही इस संकट का अंत कर सकता है। हर नागरिक को संरक्षक बनना होगा–हर आँख सतर्कता का प्रहरी और हर कदम न्याय का संवाहक। पाँचवाँ, संरक्षण संगठनों को शक्ति देनी होगी। ये संगठन वन्यजीवों के लिए योद्धा हैं, जो दिन-रात उनके जीवन की रक्षा में संलग्न हैं। हमारा सहयोग–चाहे धन से, समय से या संदेश के प्रसार से–इनके संकल्प को पंख देगा। ये संगठन अकेले नहीं लड़ सकते; यह युद्ध हम सबका है। आज जब वन्यजीवों पर संकट की काली छाया गहरा रही है, तब यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम संरक्षण का संकल्प करें। प्रकृति और संरक्षण का उत्सव एक थीम नहीं, बल्कि एक स्वर है–प्रकृति का स्वर, जो हमें जीवन का मोल समझाता है। यदि आज हम चूप रहे, तो कल की पीढ़ियाँ इस सौंदर्य को कोसेंगी। उनकी आँखों से यह विविधता छिन जाएगी, और हम इतिहास के गुनहगार कहलाएँगे। समय आ गया है उठ खड़े होने का–एक ऐसा संकल्प करें जो वन्यजीवों में जीवन, प्रकृति में सम्मान और धरती में समृद्धि का संदेश फैलाए। विश्व वन्यजीव दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक पुकार है–एक जागृति जो हमें याद दिलाती है कि यह धरती तभी तक जीवंत है, जब तक हर प्राणी का स्वर इसमें गूँजता रहता है। हर साँस, हर कदम, और हर प्रयास इस अद्भुत संगीत को अनंत बनाए। चलिए, हम एकजुट होकर इस धरती के हर प्राणी के लिए एक शाश्वत और सजीव संगीत की रचना करें, जो युगों-युगों तक गूँजता रहे।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आज कई विशिष्ट स्थानों की युति होगी। इसका आज एक साथ असरदार रहेगी है कि आपके जीवन के किसी परिवर्तन होने है, तथा आपको किसी कुशल लोगों और दुनियां तथा, आपको विशेष बातों से सावधान रहना। रात्रि में किसी स्वजनों सहयोग और अधिक युद्धों को सुलझाने वाला सहायतापूर्ण आज्ञ को समझना होगे, बल्कि परस्पर्शित संबंधों में भी, तथा एक सहायतापूर्ण सर्व संतुष्ट और बातों में सफल प्राप्त होगा

मेष
पैसे की तंगी महसूस होगी। दुर्घटना, ऑपरेशन का योग बन रहा है, इसलिए सावधानी बरतें। ईश्वर भक्ति से राहत महसूस कर सकेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। सार्वजनिक जीवन में अपयश या स्वाभिमान भंग होने का योग है।

वृष
प्रिय व्यक्ति के साथ की गई मुलाकात रोमांचक रहने की उम्मीद है। तन-मन से ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव होगा। अत्यधिक विचारों से मन विचलित रहेगा। आज किसी के साथ बौद्धिक चर्चा या वाद-विवाद हो सकता है।

मिथुन
आज के दिन आप शारीरिक और मानसिक रूप से भय अनुभव करेंगे। पारिवारिक सदस्यों तथा सगे- संबंधियों के साथ अनबन होने की आशंका है। कोशिश करें कि किसी के साथ विवाद न हो। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कर्क
सरकार से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रतिकूल संयोग के बनने से आपके कार्य में विलंब होगा। पेट के रोग सताएंगे। नौकरी में अधिकारियों के नकारात्मक व्यवहार से आपको दुख होगा। परिजनों के साथ गलतफहमी पैदा होने से मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव होगा।

सिंह
भागीदारों के साथ मतभेद होगा। कुछ खास दोस्तों के साथ मुलाकात विशेष आनंददायक नहीं रहेगी। कोर्ट- कचहरी के काम में दिक्कत होने की आशंका है। आर्थिक लाभ और काम में सफलता मिलेगी। बीमारी में राहत महसूस होगी।

कन्या
आपका आज का दिन सामाजिक प्रवृत्तियों और मित्रों के साथ दौड़-धूप में व्यतीत होगा। फिर भी सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। आज के दिन बुजुर्गों और पूजनीय व्यक्तियों से मुलाकात होगी। आज कोई भी सोच-विचार करने के बाद ही बोलें।

तुला
नए काम की शुरुआत आज कर सकते हैं। सगे-संबंधियों तथा मित्रों का आपके यहां आगमन होने से आनंद अनुभव होगा। कहीं यात्रा होने की संभावना है। भाग्य वृद्धि का अवसर मिलेगा। धार्मिक कार्यों में मन लगाएंगे, तो शांति मिलेगी।

वृश्चिक
अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। आज आप कल्पना और सृजनशक्ति का उपयोग कर सकेंगे। संतान की प्रगति होगी, जिससे आपका मन खुश रहेगा।

धनु
बाहर का खाने-पीने के कारण स्वास्थ्य खराब होने की आशंका है। अपने क्रोध की नियंत्रण में रखें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ बखेड़ा खड़ा हो सकता है। नए संबंध तकलीफदायक साबित होंगे।

मकर
जमीन, वाहन वगैरह की खरीदारी के दस्तावेज बनवाने में सावधानी रखें। गृह रहस्यमय विद्याएं और आध्यात्मिकता का प्रभाव आप पर विशेष रहेगा। आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा। भाई-बहनों के साथ मेल-जोल बना रहेगा।

कुंभ
सरकारी काम में बाधा होगी। महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय आज स्थगित रखना उचित रहेगा। संतान के साथ मतभेद होगा। विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है। आज मन का नकारात्मक व्यवहार आपको हताश करेगा।

मीन
आज आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे। नौकरीपेशा वालों के लिए आज का दिन शुभ है। उन्हें आय वृद्धि या पदोन्नति का समाचार मिलेगा। सरकारी लाभ मिलेगा। उच्च अधिकारियों का प्रोत्साहन आपका उत्साह बढ़ाएगा। धन खर्च होने की संभावना है।

न्यायालयों में अनसुलझे मामलों की बढ़ती हुई संख्या

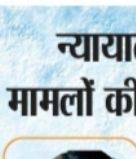

प्रियंका सौरभ

देश की न्याय व्यवस्था कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों से जूझ रही है, जिसका मुख्य कारण भारतीय अदालतों में अभी भी 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यह लंबित मामले न केवल न्याय में देरी करते हैं, बल्कि कानूनी व्यवस्था में लोगों का भरोसा भी कम करते हैं। इनमें से कई मामले एक दशक से अधिक समय से लंबित हैं, जिनमें से लगभग 50 लाख मामले दस साल से भी अधिक समय पहले शुरू किए गए थे। नीति आयोग ने सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है, चेतावनी दी है कि मामले के समाधान की वर्तमान गति से, केवल जिला अदालतों में लंबित मामलों को हल करने में 300 साल से अधिक लग सकते हैं।

भारत में, लंबित मामलों का अर्थ कानूनी ढांचे के भीतर अनसुलझे मामलों की भारी संख्या है। स्थिति विशेष रूप से निचले न्यायिक स्तरों पर गंभीर है, जहाँ अधिकांश मामले दायर किए जाते हैं और न्यायाधीशों की कमी से निपटान नहीं होता है। लंबित मामलों की बढ़ती संख्या भारतीय न्याय वितरण प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती है। लंबी कानूनी प्रक्रियाएँ न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है कहावत को चरितार्थ करती हैं, क्योंकि वे जनता के विश्वास को खत्म कराती हैं और व्यक्तियों को समय पर न्याय से वंचित करती हैं। बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद जैसे मामलों के लंबे समाधान ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ दिया है, जिसमें लगभग 70 साल लग गए। अदालतों में मामलों की विशाल मात्रा अदालती दक्षता में बाधा डालती है और लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि करती है, जिससे त्वरित न्याय लगभग असंभव हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में 82, 000 से अधिक और उच्च न्यायालयों में 62 लाख से अधिक मामले लंबित होने के कारण, निर्णयों में बड़ी देरी आम बात है। मुकदमेबाजी का वित्तीय बोझ आर्थिक विकास को भी बाधित करता है, क्योंकि यह संसाधनों को खत्म करता है और व्यक्तियों और व्यवसायों को कानूनी कार्यवाही करने से हतोत्साहित करता है। भारत में न्यायिक देरी की अनुमानित लागत दो मिलियन डॉलर से अधिक है। न्याय प्रणाली पर लंबित मामलों का प्रभाव गहरा और दूरगामी है। लंबे समय तक चलने वाले मामले कानूनी प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म कर सकते हैं, जिससे इसकी प्रभावशीलता के बारे में निराशा और संदेह पैदा होता है, जिससे कुछ लोग वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों की तलाश करने लगते हैं। देरी का यह चक्र समस्या को और बढ़ाता है। न्यायिक देरी में योगदान देने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक जनसंख्या के लिए न्यायाधीशों का अपर्याप्त अनुपात है। भारत में, विकसित देशों की तुलना में कानूनी प्रणाली बहुत धीमी गति से काम करती है, जहाँ हर दस लाख निवासियों के लिए केवल 21 न्यायाधीश उपलब्ध हैं। सरकार सबसे बड़ी वादी है, जो सभी लंबित मामलों में से लगभग आधे मामलों के लिए जिम्मेदार है, जिनमें से कई तुच्छ मुद्दों पर अपील में बंधे हैं। सीमित कोर्ट रूम स्पेस और पुरानी केस मैनेजमेंट प्रथाओं जैसी चुनौतियों से लंबी अदालती कार्यवाही और भी जटिल हो जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र ने 15 वर्षों में 200, 000 से अधिक मामलों को सफलतापूर्वक हल किया है, जो वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों की प्रभावशीलता को उजागर करता है। दुर्भाग्य से, वकील और वादी दोनों अक्सर स्थगन का दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण मामले सालों या दशकों तक टल जाते हैं। मैन्युअल दस्तावेज़ीकरण और पुरानी कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भरता मामलों के समय पर समाधान में बाधा डालती है, जिससे अनावश्यक नौकरशाही बाधाएँ पैदा होती हैं। लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने के लिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कार्यवाही निरंतर हो।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नारायण सिंह
(आईएएस)

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं आईएएस श्री नारायण सिंह जी। 2 दिसम्बर सन् 1968 को सीकर जिले में जन्में नारायण सिंह बहुत ही शानदार अधिकारी हैं। अलवर एसडीएम व एडीएम प्रथम के कार्यकाल के दौरान इनकी शानदार कारंसी देखने को मिली। आज ये प्रबन्ध निदेशक, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, राजस्थान जयपुर जैसे बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं। इससे पूर्व ये प्रबन्ध निदेशक, राजफेड जयपुर। सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर। संयुक्त शासन सचिव, सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर। अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, खेल एवं युवा मामलात विभाग जयपुर। अतिरिक्त कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा। अतिरिक्त कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर। अतिरिक्त कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, अलवर। उपखण्ड अधिकारी, अलवर। उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी धौलपुर। उपखण्ड अधिकारी, नागौर। उपखण्ड अधिकारी, सीजत। उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा कोटा। उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल जालौर। उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा बांसवाड़ा। सहायक कलेक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अलवर रहे हैं। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

सत्यम शर्मा

2025_060

बढ़ता राजस्थान

Suduko

		8			2		9	
	9	4		8		2		
	7	6		3	9	4		
			9		4			1
9	6	3		7	1		4	2
		1	3	2	5	9		
				5	6	1	7	9
6	4	9				8		5

Ans_2025_059

9	5	7	6	2	1	8	3	4
3	2	4	5	7	8	1	6	9
8	6	1	3	9	4	5	2	7
5	7	8	1	6	9	3	4	2
4	1	3	7	8	2	9	5	6
2	9	6	4	3	5	7	1	8
1	3	2	9	4	7	6	8	5
7	8	5	2	1	6	4	9	3
6	4	9	8	5	3	2	7	1

कैसे खेलें

वर्ग को 1 से 9 तक अंकों से ऐसे भरें कि आड़ी व खड़ी पंक्ति के साथ ही 3 गुणा 3 के बॉक्स में 1 से 9 तक अंक आएं। कोई अंक दुबारा नहीं आए।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश जिलवर्मसिंह द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इंदिरापुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान* । प्रधान संपादक-राव बिलास जिलवर्मसिंह मो.नं. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-भाईपथा निवाई, टोंक मो.नं.9414823448 अलवर कार्यालय-नेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो.नं. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.नं.7023350734 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 3 मार्च 2025

यह कैसी कूटनीति

वाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को जिस तरह की तीखी नोकझोंक देखने को मिली, उसे कूटनीति के इतिहास में अभूतपूर्व कहा जा सकता है। लाइव टीवी कवरेज के जरिए पूरी दुनिया ने पहली बार देखा कि दो राष्ट्राध्यक्ष अपनी टीम के साथ एक-दूसरे से तू-तू मैं-मैं कर रहे हैं।

ट्रंप-जेलेंस्की में नोकझोंक

बात सही, तरीका गलत | वैसे, दोनों पक्षों के स्टैंड पर गौर करें तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती जिसे सिरे से गलत कहा जाए। रूस-यूक्रेन युद्ध को तीन साल से ज्यादा हो चुके हैं। अमेरिका इस युद्ध में लगातार यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। अब अगर उसे लगता है कि अपने देश के करदाताओं का पैसा इस लड़ाई में नहीं झोंका जाना चाहिए, तो इसमें कुछ भी असंगत नहीं है। इस लिहाज से उसकी यह कोशिश जायज है कि यह लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो।

सुरक्षा गारंटी का सवाल | दूसरी तरफ, यूक्रेन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि युद्धविराम के बाद रूस फिर से हमला न कर बैठे। कारण चाहे जो भी हों, उसकी यह शिकायत तथ्यात्मक रूप से सही है कि रूस अलग-अलग बहानों से उस पर हमले करता रहा है, सहमतियां तोड़ता रहा है। ऐसे में जहां अमेरिका पहले समझौता और युद्धविराम पर जोर दे रहा था, वहीं यूक्रेन पहले सुरक्षा गारंटी चाहता था।

गतिरोध अस्वाभाविक नहीं | दो देशों के बीच सहमति बनने से पहले इस तरह का गतिरोध आना कोई नई या अस्वाभाविक बात नहीं है। नई बात यह हुई कि इन मतभेदों पर चर्चा मीडिया के सामने शुरू हो गई। चूंकि बातचीत वाइट हाउस में हो रही थी, इसलिए स्वाभाविक ही इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर आ जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद भी उसी समय इस पूरी नोकझोंक को 'ग्रेट टेलिविजन' करार दिया।

आगे क्या | मकसद चाहे जो भी रहा हो, इस पूरे प्रकरण से दोनों में से कोई भी पक्ष फायदे में नहीं दिख रहा। अमेरिका जो समझौता यूक्रेन के साथ करना चाहता था, वह टल गया। यूक्रेन को भले ही यूरोप का साथ मिलता दिख रहा है, अमेरिकी समर्थन के बगैर उसका इस युद्ध में टिकना मुश्किल है। ऐसे में बहुत संभव है कि देर-सबेर दोनों फिर बातचीत की टेबल पर आएं। बेहतर होगा कि इंतजार में ज्यादा वक्त और जिंदगियां न बर्बाद की जाएं।

ऑफ़बीट

वह हारकर भी हीरो

सौरभ श्रीवास्तव

वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो हुआ, उससे दुनिया दो हिस्सों में बंटती दिख रही है। ऐसा ही एक वक्त था जब दुनिया दो ध्रुवों में बंटी थी और दोनों ध्रुवों के नुमाइंदों अमेरिका और USSR (अब रूस) की सारी बौद्धिक ताकत शतरंज के 64 खानों पर सिमट आई थी। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था, जिसने हारने के बाद अमेरिकी खिलाड़ी बॉबी फिशर की तारीफ की और उनसे हाथ मिलाया। मैच हार कर भी रॉजेश को हराने वाले यह खिलाड़ी थे, बोरिस स्पास्की। 88 साल के स्पास्की ने हाल ही में दुनिया को अलविदा कहा।

बात सत्तर के दशक के शुरुआती सालों की है। कोल्ड वॉर चरम पर थी। सितंबर 1972 में आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक में खेला गया 'मैच ऑफ द सेंचुरी'। मैच में फिशर ने स्पास्की को हराकर शतरंज से रूसी आधिपत्य खत्म किया। फिशर ने स्पास्की को हराने के लिए चेस बोर्ड से इतर कई पैतरों का इस्तेमाल किया। जैसे पहले दिन वह जानबूझ कर देर से पहुंचे। एक गेम स्थगित करवा दिया। तीसरा गेम तय हॉल के पीछे एक छोटे से कमरे में खेला। यहां तक आरोप लगाया कि मुझे डिस्टर्ब करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल किया गया। जांच हुई तो कुछ भी साबित नहीं हुआ। मैच वाले कमरे से सिर्फ दो मरी हुई मक्खियां मिलीं। इस पर एक अमेरिकी अखबार ने खबर प्रकाशित की कि उन दो मक्खियों को किसने मारा और क्यों? इस हद तक के सतही दांव-पेच इस्तेमाल करने के बावजूद स्पास्की, फिशर के प्रति शालीन रहे। मैच हारने के बाद फिशर की तारीफ करने के लिए सरकार ने दो साल तक उनकी हवाई यात्राएं बंद कर दीं। अपने देश में स्पास्की पर कई आरोप लगे। इससे ऊबकर स्पास्की ने फ्रांस की नागरिकता ले ली और पैरिस में बस गए। हालांकि 2012 में वह वतन लौट आए।

स्पास्की 1969 से 1972 तक तीन साल शतरंज के विश्व चैंपियन रहे। फिशर से हारने के बाद यह खिताब उनसे छिन गया। स्पास्की चाहते तो फिशर के गलत तौर-तरीकों को हार की वजह बता कर रूसी लॉबी के साथ खड़े हो जाते। लेकिन हार के बाद स्पास्की ने स्वीकारा कि फिशर मैच में मुझसे बेहतर खिलाड़ी थे। तमाम दबावों के बावजूद स्पास्की हमेशा खेल के पक्ष में रहे।

एकदा

सफलता का जुनून

हेनरी फोर्ड का सपना ऐसी कार बनाने का था, जो चलाने में आसान, टिकाऊ और आम आदमी की पहुंच में हो। उस समय तक कारें बहुत महंगी होती थीं और केवल अमीर ही उनमें चल सकते थे। फोर्ड चाहते थे कि कारों को तेजी से, सस्ते में और बड़े पैमाने पर बनाया जाए। 1 अक्टूबर 1908 को फोर्ड मोटर कंपनी ने मॉडल टी कार लॉन्च की। शुरुआत में मॉडल टी कार की कीमत 825 डॉलर थी। फोर्ड ने इसे और सस्ता बनाने और

अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाकर दोगुनी कर देने का ऐलान किया। यह बात चारों तरफ फैल गई और फोर्ड की आलोचना होने लगी। निवेशक उन पर संदेह करने लगे। इस प्रोजेक्ट में असफल होने का मतलब था बिजनेस तबाह हो जाना, लेकिन हेनरी फोर्ड ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। साल 1913 में Assembly Line तकनीक को अपनाया। इस तकनीक से छह गुना तेजी से कारें बनने लगीं। उत्पादन बढ़ने से लागत घटी और 1925 तक मॉडल टी की कीमत 260 डॉलर रह गई। 1927 में फोर्ड ने डेढ़ करोड़ से भी ज्यादा कारें सड़क पर उतार दीं। हेनरी फोर्ड की मॉडल टी केवल एक कार नहीं, बल्कि औद्योगिक क्रांति थी। इसने दुनिया को सिखाया कि इनोवेशन, लागत नियंत्रण और मास प्रॉडक्शन से कोई भी चीज आम जनता की पहुंच में लाई जा सकती है।

संकलन : **दिलीप लाल**

यूरोप चाहता है कि रूस का व्यवसाय और गैस पाइपलाइन बरबाद हो, आतंकी उसे निशाना बनाएं

यूक्रेन जंग क्यों जारी रखना चाहती है EU

आशीष शुक्ला

यूरोप में एक देश रोमानिया है। क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से कम, जनसंख्या करीब 2 करोड़। रोमानिया यूरोप में एक खास मामले में सबसे ऊपर है। नैटो (NATO) उसे जर्मनी से भी बड़ा मिलिट्री बेस बनाने में लगा है। अमेरिका और ब्रिटेन समुद्र के रास्ते पिछले तीन सालों से वहां हथियार पहुंचाते रहे हैं। यही हथियार रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करते हैं। NATO और रूस एक-दूसरे के आमने-सामने ना पड़ जाएं और यूक्रेन युद्ध फैल न जाए, यह सुनिश्चित करने में रोमानिया काम आता है।

तुरुप का पत्ता | अगर आप रोमानिया के मैप पर निगाह डालें तो देखेंगे कि NATO का यह मिलिट्री बेस क्राइमिया की बिलकुल नाक की सीध में पड़ता है। यानी रूस के दक्षिण में जो ब्लैक सी है, उसमें NATO का यह बेस पश्चिमी देशों के लिए एक तरह से तुरुप का पत्ता है। ब्लैक सी पूरे इतिहास में रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहीं से मध्य एशिया पर भी रूस की पकड़ मजबूत होती है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देश रूस के प्रभाव क्षेत्र में ही हैं।

ब्लैक सी की राह | रूस के बंदरगाह कड़ाके की सर्दी में बंद रहते हैं, पर वह ब्लैक सी के बंदरगाह से पूरे विश्व में व्यापार कर सकता है। आज की बात करें तो रूस की बीसियों गैस पाइपलाइनें यहां से जाती हैं। यानी रूस का पूरा ढांचा ब्लैक सी के बगैर गिर सकता है। इसलिए जब रूस की कैथरिन द ग्रेट ने 1783 में ऑटोमन एंपायर से क्राइमिया जीता, तो वह रूस के इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण घड़ी थी।

नैटो की राजनीति | अब घड़ी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। पिछले 25-30 सालों में ब्लैक सी के आसपास जितने भी देश हैं, NATO ने उन्हें एक तरह से अपने आप में शामिल कर लिया है, सिवाय यूक्रेन और जॉर्जिया के। जॉर्जिया में जब 2008 में तख्तापलट की कोशिश हुई, तो रूस ने हस्तक्षेप किया। ऐसे ही जब यूक्रेन के NATO में शामिल होने की बात गरमाई तब भी वह खुद को नहीं रोक सका। रूस ने तीन साल पहले अपने सैन्य दल के साथ यूक्रेन में प्रवेश किया।

रोमानिया के चुनाव | रोमानिया में पिछले नवंबर में चुनाव का पहला चरण हुआ। दूसरा चरण दिसंबर में होना था। पहले चरण के नतीजे अप्रत्याशित थे। Calin Georgescu से कोई उम्मीद नहीं थी पर उन्हें सबसे ज्यादा 23% वोट मिले। इस प्रत्याशी का चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण वादा यह था कि वह रोमानिया को ना तो NATO और ना ही रूस की तरफ झुकने देंगे।

खतरे की घंटी | यह तो खतरे की घंटी थी। रोमानिया का जो इस्तेमाल NATO या अमेरिका कर रहे थे, उसमें व्यवधान आ सकता था। वहां हथियार भेजने पर रोक लग सकती थी। रूस की ब्लैक सी में घेराबंदी खटाई में पड़ सकती थी। यही नहीं, रूस के व्यवसाय और गैस पाइपलाइन पर अड़ंगा लगाने का मौका हाथ से निकल सकता था।

पलट गए नतीजे | इसलिए इन शक्तियों ने कदम उठाया। आरोप यह लगाया गया कि रोमानिया के इस प्रत्याशी को बाहर से फंड किया गया है। ऐसे ही डॉनल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के लिए चुनाव जीतने पर कहा गया था कि रूस ने फंड किया है। इसी आधार पर रोमानिया के सुप्रीम कोर्ट ने पहले चरण के नतीजों को खारिज कर दिया। और तो और, Calin Georgescu भी हिरासत में ले लिए गए।

यूरोप की राह | इन सब तारों को जोड़ें तो समझ में आएगा कि यूरोप किसलिए हर हाल में यूक्रेन युद्ध को चलने देना चाहता है। वह किसी भी हालत में ब्लैक सी में रूस को दबोचना चाहता है। वह चाहता है कि उसका व्यवसाय और गैस पाइपलाइन बरबाद हो, आतंकवादी उसे निशाना बना सकें। मध्य एशिया उसके प्रभुत्व से जाता रहे। इसलिए जब अमेरिका भी यूक्रेन से पल्ला झाड़ने के लिए तैयार है, यूरोपियन यूनियन इसके लिए तैयार नहीं है। भले ही इसके लिए उसे अमेरिका से विपरीत राह अपनानी पड़े।

डीप स्टेट की जड़ | सवाल है कि यूरोपियन यूनियन क्यों लड़ाई जारी रखना चाहती है? दरअसल, यूरोप के नेता जिस तरह से गद्दी संभालते हैं, वह एक प्रॉसेस है। ये नेता छोटी उम्र से वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम (WEF) के चहेते बन जाते हैं। इस फोरम को ही डीप स्टेट माना जाता है। यहीं से वे नेता तैयार किए जाते हैं जो आगे जाकर अपने देश में गद्दी संभालें। बाद में वे वही करते हैं जो डीप स्टेट चाहता है। और डीप स्टेट की जरूरत इस समय यूक्रेन लड़ाई को जारी रखने की है। अगर रूस जीत गया, तो डीप स्टेट की जड़ें हिल जाएंगी। यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जो ताना बाना बुना है, वह बिखर जाएगा।

(लेखक ने यूक्रेन लड़ाई पर यह किताब- Russia Forever, a Future Foretold लिखी है)

रोटी के जादू ने इंसानों को बांध दिया

AI Image

जीवन आनंद
शैलेंद्र पांडेय

कोई कुछ भी कहे, लेकिन आखिर में सारा सवाल दो वक्त की रोटी का ही रह जाता है। सारी मेहनत इसीलिए और सारा झगड़ा इसी का। इंसानों ने रोटी बनाई या रोटी इंसानों की किस्मत में आ गिरी? Sapiens के लेखक युवाल नोवा हरारी ने जिस तरह लिखा है, उससे लगता है कि रोटी के गार्जियन गेहूं ने इंसानों को चुना। शुरुआत में दोनों ही जंगली थे। इंसानों को पसंद था खानाबदोश जीवन। एक से दूसरी जगह घूमते रहना, जो मिले उसे खा लेना। फिर उसका गेहूं से मिलना हुआ। गेहूं ने उसे मिलवाया रोटी से। रोटी का स्वाद जो एक बार चढ़ा, तो फिर इंसान की फितरत बदल गई। उसके पैर ठहर गए। गेहूं को वह जंगलों से निकाल अपनी बस्तियों में ले आया। जंगल काटे, खेत बनाए, बुआई, निराई की। करीब 10 हजार या कुछ अनुमानों के मुताबिक 12 हजार साल पहले यह सब शुरू हुआ और तब से चला ही जा रहा है। जिस चीज ने इंसानों को एक जगह से बांध दिया, वह थी रोटी। गर्म, नर्म और सोंधी सुगंध वाली रोटी, जिसके स्वाद ने इवॉल्यूशन का एक नया चैप्टर लिखा।

गेहूं से शुरू होकर थाली में पहुंचने तक, रोटी आटे और पानी का मिश्रण भर नहीं, यह जीवन की लय है। जब आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथा जाता है, तो उसमें हाथों का स्पर्श एक अनकही आत्मीयता जोड़ देता है। आटे को हाथ सहलाते हैं, दुलारते हैं और लचीला बनाते हैं ताकि वह आने वाली परीक्षा को पास कर सके। यह परीक्षा शुरू होती है चौका और बेलन के बीच दबकर एक नया आकार पाने से। रोटी बेलना कला है। इसके लिए चाहिए धैर्य और अभ्यास। इसमें भी गोल रोटी बेल लेना एक सिद्धि है, और इसे साध लेना किसी महारत को हासिल कर लेने जैसी ही खुशी देता है। हालांकि अभी खुशी अधूरी ही है। अभी तो इसे फूलना है, भाप भरनी है इसमें।

आटे को बेलकर जब उसे तवे पर डाला जाता है, तब उसमें पकने की प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे इंसान अपने अनुभवों से परिपक्व होता जाता है। अनुभव जीवन को परतदार बनाते हैं और आग रोटी को। दोनों ही अपने भीतर कुछ छिपाए रहते हैं, जिसका अहसास बाहर से देखकर नहीं होता। तवे पर सिंकते गीले आटे के भीतर हर फूले हुए बुलबुले की एक कहानी है - श्रम की, प्रेम की और संतोष की। फूलती हुई रोटी प्रतीक है संघर्ष और सादगी की।

रोटी हमें चैलेंज की अहमियत बताती है। आटे में पानी एक निश्चित चैलेंज में होता है। आंच भी होती है चैलेंज में और रोटी को उलटते-पलटते समय भी वक्त का संतुलन बनाए रखना पड़ता है। जल्दबाजी काम बिगाड़ देती है। ज्यादा देर आग के साथ रह गई तो जलने का खतरा और पहले उतार दिया तो कच्चापन। रोटी को फूलते हुए देखना किसी जादू से कम नहीं। यह उस मेहनत और प्यार का प्रमाण है, जो इसे बनाने में लगाया गया। इस क्षण आकर लगता है कि मेहनत सफल हो गई। एक जबरदस्त महक रसोई से निकल पूरे घर में फैल जाती है। यह सब केवल भूख के लिए नहीं है, यह आनंद के लिए है। रोटी केवल भोजन नहीं है। यह जीवन का स्वाद है।

शेयर करें अपने अनुभव
जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं nbtreader@timesofindia.com पर, और सम्भव में लिखें-'जीवन आनंद'

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

कर्तव्यों के बंधन से मुक्ति दिलाता है सच्चा गुरु

नारायणी गणेश

आत्म-विकास की शुरुआत खुद को प्यार करने से होती है। खुद को प्यार करना यानी अपनी चेतना से प्यार। बाकी दुनिया के साथ प्रेम और शांति की शुरुआत भी इसी से होती है। इसे यूं समझिए कि अगर कोई employee creative है, उसका काम में मन लगता है तो वह उस employee से बेहतर है, जो बिना कोई सवाल किए boss की हां में हां मिलाते रहता है। साथ ही, ऑफिस में ज्यादा वक्त बिताकर काम करने का दिखावा करता है।

अगर आप creative employee हैं, आपकी काम में रुचि है तो आप प्रगति करते हैं। भगवद्गीता के संदर्भ में समझें तो, कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि 'समूह (यानी समाज) से पहले व्यक्ति आता है और इसी से मुक्ति का मार्ग खुलता है।' भगवान कृष्ण, अर्जुन के mentor थे। और एक अच्छा mentor वही होता है, जो शिष्य पर समाज का बोझ नहीं थोपता। आध्यात्मिक विमर्श में, जब आप खुद को सांसारिक चीजों से मुक्त कर लेते हैं तो किसी बंधन से नहीं बंधे होते। जो व्यक्ति इस तरह का जीवन गुजारता है, वह अपने अंदर के संघर्ष से उबरते हुए ईश्वर को पा लेता है।

क्या आपने गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए आपसे कुछ करने को कहता है तो वह अपना हित साधना चाहता है। लेकिन अगर कोई सच्चा mentor या गुरु है, तो वह अपने शिष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहेगा। वह शिष्य को समाज के बनाए बंधनों में नहीं बांधना चाहेगा, क्योंकि असल शांति सारे बंधनों से मुक्त होने और आत्मज्ञान पाने से मिलती है।

हाल में लार्सन एंड टुब्रो के S. N. Subrahmanyan और Elon Musk जैसे corporate leaders ने अधिक काम करने पर जोर दिया। लेकिन, उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि अगर उनकी इस मांग की अनदेखी हुई तो इससे उनकी वित्तीय सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आएगी। हो सकता है कि employees उनकी बातें सुनकर अधिक काम करें, तो कुछ समय तक उनकी कंपनियों को अतिरिक्त लाभ हो सकता है। लेकिन, यह कर्मचारियों के हित में नहीं होगा, न ही इससे संबंधित कंपनियों की छवि बेहतर होगी।

एक Zen कहावत भी है, 'अगर रास्ते में बुद्ध मिलें तो उन्हें मार दो, ताकि तुम अपनी खुद की बुद्ध-प्रकृति को अपना सको।' इसका अर्थ है कि हमें अपनी सच्ची पहचान और चेतना से जुड़ना चाहिए, बाहरी चीजों में नहीं उलझना चाहिए। गीता की शुरुआत होती है कर्म पर जोर देने से, लेकिन बाद में इसी ग्रंथ में लिखा है कि जब सभी कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं, तब मुक्ति मिलती है। सच्चे गुरु का यही दायित्व है।

सोशल मीडिया के जाल से कैसे बचें

मृत्युंजय राय

कम्युनिकेशन टेक्नॉलजी के ऐसे नतीजे भी हो सकते हैं, जिनके बारे में सोचा न गया हो। निकोलस कार (Nicholas Carr) इस विषय पर पहले भी किताब लिख चुके हैं। लेकिन यहां हम उनकी जिस हालिया किताब का जिक्र कर रहे हैं, उसका नाम थोड़ा चौंकाने वाला है. नाम है सुपरब्लूम (Superbloom)। किताब का नाम सुनकर नहीं लगता है कि यह कम्युनिकेशन टेक्नॉलजी पर होगी। लेकिन इसमें दी गई एक घटना से नाम के पीछे की कहानी सामने आ जाती है। कहानी 2019 की है, लॉस एंजिलिस के वॉकर केन्यन (Walker Canyon) की। यहां की पहाड़ियों पर तब अफीम के पौधों पर नारंगी रंग के फूल खिले, जो आमतौर पर लाल, पीले, सफेद या गुलाबी होते हैं। खबर फैली तो यहां सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स का रेला लग गया। फिर उनके फॉलोअर्स भी आने लगे। निकोलस लिखते हैं कि फूलों का सुपरब्लूम इस तरह से लोगों के सुपरब्लूम में बदल गया, जिसकी कीमत पौधों ने पांवों तले रौंदे जाकर चुकाई। उनके मुताबिक, वॉकर केन्यन के इन पौधों की तरह सोशल मीडिया भी खूबसूरत दिखता है। लेकिनइन पौधों की तरह ही सोशल मीडिया में भी नशे के तत्व हैं।

AI Image

विचार विंडो

लंबे समय से यह सोच रही है कि आगर कम्युनिकेशन तेज हो तो शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिलती है, सूचनाओं से समझ बढ़ती है। लेकिन क्या यह सोच सही है? सूचनाओं का प्रवाह तेज होने के नुकसान भी हैं। इससे फैक्शनलिजम बढ़ता है। तानाशाह सूचनाओं का दुरुपयोग करते हैं और लोगों को अतिवादी बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। निकोलस ने इस संदर्भ में इटली के गुगलिएल्मो मार्कोनी (Guglielmo Marconi) की मिसाल दी है, जिन्हें लगता था कि रेडियो के आने के बाद युद्ध बंद हो जाएंगे, लेकिन नाजियों ने इसका इस्तेमाल अपना अजेंडा बढ़ाने में किया। निकोलस लिखते हैं कि डिजिटल नेटवर्क्स की वजह से अलग-अलग मीडिया साथ आ गए हैं। इससे संवाद और ब्रॉडकास्टिंग का फर्क मिट गया है। इससे कभी न खत्म होने वाली फीड का कल्चर शुरू हुआ, जो फेसबुक की देन है, लेकिन उसके बाद दूसरे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स ने भी अपनाया।

खैर, इन बातों के लिए टेक्नॉलजी कंपनियों पर इल्जाम लगते रहे हैं। कहा गया कि वे सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं। इसलिए इन कंपनियों को सख्ती से रेग्युलेट करना चाहिए। लेकिन निकोलस मानते हैं कि सिर्फ टेक्नॉलजी कंपनियों पर आरोप लगाने का मतलब है कि इंसान अपनी गलती नहीं मानता। डिजिटल मीडिया ने इंसानी स्वभाव को नहीं बदला है। हां, यह सही है कि वह कुछ भावों को दबाता-उभारता है। इसलिए वह टेक्नॉलजी कंपनियों को तोड़े जाने (आकार छोटा करने के लिए) के खिलाफ हैं। वह कहते हैं कि फिर जो स्पेस बनेगा, उसे दूसरी कंपनियां भर देंगी। उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया नेटवर्क्स से दूरी बनाकर और उनके सीमित इस्तेमाल से ही इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है।

सीखने की तड़प

प्रणव प्रियदर्शी

लड़कियों के निरंतर आगे बढ़ने की कहानी तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन इसका असली मजा तब है, जब हमें इन बढ़ते कदमों के निशान दिखाई दें। ऐसा तब होता है जब किसी खास पहलू पर गौर करने का मौका बनता है। ऐसा ही एक पहलू है विमिन प्रफेशनल्स के अंदर करियर में आगे बढ़ने की अंगड़ाई लेती आकांक्षाएं। इसका सबूत है करियर अपग्रेडेशन के लिए तरह-तरह के कोर्स कराने या प्रशिक्षण देने वाले कार्यक्रमों में उनकी बढ़ती भागीदारी। कोर्सेरा (Coursera), अपग्रैड (Upgrad), सिंपलीलर्न (Simplilearn), एमेरिटस (Emeritus) और न्यूटन स्कूल (Newton School) जैसी तमाम कंपनियां उनके यहां उपलब्ध कोर्सों में विमिन प्रफेशनल्स की बढ़ती भागीदारी का गवाह बन रही हैं। यह बढ़त दोनों स्तरों पर दर्ज की जा रही है- अन्य देशों के मुकाबले भी और भारत में ही पिछले सालों के मुकाबले भी। मिसाल के तौर पर, एमेरिटस के आंकड़े बताते हैं कि पिछले दो वर्षों में दुनिया के अन्य हिस्सों के मुकाबले भारत में कंपनी ने विमिन एनरोलमेंट में दोगुनी बढ़त देखी और सिंपलीलर्न प्लैटफॉर्म पर विमिन एनरोलमेंट में 2023 के मुकाबले 78 फीसदी इजाफा हुआ है। इन कंपनियों से जुड़े लोगों से बात करें तो यह तथ्य सामने आता है कि विमिन प्रफेशनल्स के बीच अपनी मौजूदा भूमिका में अन्य सहकर्मियों से आगे रहने और संभावित अवसरों का लाभ उठाने की भावना काफी जोर पकड़ रही है। यही वजह है कि वे नए-नए कोर्सों के जरिए अपने स्किल्स को अपडेट करने में पीछे नहीं रहना चाहतीं। खास बात यह कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग से जुड़े कोर्सों में भी 2023 के मुकाबले विमिन एनरोलमेंट में 100 फीसदी इजाफा हुआ है।

AI Image

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ **वैज्ञानिक तरीका अपनाएं** | **1 मार्च** को प्राकृतिक खेती करने वाले सुभाष खेतुलाल शर्मा का इंटरव्यू 'बिना केमिकल के उपज होती है कई गुना' पढ़ने को मिला। इसमें जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की उर्वरता, गिरते भूजल स्तर और पेड़ों की उपेक्षा को रेखांकित किया गया है। किसान वैज्ञानिक सोच अपनाएं, तो खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सकता है। सरकार और व्यापारिक हितों के कारण किसानों का शोषण बढ़ा है, जिससे खेती में उतना लाभ नहीं मिल पाता है।

रोहित शर्मा, ईमेल से

■ **सफलता का राज** | **जीवन आनंद** कॉलम में 24 फरवरी को 'इंतजार कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा' शीर्षक से प्रकाशित लेख धैर्य, संघर्ष और सही समय पर सफलता मिलने की गहरी सचाई को उजागर करता है। हर व्यक्ति और चीज का एक सही समय होता है, और जब वह आता है, तो उसकी खुशी का आनंद ही अलग होता है। चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी और बीज बनने की उपमा दर्शाती है कि असली सफलता धैर्य और तैयारी के बाद ही मिलती है। इंतजार केवल समय बिताने की प्रक्रिया नहीं, खुद को निखारने का अवसर है।

जीवन आनंद के बड़ा वृक्ष

पुरुषोत्तम प्रसाद, गुड़गांव

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

मीडिया के सामने झगड़ते रहे ट्रंप और जेलेंस्की - एक खबर
- इन दोनों में मध्यस्थता के लिए पूतिन को बुलाया जाए।

पूर्णिमा रावत

[illegible]

8,715 नए नागा संन्यासी मिले अलग-अलग अखाड़ों को प्रयागराज महाकुंभ के दौरान, जबकि 1,850 दलित और आदिवासीजन भी इसी परंपरा में दीक्षित हो गौरवशाली परंपरा का अंग बने।

सिद्धार्थ मिश्र
एसोसिएट प्रोफेसर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

नैतिक संहिता की आवश्यकता

हालही में एक यूट्यूबर द्वारा दिए गए बयान से उपजे विवाद के चलते इंटरनेट मीडिया की सामग्री को विनियमित करने पर भी चर्चा हो रही है। ऐसे में लक्षणों को मूल कारण पर हावी नहीं होने देना चाहिए और असल मुद्दे से निपटने को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लिहाजा 'बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा' इस प्रश्न को एक क्षण के लिए अलग रखते हुए, वर्तमान में नैतिकता को परिभाषित करना और समाज में नैतिक आचरण के आदर्श को स्थापित करना विचारणीय विषय है

प्रतीकात्मक

बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान एक यूट्यूबर द्वारा यौन अंतरंगता से संबंधित कंटेंट से समाज के एक वर्ग की नैतिक भावना आहत हुई। उसके बयान की नैतिकता या अनैतिकता पर बहस जारी है। नैतिक सापेक्षतावाद यह मानता है कि नैतिकता किसी विशेष समय में किसी समाज द्वारा पालन किए जाने वाली मूल्य प्रणाली पर आधारित होती है। यह स्थान और समय के अनुसार बदल सकती है, यानी जो एक स्थान पर अनैतिक है, वह दूसरे स्थान पर न हो, और जो आज अनैतिक माना जाता है, वह कुछ वर्षों बाद सामान्य हो जाए। भारत भी इस बदलाव का अपवाद नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिनेमा में देखा जा सकता है। पहले जिन दृश्यों को परिवार के साथ देखने योग्य नहीं माना जाता था, वे अब सामान्य हो गए हैं। यदि फिल्में वास्तव में समाज का प्रतिबिंब हैं, तो यह स्पष्ट है कि समाज की रुचियां, आदतें और दृष्टिकोण भी बदल रहे हैं।

इसलिए यह संभव है कि जो बयान आज अनैतिक या आपत्तिजनक लगता है, वह भविष्य में सामान्य माना जाए। सवाल यह है कि जब राज्य द्वारा किसी नैतिक आचरण का स्पष्ट रूप से निर्धारण नहीं किया गया है, तो क्या यह उचित है कि समाज हर व्यक्ति से अपेक्षा करे कि वह स्वाभाविक रूप से नैतिक आचरण को समझे? गंभीर अनैतिक आचरण के मामले में यह अपेक्षा उचित हो सकती है, लेकिन क्या हल्के अनैतिक बयानों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है?

नैतिकता एक अमूर्त अवधारणा है, जो व्यक्ति और समाज के अनुसार भिन्न हो सकती है। अतः जिस प्रकार अवैध कार्यों को कानून बना कर स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, उसी प्रकार नैतिकता को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। अदालतें इस विषय पर तर्क कर सकती हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। यहां इलाहाबादिया के कथन का समर्थन करना या उसे न्यायोचित ठहराना कदापि नहीं है, लेकिन जब नैतिकता का निर्धारण व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर हो, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग स्पष्ट रूप से यह जानें कि क्या नैतिक रूप से स्वीकार्य है और क्या अनैतिक है।

अनैतिकता और गैरकानूनी कृत्य में अंतर होता है। जो कुछ गैरकानूनी है, वह अनिवार्य रूप से अनैतिक भी होता है, लेकिन हर अनैतिक कार्य गैरकानूनी नहीं होता। यह राज्य पर निर्भर करता है कि वह विभिन्न कारकों के आधार पर इसे परिभाषित करे। नैतिकता या मर्यादित आचरण अभी भी व्यक्ति की स्वयं की जानकारी या समझ पर निर्भर है। ऐसे में वह किस बात को नैतिक माने व किस बात को नहीं, स्पष्ट नहीं है। निश्चित ही यह सबकी अपनी अलग पृष्ठभूमि, शिक्षा व संस्कारों पर भी निर्भर करता है और एक सार्वभौमिक संहिता के अभाव में नैतिकता पर सबका अपना अलग सोच व विचार हो सकते हैं।

स्वीकार्य आचरण का पालन : क्या एक सभ्य समाज को पूरी तरह अनैतिक आचरण से मुक्त नहीं होना चाहिए? क्या समाज को नागरिकों के लिए एक नैतिक आचरण का पैटर्न स्थापित नहीं करना चाहिए? और, क्या समाज ने कभी यह प्रयास किया है कि एक ऐसा वातावरण निर्मित हो, जहां लोग एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य आचरण का पालन करें? मात्र कानूनों के माध्यम से समाज में नैतिक आचरण के उद्देश्य को प्राप्त करना व्यावहारिक नहीं लगता। भारत में कानून आमतौर पर निषेधात्मक होते हैं, यानी वे किसी विशेष आचरण को प्रतिबंधित तो करते हैं, पर एक आदर्श आचरण का निर्धारण नहीं करते। कानून यह निर्धारित नहीं करते कि लोगों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, बल्कि वे केवल यह बताते हैं कि क्या आचरण अवैध और दंडनीय है।

यह हास्यास्पद नहीं लगता कि हर नागरिक से अपेक्षा की जाए कि वह कानूनों व नैतिक रूप से सही आचरण को जानता ही हो? जब सरकारी अधिकारियों और पेशेवरों के लिए नैतिक संहिता हो सकती है, तो आम नागरिकों के लिए ऐसा कोई कोड क्यों नहीं होना चाहिए? भले ही वह अनिवार्य न हो कर मार्गदर्शक या प्रेरणादायक ही हो।

ठोस प्रयास : समाज या सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया है। क्या यह माना जाए कि यह कार्य शैक्षिक संस्थानों का है? यदि हां, तो क्या वे इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाए या कर रहे हैं? पूर्व व वर्तमान की स्थिति का आकलन करें तो प्रतीत होता है कि शैक्षिक संस्थाएं भी किसी न किसी कारणवश इस लक्ष्य में असफल ही रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम व सभी कोर्सेस/ उपाधियों में अनिवार्य नैतिक शिक्षा के अभाव और स्कूलों में सभी बच्चों/ छात्रों के अनिवार्य प्रवेश व उपस्थिति न होने के कारण भी जनता में वांछित नैतिक आचरण का अभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है।

इंटरनेट मीडिया का नियमन करना उसे कथित अनैतिक और अवांछनीय सामग्री से मुक्त करने का एक प्रयास हो सकता है। लेकिन क्या यह उपाय ऐसी सामग्री के निर्माण को पूरी तरह रोक सकता है? पर क्या हमारा उद्देश्य इसकी मौजूदगी को नियंत्रित करना मात्र है, या इसे पूरी तरह समाप्त करना है? वर्तमान में इंटरनेट मीडिया माध्यमों की भीड़ व उन पर आती आपत्तिजनक सामग्री के बाढ़ से देश को और विशेषकर युवा पीढ़ी को बचाने हेतु त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

वहीं सरकार को प्रत्येक नागरिक के लिए आदर्श सामाजिक व नैतिक आचरण को परिभाषित करते हुए, एक विस्तृत नैतिक संहिता का निर्माण करना चाहिए व वर्तमान पीढ़ी को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वह उस नैतिक संहिता को अपनाए और उसका पालन करे।

सही और गलत के बारे में जागरूकता का प्रसार

शशांक राय
अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय

स्वतंत्रता की सीमा और सीमा की स्वतंत्रता, दो भिन्न परंतु साथ ही एक दूसरे के पूरक भी हैं। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित सीमाओं की परिधारणा की कल्पना करता है। माना कि ये सीमाएं असीमित नहीं हैं और उन सीमाओं की भी एक सीमा है। उन सीमाओं के बाहर आप आइपीसी (अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता) या अन्य कानूनी प्रविधानों से घायल हो सकते हैं, क्योंकि उन सीमाओं के बाहर मौलिक अधिकारों की ढाल काम करना बंद कर देती है। कहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का कोई मतलब नहीं, जब तक इसमें दूसरों को चुभने वाली बातें कहना या अप्रसन्न करन निहित न हो। पर मुद्दे की बात यह है कि क्या उन चुभने वाले बातों की भी सीमा नहीं होगी?

सीमा को संरचना पर बहस संविधान के साथ ही शुरू हो गई थी। परंतु इंटरनेट मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के दौर में सीमा की समानता पर ही बहस छिड़ गई है। आधुनिक युग का सवाल है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा सबके लिए समान है? कहते हैं कि कोई भी विचार व्यक्ति-विशेष का नहीं, बल्कि दौर का होता है। अगर रणबीर इलाहाबादिया के मन में अभिभावकों के साथ यौन अंतरंगता से संबंधित सवाल आ सकता है तो फिर औरों के दिमाग में भी ऐसे सवाल/ ख्याल आ सकते हैं। उनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो गली-कूचों, क्लबों, पार्टियों में ऐसी बातें करते हों। उनकी बातों को सुनकर कुछ लोग हंसते होंगे, कुछ अनसुना कर देते होंगे, कुछ लोग उनके संस्कारों, माता-पिता पर आलोचना/ तंज करते होंगे, और कुछ लोग अपने जमाने और आज के जमाने के बीच तुलना करने लगते होंगे। अगर कोई सोनू-मोनू ऐसी बातें इंटरनेट मीडिया पर डाल दे तो शायद उसे हटा दिया जाए, परंतु उस पर कोई भी एफआइआर नहीं होती, कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाए जाते। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि इलाहाबादिया की कही हुई बात और सोनू-मोनू की बात में फर्क है। सोनू-मोनू की बात अधिकतम हजार लोगों तक पहुंच सकती है, पर इलाहाबादिया के कंठ से निकली हुई बात दूर तक जाएगी।

यह एक दुखद सत्य है कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो इलाहाबादिया जैसे इन्फ्लुएंसर्स के खुलेपन से बहुतों को इन्फेक्शन फैल सकता है। लिहाजा, इस प्रकार के संक्रमण को फैलने से रोका जाना चाहिए।

तो क्या उन इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुछ ऐसा नहीं करें कि समाज के बड़े वर्ग पर गलत प्रभाव पड़े। अगर इन्फ्लुएंसर्स के कुछ कहने/ करने से इतना प्रभाव पड़ सकता है, तो उन्हें उनकी गलतियों का दंड देने का भी असर दूर तक पहुंचता है। इनके खिलाफ कार्रवाई से समाज में सही और गलत को लेकर जागरूकता फैलती है। पूरे समाज में एक भाव पैदा होता है कि वैसा नहीं करना/ कहना चाहिए था।

तो क्या लोकप्रियता और अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा में विपरीत अनुपात है? क्या समाज को सबक सिखाने के लिए किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करना संवैधानिक है? क्या सफलता-लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ने के साथ मौलिक अधिकारों का दलान होना तय है? जे. एस. मिल का हानि सिद्धांत इस दुविधा को दूर कर सकता है। अपनी पुस्तक 'आन लिबर्टी' में मिल कहते हैं कि सरकार या समाज किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को तब तक सीमित नहीं कर सकता, जब तक कि उस व्यक्ति का कृत्य दूसरों को हानि न पहुंचाए। अब सोनू-मोनू की बातें, चाहे कितनी बुरी-अश्लील क्यों न हों, किसी को हानि नहीं होगी। पर वहीं दूसरी ओर इलाहाबादिया जैसे इन्फ्लुएंसर्स के खुलेपन से बहुतों को इन्फेक्शन फैल सकता है। लिहाजा, इस प्रकार के संक्रमण को फैलने से रोका जाना चाहिए।

खरी-खरी

मेरी पीठ और वो

इंद्रजीत कौर

उन्हें मेरी पीठ पीछे बुराई करने में बड़ा मजा आता है। दरअसल मैं परोपकारी स्वभाव की हूं। उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखती हूं। महानुभाव की तरफ पीठ किए रहती हूं। बस फिर क्या, उन्हें अपना शौक पूरा करने के लिए अच्छा माहौल मिल जाता है। पर बुरा असर यह रहता है कि उनसे नजरें नहीं मिल पाती हैं। कमबख्त, पता नहीं चलता कि नजरें हसीन हैं कि बोरियत वाली, गहरी हैं या उथली, फानीदार हैं या सूखी, सीधी हैं या तिरछी, छोटी है या बड़ी, भोली है या चालाक। चूंकि नजरों से ही दिल का रास्ता निकलता है, इसलिए एक-दूसरे के दिल भी दूर रहते हैं। ऐसे हालात में दिल्लगी तो पूछो मत, धरी की धरी रह जाती है।

ऐसे लोगों के दिल नहीं होते, क्योंकि इस जगह पर दिमाग अपनी जगह बना लेता है। यह जगह यंत्र की तरह काम करती है। इसी दिमागी यंत्र से बातें करना, प्रेम करना, रिश्ते निभाना आदि काम चलता रहता है। ऐसे लोग पीठ विज्ञान में बहुत कुशल होते हैं। ये बखूबी जानते हैं कि पीठ जितनी बड़ी होती है उसके पीछे खड़े होना उतना आसान होता है। छाया अच्छी मिल जाती है। समूह बनाकर बुराई करना और भी ज्यादा आसान होता है। भले ही पीठधरक ने पीठ बड़ी करने में दिन-रात एक किया हो, खुद पीठ पीछे बुराइयां करने में समय और दिमाग न गंवाया हो, कई मजेदार पलों की कुर्बानियां दे हों और पूरी तरह बुद्ध बना हो, लेकिन बुराईकर्ता अपना धर्म नहीं छोड़ता। भोला है वह। क्या करे?

उसे यह अहसास नहीं होता कि वह जितनी मात्रा में बुराई करता है, सामने वाले की पीठ उतनी ही बड़ी होती जाती है। दूसरी तरफ उसकी स्वयं की पीठ छोटी होती जाती है। इतनी कि वह बिंदु तक भी आ जाती है। रीढ़विहीन तो वह पहले से ही रहती है, पर अफसोस कि वह इतना जागरूक नहीं होता कि अपने बारे में भी सोच सके।

सब कुछ जानने के बावजूद पीठधरक तो बेफिक्र रहता है। अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करता रहता है। चूंकि उसे यह भलीभांति पता होता है कि यदि बुराई पीठ पीछे होती है तो शाबाशी भी पीठ पर ही दी जाती है।

पोस्ट

मायावती भी कमाल करती हैं। कभी उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था, पर आज उन्हें किनारे कर दिया। अब अपने भाई आनंद को जिम्मेदारी सौंपी है।
पंकज झा@pankajjha_

ट्रंप-जेलेस्की मुलाकात से एक सबक यह भी निकला है कि कभी अपने प्रमाण हथियार त्यागने नहीं चाहिए। कभी भी नहीं।
राहुल शिवशंकर@RShivshankar

जब मैंने कहा था कि ट्रंप के साथ मुलाकात को मोदी ने बड़े कारगर तरीके से अंजाम दिया तो उस पहलू को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। कल्पना कीजिए कि अगर यह प्रवासियों को भारत भेजने के मुद्दे पर आक्रामकता दिखाते तो क्या स्थिति बन सकती थी। सदानंद धूमे@dhume

कुछ लोग विमानों के मुद्दे पर वायुसेना प्रमुख की तारफ की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन यह तो अच्छी बात है कि कोई तो ऐसी तारफ दिखा रहा है। अगर किसी संकट में दस्तक दी और भारत की क्षमताएं अपर्याप्त साबित हुईं तो यही लोग उन्हें दोष देंगे।
तन्वी मदान@tanvi_madan

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या ट्रंप के साथ तीखी बातचीत के बाद यूक्रेन के लिए अमेरिका की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं?

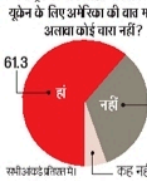

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या लोकसभा परिसीमन को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भय फैलाने का काम कर रहे हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

अमरीका में पी मिली जे रदार फटकार,
लेकिन ब्रेट ब्रिटेन में पाया खूब दुलार।
पाया खूब दुलार मिला उनको आश्वासन,
लड़ो जेलिंस्की आप मिलेगा हमसे राशन!
साथ खड़ा यूरोप मगर सस्ता फीका-फीका,
क्योंकी अब है दूर बाप सबका अमरीका!!
- ओमप्रकाश तिवारी

राकेश पांडेय
संपादकीय प्रभारी, प्रयागराज

हर सनातनी के पास इस महाकुंभ की गठरी

परंपराओं, संस्कारों, अनुष्ठानों और आध्यात्मिक बयार की जीवंतता से परिपूर्ण महाकुंभ का समापन तो हो गया है, लेकिन इस बार इसकी गठरी में पहले से कहीं अधिक स्मृतियां और उपलब्धियां हैं और यह गठरी विश्व के लगभग हर सनातनी के पास है। इस महाकुंभ का संदेश व्यापक और सकारात्मक है कि यदि एक लक्ष्य, एक संदेश और एक उद्देश्य के निर्मल भाव से चला जाए, तो संख्या चाहे जितनी हो, परिणाम सकुशलता और सफलता ही रहता है। पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चले 45 दिनों के इस मेले ने जनसमुद्र का ज्वार ही नहीं देखा, सनातन के प्रति विश्व भर में बढ़ रही विकलता-आकुलता का साक्षी भी रहा। एपल के संस्थापक स्टीव जाब्स की पत्नी लारेन पावेल व अन्य के हाथ में सनातन की धर्मध्वजा इसका प्रमाण है। आस्था के इस महासागरम में श्रीकुंभ जनमस्थान से लेकर सनातन बोर्ड आदि विषयों पर हुआ मंथन भी मायने रखेगा जो आने वाले दिनों में देश में बड़े मुद्दों के रूप में दिखाई दे सकते हैं।

इस सनातनी महासम्मेलन में हर किसी को कुछ मिला। अखाड़ों को 8,715 नए नागा संन्यासी मिले, तो धर्मध्वजा को अपने कंधों पर उठाए सनातन का भाल सदैव उन्नत रखने वाले 1,850 दलित और आदिवासीजन भी इसी परंपरा में दीक्षित हो गौरवशाली परंपरा का अंग बने। फ्रांस की मरियम एवं इटली की बॉबिया को जूना अखाड़े से जुड़ कामाख्या भारती और शिखानी गिरि नाम मिले, साथ ही मिला 1,250 महिलाओं को नागा परंपरा में प्रवेश। किन्नर अखाड़े से कई ईसाई, इस्लामी और यहूदी जुड़े, तो ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर विवाद भी हुआ। तीन नदियों के साथ सेवा की वह धारा भी बही, जिसमें मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी भी आकर धन्य हुए।

प्रयागराज महाकुंभ के नाम अनेक उपलब्धियां दर्ज हुई हैं जो स्वयं में एक कीर्तिमान है। फाइल

धार्मिक परंपरा के पहरुए इस बार उन विषयों को लेकर भी चिंतित दिखाई पड़े जो भविष्य में जनजीवन के लिए संकटकारक हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों को विस्तार देते हुए इस बार सामाजिक सरोकारों पर भी गहन चिंतन एवं विमर्श हुआ और क्रियान्वयन हेतु सहमति बनी। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर कुठाराघात करते लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अभियान चलाने के लिए संकल्पित विश्व हिंदू परिषद द्वारा गोहत्या रोकने के लिए अखाड़ों और धर्माचार्यों के नेतृत्व में एक वृहद अभियान छेड़ने का संकल्प लिया गया। पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ बढ़ती आबादी एवं घटते जल को लेकर भी चिंता दिखी। सामाजिक सरोकारों पर मंथन से इस महाकुंभ में वह अमृत निकला है जो युवाओं में नई चेतना का संचार करेगा।

कुछ अद्भुत रहा इस बार का सनातनियों का जमावड़ा। अगर गणना और कीर्तिमानों को मानक मान जाए तो यह आयोजन वृहद से बृहत्तर होता गया और अपने समापन तक इसने पिछले सभी कीर्तिमान ध्वस्त कर डाले। आस्था और श्रद्धा के 45 दिवसों तक चले इस समागम में जहां 66 करोड़ से ऊपर लोगों ने डुबकी लगाई, वहीं चार हजार हेक्टेयर के विस्तार वाले मेलाक्षेत्र की निगरानी, सुरक्षा, व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं की गणना के लिए अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग किया गया। संगम के तट पर बैठे महात्मा का प्रवचन नीदरलैंड में बैठा भक्त श्रवण कर रहा था और उनसे संवाद कर अपनी जिज्ञासा भी शांत कर रहा था तो यह भविष्य में सनातन की व्यापकता की नई राह है। महाकुंभ के आर्थिक पक्ष की अनदेखी नहीं की जा सकती, जिसने धार्मिक पर्यटन के जरिये प्रदेश को नया आर्थिक संबल दिया है। अर्थव्यवस्था को एक लाख करोड़ डालर के लक्ष्य की ओर बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंच तीर्थों की अवधारणा दे है तो निश्चित रूप से काशी, प्रयागराज, मथुरा, अयोध्या और गोरखपुर अब यूपी की वैश्विक पहचान हैं।

मानव निर्मित हर एक वस्तु नश्वर है, इसका संदेश देते हुए यह महाकुंभ भी चला गया। अधजली लकड़ियां और पक चुकी मिट्टी के चूल्हे इस तथ्य को दर्शाते हैं कि यहां बसा कोई कल्पवासी तपस्वी आधुनिक काल में भी पौराणिक परंपराओं का अनुपालन कर रहा था। मां गंगा प्रसन्नचित हैं कि जो त्रिवेणी स्नान को आया वह वंचित नहीं रहा, विशाल तट इस उपलब्धि से आह्लादित है कि इतने श्रद्धालुओं का बोझ सह सका, वापस लौटते श्रद्धेखुले लोग गंगा का आचमन करते और संगम तट की मिट्टी सिर पर लगाते इस बात का आभार प्रकट कर रहे हैं कि आपने हमारी रक्षा की। कुंभपूर्ति की रस्म निभाते हुए सभी अखाड़े श्रीकाशी विश्वनाथ के दरबार में उपस्थिति लगा चुके हैं और अपने-अपने डेरों की ओर क्रमबद्ध तरीके से वापसी कर रहे हैं। अगला कुंभ भी विशाल होगा, समातनियों से भरा होगा, लेकिन यह निश्चित है कि जहां महाकुंभ के आगमन से समापन तक की रोचकता चिरकाल तक जन-जन की स्मृतियों में रहेगी, वहीं तीर्थराज प्रयाग के निवासियों का अतिथ्य और हृदय की विशालता भी किस्से-कहानियों के रूप में चिरकाल तक वर्णित की जाएगी।

सतीश चंद्र श्रीवास्तव
संपादकीय प्रभारी, रायपुर

छत्तीसगढ़ डायरी

फूलने से पहले फूट गए गुब्बारे

प्रदेश के रजत जयंती वर्ष का बजट सोमवार को पेश हो जाएगा। वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 'मोदी का संकल्प' अब 'अटल विश्वास पत्र' पर आगे बढ़ेगा। प्रदेश की जनता के लिए गरीब कल्याण, किसान हित, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा सुधार और अधोसंरचना विकास जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के समक्ष विकास के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब तीनों स्तर पर भाजपा की सरकार है। ट्रिपल इंजन सरकार। स्थानीय निकायों, राज्य और केंद्र में तालमेल वाली व्यवस्था बन चुकी है। कल से नए मुद्दे सामने होंगे और अबतक चर्चा के केंद्र में रहे मामले नेपथ्य में जाने लगेंगे। यद्यपि पिछले एक सप्ताह में जिस तरह छोटे शहरों के मुद्दे अंडर करंट के साथ अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में विस्तारित होने लगे, व्यवस्था को सतर्क होने का संदेश दे गए हैं। अफवाहों पर नियंत्रण संभव नहीं भी नहीं की जा सकती। प्रशासन द्वारा तत्पर कार्रवाई करके प्रभाव को सीमित अवश्य किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर प्राप्त विदेशी फंड का प्रयोग मतांतरण के लिए किए जाने की आशंका जताए जाने और जांच की घोषणा के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। यह अवश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर यूएसएड के दुरुपयोग की आशंका के बाद आया था। ट्रंप का मानना है कि भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए उक्त धन का उपयोग हो रहा था। विदेशी सहायता लेने वाले प्रदेश के 150 से अधिक स्वयंसेवी संगठनों में 50 से अधिक घोषित तौर पर ईसाइयों द्वारा संचालित है। सभी के विरुद्ध केंद्र और राज्य की एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। मामला गर्म ही था कि ईसाई संगठनों ने गो हत्या के विरुद्ध एक मार्च को हिंदू संगठनों की रैली के आह्वान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठा दिया। ईसाइयों की सामूहिक हत्या और ईसाई महिलाओं पर अत्याचार का षड्यंत्र करार दिया। प्रदर्शन रोकने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशों के ईसाई संगठनों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेजे। दक्षिण भारत के राज्यों के ईसाई संगठन भी सक्रिय हो गए। प्रशासन ने तत्परता दिखाई तो ईसाई संगठन शांत हुए। गो हत्या नहीं करने का भरोसा दिया। हिंदूवादी संगठनों ने एक मार्च को आधार रैली निकाली और कोई हादसा भी नहीं हुआ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 14 मार्च तक गो हत्या के विरुद्ध ठोस व्यवस्था नहीं होने पर आंदोलन का आह्वान कर रखा है।

महाशिवरात्रि के अवसर पर राजिम कुंभ में सभा को संबोधित करते विष्णु देव साय। डीपीआर

दूसरी कहानी रायपुर से भागकर जयपुर में मुस्लिम युवक से शादी करने वाली सिंधी युवती की रही। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाया तो लड़की की तरफ से जारी वीडियो में लड़के वालों को थाने में नहीं बैठाने, बालिग होने और अपनी मर्जी से शादी का दावा किया गया। रविवार को लड़की वालों की तरफ से एक और वीडियो जारी कर दावा किया गया है कि युवक ने कुछ खिलाकर और सूंघाकर अपने वश में कर लिया, हस्ताक्षर कराए और जबरदस्ती शादी कर ली थी। अब युवती परिवार वालों और पुलिसवालों को धन्यवाद कर रही है। 'लव जिहाद' के विरुद्ध हिंदूवादी संगठनों की आक्रमकता भी अब शांत हो गई है।

इसी तरह की तीसरी घटना मुख्य सचिव अविनाश जैन द्वारा शुक्रवार को सड़क पर पार्टी या लंगर करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी से जुड़ी रही। कुछ दिन पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को सड़क पर बर्थडे पार्टी मनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विपक्ष को मौका मिला और शनिवार से ही महापौर के पुत्र द्वारा 28 फरवरी की रात सड़क पर बर्थडे पार्टी मनाने का वीडियो वायरल होने लगा। पुलिस ने महापौर पुत्र समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर कानून सबके लिए समान होने का संदेश दिया तो रायपुर की महापौर ने माफी मांग संदेश दिया कि कांग्रेसी महापौरों जैसी स्थिति नहीं है जिनके स्वजन कानून व्यवस्था तोड़ते थे और प्रशासन कार्रवाई तक नहीं कर पाता था। इस तरह फूलने से पहले ही गुब्बारे फूट गए।

इसलिए अब बजट चर्चा के केंद्र में होंगे। साथ के समक्ष मोदी की गारंटी के बाद अब "अटल विश्वास पत्र" से सामंजस्य बैठाने की चुनौती है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मोदी की गारंटी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जाने वाली योजनाओं और घोषणाओं को सामने रखा था। अब यह दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार दोनों घोषणाओं को किस तरह लागू करेगी। विशेष रूप से किसानों की कर्जमाफी, महिला सुरक्षा और रोजगार को लेकर किए गए वादों पर जनता की निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय प्रबंधन है। लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच नीतियों के समन्वय पर भी काम करना होगा, ताकि दोनों स्तरों पर विकास योजनाएं सुचारु रूप से लागू हो सकें। मुख्यमंत्री प्रदेश में नई उद्योग नीति लागू होने के बाद 1.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का प्रस्ताव मिलने की बात कर रहे हैं। अगर सात लघु औद्योगिक और चार बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के बाद जमीन पर उतरें तो ही राय नहीं कि न्यूनतम प्रशासन और अधिकतम प्रोत्साहन से अनुकूल माहौल का निर्माण होगा। अंततः समृद्ध छत्तीसगढ़ और सुशासन ही लक्ष्य है।

****

दैनिक जागरण
परिणाम सदैव प्रयास के अनुरूप प्राप्त होता है

सफाई की प्रतीक्षा में यमुना

यह अच्छा तो है कि केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय यमुना को स्वच्छ करने के लिए एक नई योजना को रूपरेखा बना रहा है, लेकिन क्या ऐसी योजना तैयार करने के लिए दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की प्रतीक्षा की जा रही थी। ऐसी कोई योजना तो पहले भी बनाई जा सकती थी। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। क्या यमुना को स्वच्छ करना केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी नहीं थी। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय की पहल पर भले ही यह कहा जा रहा हो कि यमुना को सफाई के काम को एक अभियान का रूप दिया जाएगा और उसे एक निश्चित समयसीमा में स्वच्छ किया जाएगा, लेकिन इस पर भरोसा करना इसलिए कठिन है, क्योंकि यमुना केवल दिल्ली में ही प्रदूषित नहीं है। दिल्ली में प्रवेश करने के पहले ही वह प्रदूषित होनी शुरू हो जाती है। दिल्ली से लगते हरियाणा के इलाकों में कई कारखानों का बिना शोधित जल उसमें डाला जाता है। आखिर हरियाणा सरकार अपनी सीमा में यमुना को प्रदूषित होने से बचाने के अपेक्षित उपाय क्यों नहीं कर सकी।

यह ठीक नहीं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान यमुना की सफाई का एजेंडा राज्य और केंद्र के झगड़े में उपेक्षित बना रहा। नदियों को साफ-स्वच्छ करने को दलगत राजनीति का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि अपने देश में अधिकांश नदियां बुरी तरह प्रदूषित हैं। उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने में न तो राज्य सरकारें सफल हो पा रही हैं और न ही केंद्र। स्थिति यह है कि नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए आवश्यक बुनियादी काम भी नहीं हो पा रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि नदियों के किनारे पर्याप्त संख्या में सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित नहीं किए जा सके हैं और जो हैं भी, उनमें से अनेक पूरी क्षमता से काम नहीं करते। इस मामले में नगर निकायों का काम बेहद असंतोषजनक है। यही स्थिति प्रदूषण रोधी एजेंसियों की भी है, क्योंकि कल कारखानों को भी विषाक्त जल नदियों में छोड़ने से नहीं रोका जा पा रहा है। इसका मूल कारण नौकरशाही की लापरवाही और सरकारों की ओर से राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय न दिया जाना है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि गंगा को भी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं किया जा सका है। गत दिवस ही बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया कि राज्य में गंगा का जल स्नान के योग्य नहीं है। जब देश की सबसे प्रमुख नदी की यह स्थिति है तो इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि अन्य नदियों का क्या हाल होगा। उचित यह होगा कि राज्य और केंद्र सरकार, नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के आश्वासन देकर कर्तव्य की इतिश्री न करें और यह समझें कि नदियों को साफ-स्वच्छ रखने का काम संतोषजनक नहीं।

जनाकांक्षा का दबाव

उत्तराखंड में दायित्व का निर्वहन नहीं करने वाले सरकारी कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। विभाग ऐसे कार्मिकों को चिह्नित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह को इस संबंध में कड़ा रवैया अपनाते हुए उच्चाधिकारियों को निर्देश जारी करने पड़े हैं। यद्यपि, कार्मिक विभाग की नियमावली में अक्षम या निरंतर लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का प्रविधान है। वह अलग बात है कि इस नियम के क्रियान्वयन में सख्ती से बचने की हरसंभव कोशिश की जाती है। सरकार ने रवैये में परिवर्तन के संकेत दिए हैं तो जनाकांक्षा के बढ़ते दबाव को समझा जा सकता है। मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। विशेष रूप से विकास एवं निर्माण कार्यों को विषम भौगोलिक परिस्थितियों में समय पर पूरा करना है तो इसके लिए पूरे तंत्र को अनुशासित, नियोजित होने की आवश्यकता है। इसका दायित्व सरकारी कार्मिकों पर सर्वाधिक है। इस तस्वीर का एक पहलू यह भी है कि प्रदेश में कार्मिकों के वेतन, भत्ते मद में हर वर्ष जितनी धनराशि खर्च हो रही है, उससे काफी कम राशि पूंजीगत कार्यों के लिए बच रही है। विकास कार्यों की अपेक्षाकृत कम धनराशि का समय पर सदुपयोग नहीं होने और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आमजन तक नहीं पहुंचने की स्थिति में राज्य की कठिनाइयां बढ़ेंगी। सरकार के इन निर्देशों के बाद उम्मीद है कि यह महत्वपूर्ण मानव संसाधन अपने दायित्व बोध को लेकर सचेत होगा। कर्तव्य के प्रति उदासीन कार्मिकों को कर्मचारी संगठनों का समर्थन नहीं मिलना चाहिए।

> सरकारी कर्मचारी अपने नियमित कार्यों को लेकर जितना सजग होंगे, उतना ही सुशासन का लाभ आम नागरिक तक पहुंचेगा

संवैधानिक संस्था की अनदेखी

हृदयनारायण दीक्षित

केजरीवाल सरकार ने कैग रिपोर्ट पर संवैधानिक दायित्व की उपेक्षा की। संभव है कि रिपोर्ट को सदन में न रखने की योजना सोच-समझकर बनाई गई हो

दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी आप सरकार की विदाई के बाद कैग की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखने के बाद कई आशंकाएं सही साबित हुई हैं। कैग की रिपोर्ट पूर्ववर्ती सरकार की शराब नीति से लेकर मोहल्ला क्लीनिकों और शासन के कई स्तरों पर चलने वाली योजनाओं पर सवाल उठाती हैं। वस्तुतः आप सरकार ने कैग की रिपोर्ट सदन में रखने के संवैधानिक दायित्व की उपेक्षा की। संभव है कि रिपोर्ट को सदन में न रखने की योजना सोच-समझ कर बनाई गई हो। अतीत में भी कैग की रिपोर्ट खलबली मचाती रही हैं। कैग के कामकाज का यशस्वी इतिहास है। बोफोर्स तोप घोटाला कैग रिपोर्ट के कारण ही राष्ट्रीय मुद्दा बना। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की पोल कैग ने ही खोली। कोयला घोटाला कैग की रिपोर्ट से गंभीर मुद्दा बना। 1962 की कैग रिपोर्ट में जीप खरीदने को लेकर तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन भी फंस गए थे। राष्ट्रमंडल खेल आयोजन पर कैग रिपोर्ट से सत्तारूढ़ दल परेशाने में था। यह किसी से छिपा नहीं कि सार्वजनिक धन के अपव्यय या गलत तरीके से इस्तेमाल करने से राष्ट्र को क्षति होती है। भारी भ्रष्टाचार होता है। शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार सामने आने से अंतरराष्ट्रीय बदनामी भी होती है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 148 के अनुसार कैग और संसद भारत के सार्वजनिक धन के उपयोग के परेरेहार हैं। कैग देखता है कि देश की संचित निधि का व्यय संविधान एवं कानून के अधीन ही हुआ है। कैग की रिपोर्ट का विवेचन लोक लेखा समिति द्वारा होता है। समिति में सत्तापक्ष एवं विपक्ष, दोनों के सांसद होते हैं। कैग की रिपोर्ट को नजरअंदाज करना आसान नहीं। यह शक्तिसंपन्न संवैधानिक संस्था है। डा. आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान में शायद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में देखते हैं। संसदीय परंपरा में कैग को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक बताया गया है।

भारत में लोक लेखा परीक्षण विधान की स्थापना 1853 में ही हो गई थी। स्वतंत्र संस्था के रूप में इसे 1919 के अधिनियम से आकार मिला। इसकी नियुक्ति भारत सचिव द्वारा होती थी। भारत शासन अधिनियम 1935 से उसके अधिकारों को और ज्यादा शक्ति मिली। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने कैग की शक्ति का संवर्धन किया। देसी रियासतों के भारतीय संघ में विलय के बाद कैग का उत्तरदायित्व पूरे देश में व्यापक हो गया। 1950 में संविधान में महालेखा परीक्षक का नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा गया। इंग्लैंड में यह एक महत्वपूर्ण संस्था है। भारत का कैग महालेखा निरीक्षक है, लेकिन नियंत्रक नहीं है। ब्रिटेन के महालेखा परीक्षक के पास नियंत्रक महालेखा कार्य की शक्तियां भी हैं। भारत में कैग खर्च हुए लोक धन की गहन जांच करता है। वहीं ब्रिटेन का कैग धन के खर्च होने के पहले ही लोक धन का नियंत्रण करता है। ब्रिटेन में कैग की अनुमति के अभाव में राजकोष से कोई पैसा निकाला नहीं जा सकता। भारत का कैग संसद का सदस्य नहीं होता। ब्रिटेन में कैग हाउस आफ कामंस (निचले सदन) का सदस्य होता है। संविधान निर्माताओं ने गहन अध्ययन के बाद ही यह पद गढ़कर इसकी निष्पक्षता सुनिश्चित की। सीएजी को उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को।

अवधेश राजपूत

संविधान में अनेक संस्थाएं हैं। सबके अपने अधिकार और कर्तव्य हैं, लेकिन ऐसे कार्यों के संपादन में समय प्रतिबद्धता का उल्लेख नहीं है। कैग का काम बड़ा है। निर्धारित समय के भीतर कठिन परिश्रम द्वारा ही कार्य संभव है। दिल्ली सरकार के मामले में कैग की रिपोर्ट सदन में नहीं रखी गई। सरकार का यह कृत्य संविधानसम्मत नहीं रहा। कैग वस्तुतः तमाम अंतर्विरोधों से निपटने और लोक धन के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने की जांच करता है। रिपोर्ट बनाता है। समितियों में रिपोर्ट की गहन विवेचना होती है। संवैधानिक संस्थाओं के पदधारकों के लिए कार्य का समय निर्धारित करने में कठिनाइयां आती हैं। उन्हें समयबद्ध करने के लिए कोई संवैधानिक उपचार नहीं है। संवैधानिक नैतिकता और निष्ठा उन्हें समयबद्धता के लिए प्रेरित करती है। ऐसे लोग समय के प्रति जागरूक होते हैं। सब जानते हैं कि महत्वपूर्ण काम समय पर नहीं होते तब व्यापक राष्ट्रीय क्षति होती है। आखिरकार दिल्ली के उपराज्यपाल को रिपोर्ट मिलने और मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट पहुंचने तक अधिकतम कितना समय लगना चाहिए? इसमें महीनों लग गए। अनावश्यक लाभ के लिए जानबूझकर की गई देरी क्षमा योग्य नहीं होती।

लोक लेखा समिति सहित सभी संसदीय समितियां महत्वपूर्ण काम करती हैं। लोक लेखा समिति का काम बड़ा है। समिति कैग रिपोर्ट को संसद में पेश होने के पहले भी देख सकती है। लोकसभा के अध्यक्ष रहे जीवी मावलंकर ने कहा था, 'समिति को उसी समय उनकी परीक्षा करनी चाहिए। इससे उसे काम करने का अधिक समय मिलेगा, लेकिन समिति इस संबंध में सभा को तब तक कोई प्रतिवेदन नहीं दे सकती जब तक कि संगत लेखाओं, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को औपचारिक रूप से सभा के सामने नहीं रख दिया जाता।' हालांकि समितियों की बैठकें पर्याप्त दिनों तक नहीं चलतीं। विधानमंडलों की हालत और खराब है। कहीं-कहीं 8-10 साल पुराने मामले समिति में लंबित हैं। कम से कम संवैधानिक संस्थाओं की पत्रावलियां समयबद्ध गतिशील होनी चाहिए। कई मामलों में दोषी पाए गए लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, पर कार्यवाही नहीं होती। आश्चर्य है कि वरिष्ठ पदधारक भी समय की महत्ता पर प्रायः ध्यान नहीं देते। संवैधानिक संस्थाओं को स्वयं ही समय अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। इस विषय पर संसद या संसद की किसी समिति को गहनता से विचार करना होगा। विलंब के कारण भी सुस्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करने चाहिए।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

आर्थिकी को ताकत देती घरेलू मांग

डा. ऋतीलाल मंडारी

विश्व में टैरिफ युद्ध की बढ़ती आशंकाओं के बीच मध्य वर्ग की क्रय शक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था की नई ताकत बन गई है

इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार से एशिया से लेकर यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं तक हाहाकार मचा हुआ है। कनाडा और मेक्सिको के आयात पर 25 प्रतिशत और चीन के आयात पर भी 10 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने से अमेरिका और उसके सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों के बीच नया व्यापार युद्ध शुरू होने की आशंका है। भारत भी टैरिफ वृद्धि के मद्देनजर अमेरिका के निशाने पर है। इसे लेकर भारत में टेक्सटाइल, दवाई, आटोमोबाइल, इस्पात, एल्यूमीनियम और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में चिंताएं हैं। सेंसेक्स और निफ्टी भी बड़ी गिरावट के दौर में हैं। ऐसे में भारत अमेरिका को उपयुक्त टैरिफ रियायतों के साथ अपनी मजबूत घरेलू मांग को और तेजी से बढ़ाने तथा द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के साथ ट्रंप के टैरिफ वार से मुकाबला करने की डगर पर सुनियोजित रूप से आगे बढ़ रहा है। भारत का उपभोक्ता बाजार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। यह भारत के लिए ट्रंप के टैरिफ से जंग में सबसे मजबूत हथियार है। डेलायट इंडिया और रिटेलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (आरएआइ) के अनुसार भारतीय उपभोक्ता बाजार में जो निजी खपत वर्ष 2013 में 87 लाख करोड़ रुपये थी, वह 2024 में दोगुनी से भी अधिक 183 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई। इनके अनुसार 2026 में भारत बढ़ती खपत के कारण दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा।

निःसंदेह देश के उपभोक्ता बाजार को देश का मध्य वर्ग नई आर्थिक ताकत दे रहा है। आर्थिक सुधारों के साथ ऊंची विकास दर और शहरीकरण के बलबूते भारत में मध्य वर्ग के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हाल में प्रकाशित द राइज आफ मिडिल क्लास इंडिया नामक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मध्य वर्ग के लोगों की संख्या वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 43 करोड़ थी और 2047 तक इसके बढ़कर 102 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इस वर्ग को पांच से 30 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। रिसर्च फर्म कांतार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 तक सालाना 10 हजार डालर से अधिक आय वाले भारतीयों की संख्या तीन गुनी हो जाएगी। यह संख्या 2024 में लगभग छह करोड़ थी, जो 2030 तक 16.5 करोड़ हो जाएगी। निश्चित रूप से टैरिफ युद्ध की बढ़ती आशंकाओं के बीच यह मध्य वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था की नई शक्ति बन गया है। भारत के मध्य वर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति के कारण जहां दुनिया के कई देश भारत से आर्थिक और कारोबारी संबंध बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, वहीं दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां भी भारत के बाजार में दस्तक दे रही हैं।

बढ़ती खपत से आर्थिक वृद्धि को लगते पंख। फाइल

वास्तव में तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत अपनी घरेलू मांग की मजबूती से ही दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। पिछले 10 वर्षों में खपत बढ़ने की दर सबसे अधिक भारत में ही रही है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रही। भारत की यह विकास दर चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे तमाम विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना में अधिक है। हाल में वर्ल्ड बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनमिक प्रास्पेक्ट्स रिपोर्ट में भी भारत की आर्थिकी को निवेश और खपत की दृष्टि से विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी आर्थिकी बताया है। घरेलू मांग और खपत भारत की शक्ति है। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट भी करदाताओं, निवेशकों तथा मध्य वर्ग की खरीदी की क्षमता बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें आयकर में कटौती और कर ढांचे को आसान बनाकर खर्च और बचत को बढ़ाने की कोशिश की गई है। मध्य वर्ग पर कर का बोझ कम करने से घरेलू खपत बढ़ेगी। इससे जीएसटी संग्रह में वृद्धि होगी और कर योग्य आय वालों का आधार बढ़ेगा।

इस समय वैश्विक व्यापार नए सिरे से स्थापित होने जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अब मुख्य स्तंभ के रूप में नहीं बचा है और सबसे तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) के दर्जे के तहत गैर-भेदभावपूर्ण शुल्क खत्म हो रहे हैं। हर देश चाहता है कि उसके साथ विशेष व्यवहार किया जाए। हमें भी इसी रास्ते पर चलना होगा। वैश्विक व्यापार में आ रहे नए परिवर्तन के मद्देनजर भारत को मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाना होगा। इसीलिए भारत द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं और मुक्त व्यापार समझौतों की राह पर तेजी से बढ़ भी रहा है। हाल में भारत और यूरोपीय आयोग के बीच कारोबार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते को लेकर वार्ता हुई है। इस वर्ष के अंत तक इस पर मुहर लगने की उम्मीद है।

चूंकि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और 2047 तक विकसित भारत के लिए 7.8 प्रतिशत विकास दर पाने का लक्ष्य है। ऐसे में भारत को अमेरिका के लिए उपयुक्त टैक्स रियायतों, भारतीय बाजार में तेजी से खपत बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं और मुक्त व्यापार समझौतों के रास्ते पर सुनियोजित रूप से आगे बढ़ना होगा। भारतीय नीति निर्माताओं को ट्रंप प्रशासन की नीतियों से भारत पर होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावों का सतत मूल्यांकन करते हुए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना होगा।

(लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, इंदौर के निदेशक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

समस्या का समाधान

समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होती हैं। समस्याओं से बड़ा शिक्षक कोई और नहीं। यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं तो आप उनका सामना करके और अधिक शक्तिशाली बनेंगे। दैविक, दैहिक और भौतिक ताप जब मनुष्य को चारों ओर से घेर लेते हैं, तब वह उद्वेलित हो उठता है। वह इन तापों से उपजने वाले प्रतिकूल प्रभावों को समस्या की श्रेणी में रख देता है। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों से तभी पार पाया जा सकता है जब हम इनका समाधान खोज लेंगे।

समस्या का समाधान तभी संभव है जब उसके मूल कारण की पहचानकर उसकी तह तक जाया जाए। ऐसा करने में निष्पक्ष भाव से हर बिंदु का बैकलिंक निरीक्षण करना होगा। इसके लिए आवश्यकता होती है सही वस्तुस्थिति को ज्ञात करने की। इस प्रक्रिया में सारी शक्ति और ध्यान मुख्य बिंदु पर ही केंद्रित होना चाहिए, अन्यथा समस्या और भी उलझ सकती है। उस क्षण जरा भी विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से हमें शीघ्र ही समाधान की राह दिखाई पड़ जाएगी।

गंभीर समस्या का समाधान सबसे पहले खोजना चाहिए, न कि उसे कठिन समझकर टालना चाहिए। समाधान मिले तो तत्परता से लागू भी करें, क्योंकि जो समस्या आपके हिस्से में आई है उसका निदान सिर्फ आपका ही दायित्व है। अगर आप इस आस में बैठे रहते हैं कि कोई जादू की छड़ी घुमाकर आपकी समस्या को दूर कर देगा, तो यह सिर्फ आपका भ्रम है। ऐसी विषम परिस्थितियों में कर्मठता, एकाग्रता और दृढ़संकल्प हमारे सच्चे मित्र साबित होते हैं। इनके सान्निध्य में रहते हुए जब हम किसी समस्या को दूर कर देते हैं, तब बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, जो हमें आत्मविश्वास से भर देती है। फिर हर कार्य में अपना शत प्रतिशत योगदान करते हैं। यह सारी प्रक्रिया भविष्य में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु पुख्ता आधार भी बना देती है।

पारुल हर्ष बंसल

खराब जीवनशैली की देन मोटापा

सोनम लववंशी

> अगर थोड़ा समय निकालकर हर दिन व्यायाम करें, संतुलित आहार लें तो मोटापा समेत कई बीमारियों से बच सकते हैं

एक स्वस्थ देश के निर्माण की राह में नागरिकों का मोटापा किस कदर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चिंतित कर रहा है, इसकी बानगी हाल में 'मन की बात' कार्यक्रम में देखने को मिली। आंकड़ों पर गौर करें तो विश्व भर के 250 करोड़ लोग मोटापे से जूझ रहे हैं, जबकि भारत में हर आठवां व्यक्ति मोटापे का शिकार है। यह समस्या केवल बड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रही है। हाल के वर्षों में तो यह समस्या चार गुना तक बढ़ गई है। इसके कारण हृदय रोग, तनाव, मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों की आगाह किया और इससे बचने की सलाह दी है। साथ ही देशवासियों से खाने में तेल की खपत को 10 प्रतिशत घटाने का आग्रह किया है। इस मुहिम के लिए दस नामी-गिरामी हस्तियों को भी अभियान से जोड़ा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, मोटापा एक महामारी बन चुका है, जो हर साल 28 लाख वयस्कों की जान ले रहा है। भारत में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे से जूझ रहे हैं, जिनमें 12 प्रतिशत पुरुष और 40 प्रतिशत महिलाएं बेली फैट से परेशान हैं। आंकड़ों के अनुसार, स्थिति वाकई डराने वाली है। द लैंसेट पत्रिका के अनुसार, भारत में 5 से 19 वर्ष के करीब 1.25 करोड़ बच्चे मोटापे के शिकार हैं, जबकि 1990 में यह संख्या मात्र चार लाख थी। वयस्कों की स्थिति भी कम भयावह नहीं है। 2022 में 4.4 करोड़ महिलाएं और 2.6 करोड़ पुरुष मोटापे से ग्रस्त थे। ग्लोबल ओबेसिटी आब्जर्वेटरी के आंकड़े बताते हैं कि मोटापे से आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। 2019 में जहां यह 2.4 लाख करोड़ रुपये था, वहीं 2030 तक यह 6.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। यह दर्शाता है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो यह समस्या और विकराल रूप धारण कर सकती है।

मोटापे की समस्या खराब जीवनशैली की देन है। अगर हम रोजमर्रा की भागदौड़ में से थोड़ा समय निकालकर व्यायाम करें, तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। इस पूरी मुहिम में खानपान की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत का भोजन हमेशा से वैज्ञानिक रूप से संतुलित रहा है, लेकिन पिज्जा, बर्गर और इंस्टेंट नूडल्स की बढ़ती लोकप्रियता ने इसे हाशिये पर धकेल दिया है। जंक फूड की बढ़ती लत इस समस्या को और जटिल बना रही है। स्वस्थ खाना ही असली खाना है। फिटनेस कोई विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। मोटापे की समस्या केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता पर भी असर डालती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी जीवनशैली में बदलाव लाएं, व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और संतुलित आहार लें।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

जन-मन की आस्था का महाकुंभ

'महाकुंभ का संदेश' शीर्षक से प्रकाशित संजय गुप्त के आलेख में 45 दिनों तक चले प्रयागराज महाकुंभ की विशिष्टताओं को उल्लेखित करते हुए जिस नागरिक अनुशासन की बात की गई है, वह गौरतलब है। महाकुंभ पर दान नहीं लगता यदि दुर्घटना स्थल पर श्रद्धालुओं ने यूपी की योगी सरकार द्वारा बनाई गई व्यवस्था में संयम के साथ सहयोग किया होता। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व अनुमानित 40 करोड़ की संख्या में धीरे-धीरे 25 करोड़ श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी से भी यूपी सरकार की चाक-चौबंद व्यवस्था के बीच तीर्थयात्रियों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन यह संतोषप्रद रहा कि विपक्षी नेताओं की अनर्गल टिप्पणियों के बावजूद योगी सरकार ने अपना मनोबल ऊंचा बनाए रखा। इस पौराणिक महापर्व का साक्षी बनना हर भारतीय मन की आकांक्षा रही। श्रद्धा और आस्था का कोई विकल्प नहीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन में योगी सरकार की नियोजित और सुदृढ़ व्यवस्थाओं के बीच करोड़ों पर्यटकों ने एकता और समरसता का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वह स्तुत्य है। श्रद्धाभाव से आपूरित तीर्थयात्रियों ने पौराणिक महत्व के इस महापर्व को जन-मन की आस्था का महाकुंभ बना दिया। अनेक कीर्तिमान स्थापित करने वाला यह महाकुंभ विश्व का सर्वश्रेष्ठ मानव समागम बन गया। इस महा आयोजन से यह भी सिद्ध हुआ है कि आस्था कभी पत्थर नहीं उछालती, बल्कि मानवता का संदेश देती है। भारतीय धर्म, संस्कृति और आस्था एक-दूसरे के पूरक हैं। वैदिक ऋचाओं में भी एक साथ मिल कर चलने की बात की गई है। आस्था और मानवता का अनुपम संदेश देने वाले इस भारतीय महापर्व से सभी देशों को प्रेरणा लेनी चाहिए।

pandeyvp1960@gmail.com

मेलबाक्स

हिंदी विरोध का विरोध

दैनिक जागरण के दो मार्च के अंक में मुख पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार 'तमिलनाडु के भीतर ही उठने लगी हिंदी विरोध के खिलाफ आवाज' यह स्पष्ट करता है कि राजभाषा और राष्ट्र भाषा हिंदी का विरोध केवल राजनीतिक है और देश के सभी भागों में कोई भाषाई मतांतर नहीं है और सभी भाषाएं सर्वस्वीकार्य हैं। वैसे केंद्र और राज्य सरकारों को हिंदी एवं अन्य भाषाओं के देश के सभी भागों में प्रचलन का विषय छोड़ देना चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंदी भाषाई मानिटरिंग बंद कर देनी चाहिए। यह काम हमारी फिल्म इंडस्ट्री-बालीवुड, दक्षिण भारतीय, बंगाली, भोजपुरी, गुजराती, उत्तर पूर्व फिल्म इंडस्ट्री बेहतर तरीके से कर रही हैं और संपूर्ण देश में भाषाई सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम हैं। जब देश के सभी भागों से सभी भाषाओं को बोलने वाले नागरिक देश के प्रत्येक भाग में नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, पर्यटन, मंदिरों में जाते हैं तो हिंदी का विरोध बिल्कुल तर्कसंगत और स्वीकार्य नहीं है और न इससे कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला है। सभी भागों में लोग काम लायक हिंदी बोल और समझ लेते हैं। बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय दिल्ली और उत्तर भारत के प्रमुख नगरों में रहते हैं। सभी दक्षिण भारतीय भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न हैं। इसलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का हिंदी विरोध निंदनीय है। वहां की जनता को भी उनके राजनीतिक सेच को समझते हुए हिंदी विरोध के उनके रवैये का विरोध करना चाहिए।

विनोद जौहरी, दिल्ली

दिल्ली की बस सेवा

परिवहन मंत्री पंकज कुमार ने दिल्लीवासियों को भरोसा दिलाया है कि इस महीने दिल्ली को एक हजार नई इलेक्ट्रिक बस मुहैया कराई जाएंगी। डीटीसी के पास हाल-फिलहाल 4,536 बसें सड़कों पर हैं। जबकि 1,577 इलेक्ट्रिक बसे उपलब्ध हैं, लेकिन अब 11 हजार बसों की जरूरत है। फिलहाल खराब बसों की दिल्ली में भरमार है। सरकार का अनुमान है कि 2026 तक 3,775 बसें हट जाएंगी। सार्वजनिक परिवहन ढांचा कमजोर होने से लोग निजी वाहनों का उपयोग करने लगे हैं। नई बसें आने से नागरिकों की समस्या दूर जरूर होगी।

कांतिलाल मांडोत, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

हिन्दुस्तान
1936

हिम हादसा

उत्तराखंड के चमोली जिले में माणा के पास भयानक हिमस्खलन दुखद और चिंताजनक है। 54 मजदूर अचानक हिमस्खलन की चपेट में आ गए, पर सौभाग्य से ज्यादातर मजदूरों को बचा लिया गया। भारत-चीन सीमा पर निर्माण-कार्य में लगे इन मजदूरों को बचाने के लिए हुई हर मुमकिन कोशिशों की सराहना होनी चाहिए। तरह-तरह के सवाल पूछे गए, पर ज्यादा जरूरी था बचाव के उपाय करना। ग्लेशियर वाले इलाकों में किसी भी तरह का निर्माण करते हुए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों की वहां उपस्थिति पर भी सवाल उठाए जाएंगे। अतः सड़क निर्माण में लगे लोगों को सुरक्षा के नए इंतजाम रखने पड़ेंगे। सीमा पर जिस तरह का तनाव है, उसमें सड़क-निर्माण जरूरी है, पर इसके लिए क्या कोई सुरक्षित समय या मौसम हो सकता है? सड़क के लिए बहुत जल्दी करने के बजाय मौसम अनुकूल रहते हुए काम पूरा करना चाहिए। यह हादसा संवेदनशील निर्माण से जुड़े लोगों के लिए गंभीरतम चेतावनी है।

हिमस्खलन के मिजाज को समझना होगा। उत्तराखंड के स्थानीय लोग तो फिर भी हिमस्खलन को समझते हैं, पर अक्सर बाहर से आने वाले ग्लेशियर की प्रवृत्ति समझने में नाकाम रहते हैं। हिमस्खलन के दौरान, बर्फ, चट्टान, मिट्टी और अन्य सामग्री का ढेर तेजी से पहाड़ की ढलान से नीचे की ओर खिसकता है। हिमस्खलन में अक्सर भूस्खलन भी शामिल रहता है।

कनाडा, स्विट्जरलैंड के ऊंचे पहाड़ों में विशेष सैन्य टुकड़ियां तैनात होती हैं, जो हिमस्खलनों पर नियंत्रण करती हैं। ऐसी सुविधा भारत में भी बढ़नी चाहिए।

हिमस्खलन तब शुरू होता है, जब बर्फ का एक अस्थिर खंड ढलान से टूटकर अलग हो जाता है। 54 मजदूर नहीं, एक मजदूर भी हिमस्खलन का कारण बन सकता है। यह एक तरह से विशाल हिमखंड का ध्यान भंग करने जैसी बात है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमस्खलन की 90 प्रतिशत घटनाएं मानव जनित होती हैं और अक्सर वे मानव भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। हिमस्खलन 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक तेज गति से गिर सकता है। भारत में वैसे कम हिमस्खलन होते हैं। पश्चिम अमेरिकी पहाड़ों में हर साल लगभग एक लाख हिमस्खलन होते हैं। एक अनुमान है, हिमस्खलन से हर साल दुनिया में 150 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि मानव गतिविधियों की वजह से ही हिमस्खलन घटित होते हों। तूफान, तापमान, हवा, ढलान, भूभाग, वनस्पति और सामान्य हिमपात की स्थिति में भी हिमस्खलन की आशंका रहती है। हिमस्खलन की आशंका तब सबसे अधिक होती है, जब ताजा बर्फबारी के कारण बर्फ के ढेर से नई परत जम जाती है। चमोली में भी शायद ऐसा ही हुआ है। विगत दिनों से पहाड़ों में अनेक जगह बर्फबारी हुई है।

अभी भूस्खलन की भविष्यवाणी मुमकिन नहीं है। हिमस्खलन कब और कहां होगा, कोई नहीं जानता। बर्फ के ढेर, तापमान और हवा की स्थिति की जांच करके खतरे के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब, ग्लेशियर के इलाकों में जहां भी निर्माण चल रहा है, वहां यह अध्ययन निरंतर जरूरी है। बर्फ पर नियंत्रण के लिए क्षमता चाहिए। अक्सर बर्फ ही बर्फ से बचाव में सहायक होती है। ध्यान रहे, कनाडा और स्विट्जरलैंड के ऊंचे पहाड़ों में विशेष सैन्य टुकड़ियां तैनात होती हैं, जो हिमस्खलनों पर नियंत्रण करती हैं। कई स्विस पहाड़ी गांव बर्फ के ढेर को स्थिर करने के लिए बड़ी, मजबूत संरचनाएं बनाकर अपने घरों को हिमस्खलन से बचाते हैं। भारत में भी ऐसी सैन्य टुकड़ियों की संख्या और आधुनिक इंतजाम बढ़ाने की जरूरत है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 03 मार्च, 1950

सांसदों के विशेषाधिकार

भारतीय संसद के सदस्य अपने विशेषाधिकारों के लिए काफी जागरूक और चिन्तित हैं। यह श्री शिब्बनलाल सक्सेना के मामले को लेकर भारतीय संसद में जो गरमागरम वाद-विवाद हुआ, उससे भली प्रकार प्रकट हो जाता है। संसद-सदस्यों को यह शिकायत थी कि सरकार ने संसद के एक सदस्य को गिरफ्तार करके दिल्ली से निर्वासित किया और इस कार्रवाई की सूचना संसद के अध्यक्ष अथवा स्वयं संसद को नहीं दी गई। इस प्रकार संसद की तौहीन की गई। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री तथा उप-प्रधानमंत्री, दोनों ने इस सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण किया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि सरकार संसद के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संसद-सदस्यों जितनी ही उत्सुक है। जहां तक श्री शिब्बनलाल सक्सेना के मामले का सम्बन्ध है, दोनों ने स्वीकार किया कि वास्तव में सम्बन्धित अधिकारी से भूल हुई और ज्योंही इस भूल का पता चला, उसे दुरुस्त कर दिया गया। सरकार की भूल को स्वीकार करके और उसके लिए श्री सक्सेना के सामने खेद प्रकट करके प्रधानमंत्री और उप-प्रधानमंत्री ने सदस्यों की उभड़ी हुई भावनाओं को शान्त कर दिया। उसके बाद इस विवाद को जारी रखना निष्प्रयोजन होता और उसे खत्म करके उचित ही किया गया।

जहां तक श्री शिब्बनलाल सक्सेना के अनशन का ताल्लुक है, हमारी भी यह मान्यता है कि उन्होंने राजघाट को इसके लिए चुनकर उचित नहीं किया। राजघाट एक पवित्र स्थान है और उसकी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। छोटी-मोटी शिकायतों के पक्ष में प्रचार करने का उसे साधन नहीं बनाने दिया जा सकता। सरकार का मकसद भी यही था कि श्री सक्सेना को राजघाट से अन्यत्र हटा दिया जाये। जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें दिल्ली से बाहर भेजने की जो कार्रवाई की, वह उनके अधिकार-क्षेत्र से बाहर की वस्तु थी और अच्छा होता, यदि वह पहले अपने उच्च अधिकारियों से परामर्श कर लेते। वाद-विवाद के दौरान यह कहा गया कि उन्होंने ऐसा परामर्श किया था और उन्हें बताया गया कि श्री शिब्बनलाल सक्सेना को दिल्ली से बाहर हटाने में संसद-सदस्यों के विशेषाधिकार का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यदि वस्तु-स्थिति ऐसी है, तो ऐसा परामर्श देने वाले पर भी इस भूल की जिम्मेदारी जाती है। ऐसा मालूम होता है कि संसद-सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में अभी कुछ निश्चित नहीं है।

तेज आर्थिक तरक्की करता तीर्थाटन

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

देश में धार्मिक पर्यटन साल 2032 तक 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, पर बड़ी बात यह है कि 2030 तक इससे 14 करोड़ लोगों के लिए रोजगार भी पैदा होगा।

प्रयागराज के महाकुम्भ में 65 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने हिस्सा लिया। इस संख्या पर सवाल उठ सकता है, लेकिन इसमें विवाद की गुंजाइश नहीं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। आप इस गिनती को आधा या चौथाई भी कर दें, तब भी रहेगा, क्योंकि इस्लाम के सबसे बड़े आयोजन हज यात्रा में पिछले साल करीब 1.4 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए थे और ईसाइयत के केंद्र वेटिकन में होने वाली सामूहिक प्रार्थना में तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 15 हजार लोगों के ही शामिल होने की जगह है। साल भर में कुल मिलाकर वहां 50 लाख के आसपास लोग पहुंचते हैं। दूसरी तरफ, ईसाई और यहूदी धर्म ही नहीं, इस्लाम में भी पवित्र तीर्थ समझे जाने वाले येरूशलम में जरूर ईस्टर के मौके पर लाखों लोग इकट्ठा होते थे, पर अब वहां का माहौल इसकी इजाजत नहीं देता।

कुम्भ दरअसल समाज और आस्था का समागम है। ज्यादा से ज्यादा लोग वहां सिर्फ पवित्र संगम में डुबकी लगाने आते हैं। यहां साधुओं के अखाड़े लगते हैं और अखाड़ों के स्नान से कुम्भ का शुभारंभ होगा, यह तय है। मगर वहां लाखों-करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग भी आते हैं, जिनके लिए यह सिर्फ श्रद्धा या आस्था का पर्व नहीं, बल्कि उत्सव भी है। इन लोगों के भरोसे ही दूर-दूर से दुकानदार भी आकर यहां अपनी किस्मत आजमाते हैं। जैसे-जैसे कुम्भ का महत्व और आकार बढ़ता जा रहा है, इसके साथ जुड़ा व्यापार भी बढ़ रहा है। अब यह मेले-ठेले के अंदाज में न रहकर छोटी-बड़ी कंपनियों के लिए मार्केटिंग का एक बड़ा अवसर बन चुका है। वे यहां स्टॉल लगाते हैं, प्रचार करते हैं, साथ ही धार्मिक कार्य में योगदान देकर अपना कर्तव्य निभाने का काम भी कर लेते हैं।

एक आर्थिक अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार, महावीर सिंह 40 साल पहले अपने घर में पले ऊंट को लेकर पुष्कर मेले में गए। आठ साल के महावीर ने तब यात्रियों को सवारी करवाकर हर रोज एक हजार रुपये कमाए। उन्हें काम रास आ गया, और ऐसा-वैसा नहीं, इस बार प्रयागराज महाकुम्भ में उन्होंने चार करोड़ रुपये खर्च करके 350 टेंट लगाए। दूसरी तरफ, अपने परिवार और दोस्तों से 8,000 रुपये उधार लेकर चाय का स्टॉल लगाने वाला एक छात्र है, जिसने पहले तीन दिनों में ही अपनी लागत निकाल ली। महाकुम्भ में कितने तरह के कारोबार हुए, इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन इनवेस्टमेंट रिसर्च एजेंसी स्प्राउट ने नतीजा निकाला है कि महाकुम्भ में करीब दो से ढाई लाख करोड़ रुपये या 3,000 करोड़ डॉलर का लेन-देन होने का अनुमान है। उसका यह अनुमान इस आधार पर है कि महाकुम्भ पहुंचने वाले करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं में से 80 प्रतिशत भी अगर औसतन छह से आठ हजार रुपये खर्च करते हैं, तो कुल रकम यह बन जाएगी। 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान महाकुम्भ से पहले सरकार की तरफ से आया था। मगर अब यदि महाकुम्भ समाप्त होते वक्त सरकार का यह आंकड़ा बढ़कर लगभग डेढ़ गुना हो रहा है, तो जाहिर है कि कारोबार की रकम भी उसी अनुपात में बढ़ गई होगी।

इस किस्से में थोड़े झोल भी हो सकते हैं। खासकर भीड़ बढ़ने और उसके बाद की रोकथाम की वजह से बहुत से कारोबार परेशानी में भी आए होंगे। मगर महाकुम्भ के हिसाब में शायद बहुत कुछ प्रयागराज के बाहर भी जुड़ना है। खासकर फरवरी के मध्य से हवाई किराये जिस अंदाज में आसमान पर पहुंचे, रेलों में बेतहाशा बुकिंग हुई, उसने बहुत से लोगों को अपनी गाड़ी या टैक्सी लेकर आने की राह दिखा दी। भीड़ और ट्रैफिक जाम तो सामने दिखे, मगर इससे भी तमाम लोगों के लिए नए रोजगार का रास्ता खुला।

फिर, इस बार ऐसे लोगों की गिनती भी बहुत थी, जो सिर्फ महाकुम्भ में डुबकी लगाकर नहीं, बल्कि काशी और अयोध्या के भी दर्शन करके पूरा पुण्य साथ कमाना चाहते थे। अयोध्या में भीड़ बढ़ने का सिलसिला तो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही चल रहा है और उसे देखकर तमाम बड़े होटल वहां खुल चुके हैं या खुलने जा रहे हैं। वाराणसी में भी होटल, रहने-खाने की व्यवस्था और दूसरी सुविधाएं बढ़ी हैं। इसका असर इन शहरों के कारोबार पर भी दिख रहा है।

बात सिर्फ यहीं की नहीं है। देश के दूसरे हिस्सों में मौजूद हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्मस्थलों के अलावा बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थलों की एक पूरी शृंखला मौजूद है। इनके आस-पास भी सुविधाएं सुधर रही हैं और इन तक पहुंचने के रास्ते आसान हो रहे हैं। इसका सीधा असर इन जगहों के कारोबार पर होना तय है।

दरअसल, कोरोना के बाद से भारत में धर्मार्थ पर्यटन तेजी से बढ़ा है। उस वक्त दुनिया के दूसरे देशों में यात्रा पर तरह-तरह की पाबंदियां थीं, तो लोग देशाटन पर ही निकलने लगे। साथ में, पुण्य कमाने का मौका इन्हीं तीर्थों में मिलना था। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में ऐसे यात्रियों की संख्या 67.7 करोड़ थी, जो 2022 में बढ़कर करीब 144 करोड़ पर पहुंच गई। जाहिर है, इस गिनती में एक इंसान एक से ज्यादा बार भी गिना जा सकता है, अगर वह एक साल में एक से ज्यादा बार सफर करे। मंत्रालय का अनुमान था कि 2022 तक धार्मिक पर्यटन 16 अरब डॉलर या करीब 1.34 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हो चुका था।

जानकारों की मानें, तो भारत के घरेलू पर्यटन का 60 प्रतिशत हिस्सा तीर्थाटन ही होता है। इसके बढ़ने से न सिर्फ इस कारोबार में लगे लोगों को, बल्कि उस इलाके के और रास्ते में बसे लोगों को भी रोजगार मिलते हैं। ट्रैवेल एजेंसियों के पास तीर्थस्थलों तक पहुंचने और वहां रुकने के लिए जिस रफ्तार से इनक्वॉयरी आ रही हैं, उसे ही देखकर तमाम होटल कंपनियां अपनी विस्तार-योजनाएं बना रही हैं। अभी देश में धार्मिक पर्यटन 20 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार हो चुका है और साल 2032 तक इसके लगभग 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि 2030 तक वहां 14 करोड़ लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद दिख रही है।

साफ है, धर्मार्थ यात्राएं देश और देशवासियों के लिए अर्थलाभ का कारक भी बनती दिख रही हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दुर्लभ वन्य जीवों के संरक्षण का सफल हो रहा प्रयास

यहां स्कैन करें

प्रमोद भार्गव | वरिष्ठ पत्रकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी चीता परियोजना को दो साल पूरे हो गए हैं। नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रधानमंत्री ने छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाकर छोड़े गए थे। नई धरती और जलवायु परिवर्तन के चलते इन चीतों को शुरुआत में यहां के मौसम से तालमेल बिठाने में दिक्कतें आईं। नतीजतन, छह वयस्क और यहीं पैदा हुए चार शावकों में से तीन की मौत हो गई, जिससे इस परियोजना पर सवाल भी खड़े किए गए।

मगर अब जब दक्षिण अफ्रीका से लाकर बसाए गए 12 चीतों को 18 फरवरी को दो साल पूरे हो गए हैं, तब इस अवधि में इन चीतों की मृत्यु दर में आई कमी ने परियोजना की सफलता के प्रथम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इन चीतों के जीवित रहने की शुरुआती दर नामीबिया से लाए गए चीतों से बेहतर है। अफ्रीका से लाई गई तीन मादा चीता ने अब तक 12 शावकों को जन्म दिया है, जिनमें से छह पूर्ण स्वस्थ हैं। ये चीते अब भारतीय परिवेश में न केवल पूरी तरह से ढल गए हैं, बल्कि अपने नए घर कूनो में आबादी भी बढ़ा रहे हैं। कूनो में फिलहाल 12 चीते और 14 शावक मौज-मस्ती कर रहे हैं।

एक समय था, जब चीते की रफ्तार भारतीय वनों की शान हुआ करती थी, लेकिन 1947 के आते-आते इनकी आबादी पूरी तरह समाप्त हो गई। 1948 में अंतिम चीता छत्तीसगढ़ के सरगुजा में देखा गया था, जिसका शिकार कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि बीती सदी में चीतों की संख्या एक लाख तक थी, लेकिन अफ्रीका के खुले घास वाले जंगलों से लेकर भारत सहित लगभग सभी एशियाई देशों में पाए जाने वाले चीते अब पूरे एशियाई जंगलों में गिनती के रह गए हैं। राजा चीता (एसिनोनिक्स रेक्स) जिम्बाब्वे में मिलता है। अफ्रीका के जंगलों में भी गिने-चुने चीते रह गए हैं। तंजानिया के सेरेंगती राष्ट्रीय उद्यान और नामीबिया के जंगलों में गिने-चुने चीते हैं। प्रजनन के तमाम आधुनिक व वैज्ञानिक उपायों के बावजूद जंगल की इस फुर्तीली नस्ल की संख्या पर्याप्त बढ़ नहीं पा रही है, जो प्रकृति के समक्ष वैज्ञानिक दंभ की नाकामी है। 'जूलॉजिकल सोसायटी ऑफ लंदन' की रिपोर्ट की मानें, तो दुनिया भर में 91 प्रतिशत चीते 1991 में ही लुप्त हो गए थे। अब केवल 7,100 चीते पूरी दुनिया में बचे हैं। ऐसे में, भारत में चीतों की वंश-वृद्धि संसार के लिए खुशखबरी है। खबर यह भी है कि कूनो के बाद मध्य प्रदेश में ही मंदसौर जिले के गांधीसागर अभयारण्य में चीतों का नया कुनबा बसाने की तैयारी चल रही है। इन चीतों के आहार के लिए अभी इस वन-प्रांतर में 28 चीतल छोड़े गए हैं।

भारत में चीतों के अलावा बाघ और हाथियों का भी संरक्षण किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, साल 2024 में भारतीय बाघों की संख्या 3,682 से लेकर 3,925 तक होने का अनुमान था। भारत में यह अच्छी बात है कि बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 785 बाघ हैं। इसके बाद कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 बाघ हैं। भारत में कुल 54 बाघ संरक्षण अभयारण्य हैं। तीन नए अभयारण्य घोषित हुए हैं। इन सभी में बाघ संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं। भारत में हाथियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 2024 में इनकी अनुमानित संख्या 28,000 थी। हाथी परियोजनाओं में 2017 में की गई गिनती के मुताबिक, 27,312 हाथी पाए गए थे। इनकी सबसे ज्यादा आबादी कर्नाटक में है। इसके बाद असम और केरल का स्थान आता है।

भारत में चीतों के अलावा बाघ और हाथियों का भी संरक्षण किया जा रहा है, जिससे इनकी आबादी बढ़ रही है। विश्व वन्य-जीव दिवस पर विशेष :

हालांकि, जंगल में हाथी और बाघों का व्यवहार मानव बस्तियों से प्राकृतिक आवास स्थलों के घिरते जाने के कारण बदल भी रहा है। यह चिंताजनक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, आक्रामक हाथियों ने बीते चार साल में 2,243 और बाघों ने 300 लोगों के प्राण ले लिए हैं। ये तथ्य चौंकाने वाले जरूर हैं, लेकिन इसको झुठलाया नहीं जा सकता कि वन्य-जीवों और मानवों के बीच संघर्ष जारी है। लिहाजा, इनसे सुरक्षा के लिए अभयारण्य की सीमा पर मजबूत बागड़ या फिर दीवार खड़ी करने की जरूरत है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अहिल्या के सपने

सनातन संस्कृति में ऐसी कई कहानियां, जिन्हें आधुनिक समय में समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे *ब्रह्म पुराण* में पंचकन्याओं का जिक्र है; लिखा है, उनके नित्य स्मरण से पापों का नाश होता है। ये पांच कन्याएं हैं- अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी। इन सारी स्त्रियों के चरित्र को देखें, तो बहुत ही अलग हैं। इनमें कोई समानता नहीं है। इन सबमें अहिल्या की कहानी विलक्षण है। वह अपूर्व सुंदरी थीं, वृद्ध गौतम ऋषि से ब्याही गईं। एक दिन उन्हें अकेली पाकर इंद्र गौतम का रूप धरकर उनके पास आए और उनसे प्रेम किया। यह जानकर गौतम ने अहिल्या को श्राप दिया कि वह पत्थर बनकर जंगल में तब तक पड़ी रहेंगी, जब तक प्रभु राम आकर उन्हें मुक्त नहीं करते।

सदियां गुजर गईं, पुरुष प्रधान संस्कृति में अहिल्या के मनोभाव के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मगर 20वीं सदी में दो महापुरुषों ने अहिल्या का मर्म खोला है- एक रवींद्रनाथ टैगोर ने और दूसरे ओशो ने। रवींद्रनाथ टैगोर ने अहिल्या के लिए लंबी कविता लिखी है। उसका एक अंश है, *तुम्हारे क्या सपने थे अहिल्या, जब तुमने पत्थर बनकर लंबे साल गुजारे, धरती में जड़ें जमाए। धरती तुम्हारे शरीर में विलीन हो गई; क्या तुमने उसके विशाल प्रेम को जाना? क्या धुंधली जागरूकता ने तुम्हारे पत्थर को सताया?*

ओशो ने तो इस कहानी को एक अलग ही आयाम दिया। उन्होंने कहा, अहिल्या सचमुच हुई हो, न हुई हो, लेकिन अहिल्या हो सकती है। पत्थर की तरह पड़ी हुई कोई स्त्री- मैं नहीं कहता कि पत्थर ही हो गई होगी, लेकिन कोई स्त्री, जो राम के स्पर्श मात्र से खिल पाएगी, जब तक राम न मिलें, तब तक पत्थर ही रहती है। किसी और का स्पर्श उसे जड़ ही छोड़ जाएगा। कहानी का मर्म इतना ही है कि हरेक की अपनी प्रतीक्षा है, और एक खास क्षण आए बिना वह पूरी नहीं होती। स्त्री और पुरुष के शरीर में फर्क है। स्त्री का पूरा शरीर तंतु वाद्य की भांति होता है। जब तक किसी स्त्री को उसके अनुकूल प्रेमी न मिल जाए, जब तक प्रेम का स्पर्श उसके तार-तार को झंकृत न करे, तब तक उसके भीतर कुछ पत्थर की तरह ही पड़ा रह जाता है। स्त्री और पुरुष का संबंध गहरे में एक विद्युत शक्ति का चुंबकीय क्षेत्र है। संबंध जितना गहरा हो, उतना विशिष्ट हो जाता है। यह कोई पति-पत्नी का संबंध नहीं होता, यह धन और ऋण विद्युत का संबंध होता है। और उसके लिए स्त्री कितनी भी प्रतीक्षा कर सकती है।

न जाने कितनी अहिल्याएं युगों-युगों से अपने राम की प्रतीक्षा कर रही होंगी। उन्हें पता भी नहीं होगा अपनी क्षमता का। उन पर बंधन इतने हैं कि इस तरह के सपने देखना भी उनको पाप जैसा लगेगा।

ऐसे न जाने कितनी अहिल्याएं युगों-युगों से अपने राम की प्रतीक्षा कर रही होंगी। उन्हें पता भी नहीं होगा अपनी क्षमता का, अपने सपनों का। उन पर नैतिक और सामाजिक बंधन इतने हैं कि इस तरह के सपने देखना भी उनको पाप जैसा लगेगा।

अमृत साधना

एम के स्टालिन | मुख्यमंत्री, तमिलनाडु

परिसीमन पूरे दक्षिण भारत को प्रभावित करने वाला है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उन राज्यों को दंडित नहीं करना चाहिए, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया और राष्ट्र प्रगति में अहम योगदान दिया।

राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण की बड़ी वजह

यह है हमारे राजनीतिक पार्टियों का मूल चरित्र। ये खुद गुंडे, बदमाशों (सभ्य भाषा में दागी लोगों) का संरक्षण चाहते हैं और जनता के सामने खुद शरीफ बनने का नाटक करते हैं। देश में नेताओं की पूरी लांबी नहीं चाहती कि साफ-सुथरी छवि वाले और ठीक-ठाक लोग राजनीति की दुनिया में पैर रखें। अगर दोषी राजनेताओं के लिए विधायिका के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं या ऐसा कोई कानून बन जाए, तो इनका बाजार ही बंद हो जाएगा। यह है भारत का कानून। अपराध के आरोपी नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपराधिक रिकॉर्ड हो गया, लेकिन संगीन अपराध के आरोपी नेता जरूर बन सकते हैं, क्योंकि विधायकी-सांसदी सब कुछ साफ-सुथरा कर देती है। सजायाफ्ता लोगों को आजीवन सरकारी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन सजायाफ्ता को कानून बनाने का अधिकार छह साल के बाद जरूर मिल जाना चाहिए। इसे ही राजनीति कहते हैं।

140 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में। कुछ लाख या हजार लोगों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टे, जो नए नेता राजनीति में आएंगे, वे भ्रष्टाचार करने से डरेंगे। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए था। कम से कम एक क्षेत्र को तो भ्रष्टाचार-मुक्त करने का प्रयास करना ही पड़ेगा। राजनीति में अपराधीकरण बढ़ने की वजह यही है, जब जन-प्रतिनिधि बनकर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग आ जाएंगे, तो देश में न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है?

भ्रष्टाचार के जन्मदाता तो स्वयं राजनेता ही हैं। लगता यही है कि सभी नेता एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। कोई भी पार्टी हो, वह ऐसे नेताओं पर नकेल चाहती ही नहीं। साफ है, इस भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था में शायद ही कोई बदलाव होने वाला है। ऐसे ही चलता रहेगा। राजनेता हमेशा अपनी जमात के लोगों की ही भलाई सोचेंगे, फिर चाहे वे किसी भी पार्टी या जाति के हों। गौर कीजिए, जिस प्रतिनिधि सभा में 46 फीसदी ऐसे सदस्य हों, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड हो, उससे बहुत उम्मीद रखने का तुक नहीं है। जागरूक जनता ही भविष्य के लिए कोई विकल्प तैयार करेगी। चूंकि आज के समय में हम्माम में सब नंगे हैं, इसलिए नेताओं का यह प्रिय शगल बन गया है कि वे कानून रूपी खिलौने को जब चाहें, बनाएं और जब चाहें, बिगाड़ें? तब तक देश की जनता इन काले अंग्रेजों की गुलामी करती रहेगी? देश का नहीं, बल्कि स्वयं का सुख भोगते रहते हैं राजनेता। तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों को सत्ता-सदन में नहीं रखना चाहिए, जो दागदार छवि के साथ लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचते हैं।

सुजीत चौहान, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

दागी नेता

आजीवन प्रतिबंध जैसी कठोर सजा निरर्थक

दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध संबंधी याचिका का परोक्ष रूप से विरोध करके सरकार ने उचित किया है। दुनिया के कई देशों में दागी नेताओं के लिए अलग-अलग नियम हैं। वहां तक कि उन देशों में भी, जिनके लोकतंत्र की मिसाल दी जाती है, दोषी नेताओं को आजीवन प्रतिबंधित नहीं किया जाता। ऐसे में, भारत में यह मांग करना गले नहीं उतरता। अपने देश में तो लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जैसा मजबूत कानून है, जो चुनाव प्रक्रिया और जन-प्रतिनिधियों की योग्यता एवं अयोग्यता को तय करता है। इसी अधिनियम की धारा 102 में यह लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे कम से कम दो साल की सजा मिलती है, तो वह दोषसिद्धि की तारीख से छह साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य रहता है। इतना ही नहीं, अगर सजा दो साल से कम है, तो अयोग्यता केवल सजा की अवधि तक ही लागू होगी। मेरा मानना है कि इस अधिनियम में अभी छेड़छाड़ करने का कोई मतलब नहीं है। छह साल का समय काफी होता है, खासकर यह देखते हुए कि कितनी तेजी से राजनीतिक तस्वीर बदलने लगी है।

यहां हमें कुछ देशों के उदाहरण से भी सबक लेना चाहिए। मसलन, अमेरिका में भी दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंधित नहीं किया जाता। ब्रिटेन में तो किसी सांसद को यदि किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और एक साल से अधिक की सजा मिलती है, तो वह स्वतः संसद से अयोग्य जरूर हो जाता है, पर वह अयोग्यता सजा की अवधि तक ही रहती है, न कि पूरी जिंदगी। ऑस्ट्रेलिया में भी संविधान यही कहता है कि यदि किसी को एक साल से अधिक सजा मिली है, तो वह संसद से तभी तक अयोग्य रहेगा, जब तक की सजा होगी। सजा पूरी होते ही प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। बावजूद इसके अपने देश में दोषी नेताओं के लिए आजीवन प्रतिबंध की मांग क्यों की जाती रहती है, यह समझ से परे है। जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र (अमेरिका) में दागी नेताओं को आजीवन प्रतिबंधित नहीं किया जाता, तो सबसे बड़े लोकतंत्र (भारत) में इस तरह की मांग करने का भला क्या औचित्य है?

इसके बजाय हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि राजनीति के क्षेत्र में दागी व्यक्ति का कम से कम प्रवेश हो। अपने यहां तो व्यक्तिगत खुन्नस में भी मुकदमे लाद दिए जाते हैं। राजनीतिक शत्रुता भी एक वजह होती है, इसलिए राजनेताओं को कुछ हद तक छूट अवश्य मिलनी चाहिए। हां, ऐसी व्यवस्था भी होनी ही चाहिए कि गंभीर अपराध करने वाले लोग सरकार का हिस्सा न बन सकें। इस पर संसद को अवश्य विचार करना चाहिए।

अम्रतेश, टिप्पणीकार